www.indiatodayhindi.in

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सः खत्म हो गई रार | कोविडः क्या तीसरी लहर आएगी? | यूपी भाजपाः आगे रहने को पिछड़ा दांव

25 अगस्त, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

देश का मिज़ाज सर्वेक्षण

अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चिंता

नौकरियों की किल्लत और बढ़ती महंगाई चिंता की बड़ी वजह. यह सर्वेक्षण मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था फौरन सुधारने का संदेश देता है

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 52 (आवरण सहित)

VISIT…

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

सरकार और देश के लिए पिछले छह महीने किसी दुस्वप्न की तरह गुजरे हैं. इस साल मार्च-अप्रैल में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने देश में तांडव मचा दिया. दूसरी लहर ने दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बहाली की संभावनाओं पर दोहरा थपेड़ा जड़ दिया. भारत में भी वही हुआ. संक्रमण और मौत का सिलसिला ऐसे छलांग भरने लगा कि केंद्र के साथ राज्यों की कुव्वत भी जवाब दे गई. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच कोविड से हुई 3,29,065 मौतों में आधी तो इसी अप्रैल-मई में हुईं. महामारी के पहले ही रेंगती अर्थव्यवस्था महामारी के पूरे वर्ष 2020-21 में शून्य से नीचे गोता लगा गई, जो चार दशकों में पहली बार हुआ. संक्रमण की एक के बाद एक लहरों के कारण बचत घट गई, आमदनियां टूट गईं और रोजगार के अवसर घट गए. लॉकडाउन की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण गतिविधियां ठप पड़ गईं. सीएमआइई का मानना है कि दूसरी लहर में तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने रोजगार-नौकरियां गंवा दीं और 97 फीसद परिवारों की आमदनी का नुक्सान हुआ.

दूसरी लहर के बाद पहले इंडिया टुडे देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण में महामारी के बाद दुश्वारियों का साफ संकेत मिलता है. इसके साथ महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और मंदी यानी कुल अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण में 49 फीसद लोगों के लिए देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. अलबत्ता कोविड को 23 फीसद लोग देश की सबसे विकराल समस्या मानते हैं. अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार बताने वाले लोगों की संख्या जनवरी 2021 में 49 फीसद से इस बार लुढ़क कर 28 फीसद पर पहुंच गई है. 59 फीसद लोगों का कहना है कि देश में बेरोजगारी के हालात बदतर हैं. 60 फीसद का मानना है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं कर रही. 21 फीसद को लगता है कि अर्थव्यवस्था अगले छह महीने में सुधरेगी, लेकिन उनकी संख्या भी जनवरी के 41 फीसद से गिर गई है. हालांकि मोदी सरकार ने आम लोगों के लिए कल्याण योजनाओं के मद में राहत पहुंचाई है, मगर 46 फीसद का सोचना है कि उसकी आर्थिक नीतियां सिर्फ बड़े कारोबारियों को ही पहले लाभ पहुंचा रही हैं. प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को काफी समर्थन हासिल है, पर इसे अच्छा कहने वालों की तादाद भी जनवरी के 46 फीसद से घटकर अब 38 फीसद पर आ गई है. अर्थव्यवस्था की खस्ताहाली का साया पांच साल में पहली दफा मोदी सरकार की रेटिंग पर पसरता जा रहा है. 2016 से देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने सरकार के अर्थव्यवस्था की सार-संभाल के तौर-तरीकों पर ऐसे सवाल नहीं खड़े किए थे. अगस्त 2019 में 71 फीसद ने सरकार के आर्थिक कामकाज को 'बेहतरीन' या 'अच्छा' बताया था, लेकिन अब महज 47 फीसद ही ऐसा मानते हैं. 20 फीसद लोगों ने अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार के तौर-तरीकों को 'खराब/बेहद खराब' कहा. ऐसी नकारात्मक रेटिंग देने वालों की संख्या जनवरी 2019 के बाद से सबसे ज्यादा है.

5 फरवरी, 2021 का आवरण

देश जब ऐसी अप्रत्याशित मुसीबतें झेल रहा है तो आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को सकारात्मक रेटिंग देने वालों की संख्या जनवरी में 74 फीसद से फिसलकर छह महीने में 54 फीसद पर आ गई है. यह देश का मिज़ाज के दो सर्वेक्षणों में सबसे तीखी गिरावट है. हालांकि यह किसी लोकतांत्रिक देश के नेता के लिए अब भी ऊंची रैंकिंग है, खासकर सात साल शासन करने के बाद तो और भी अच्छी है. लोकप्रियता में गिरावट के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भी देश के अब तक के बेहतरीन प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी से आगे. मोदी अपनी पार्टी की ताबीज जैसे हैं इसलिए उनकी लोकप्रियता में बदलाव का फर्क भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर भी पड़ा है. हमारे सर्वेक्षण का अनुमान है कि अगर आज चुनाव हुए तो पार्टी को लोकसभा में सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें नहीं मिलेंगी. अलबत्ता, एनडीए अब भी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा. कांग्रेस की सीटें मामूली बढ़कर 2019 के आम चुनावों में 52 सीटों से 59 पर पहुंच जाएंगी. 17 फीसद लोग अभी भी राहुल गांधी को ही पार्टी में जान डालने के लिए सबसे योग्य मानते हैं, लेकिन यह अगस्त 2018 के 47 फीसद से करीब 30 फीसद अंक की गिरावट है.

ज्यादातर फायदा क्षेत्रीय पार्टियों के पाले में जाएगा. फिर भी विपक्ष बिखरा हुआ है. 49 फीसद लोग मानते हैं कि विपक्षी गठजोड़ केंद्र में मोदी की अगुआई वाली भाजपा को चुनौती दे सकता है, पर 50 फीसद को लगता है कि विपक्ष की सरकार की आलोचना में कोई दम नहीं है. उसे संसद में हंगामा करने के बजाए लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों पर फोकस करना चाहिए. बहुत कुछ ऐसा है, जिस पर बहस की जा सकती है और सरकार को उसकी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की सिरदर्दी कम है. 78 फीसद को लगता है कि सरकार ने चीनी घुसपैठ की समस्या का अच्छे या संतोषजनक ढंग से हल निकाला. जनवरी में 59 फीसद ही मानते थे कि सरकार ने चीन को अच्छा जवाब दिया. 45 फीसद को पाकिस्तान के मामले में सरकार का यह रवैया सही लगता है कि पहले वह आतंकवाद पर कार्रवाई करे, तभी बातचीत होगी.

हमारी आवरण कथा 'अर्थव्यवस्था बड़ी दुखती रग' सरकार की आने वाले महीनों में सर्वोच्च प्राथमिकताओं पर विचार करती है. हमारे सर्वेक्षण में भी यह संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास सुधारों को आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की राजनैतिक पूंजी है. इसका अधिक श्रेय मोदी सरकार को ही है. सात साल के कार्यकाल में उसने कमजोर तबकों के लिए शौचालय, गांवों में बिजली, रसोई गैस, और ग्रामीण सड़कों पर निवेश किया है. उसका अगला सराहनीय मिशन 'हर घर जल' है, जिसका मकसद देश के 19 करोड़ घरों में साफ नल जल पहुंचाना है, जिसमें अभी 17 फीसद के पास ही पानी का कनेक्शन है. यह अभियान गेमचेंजर हो सकता है क्योंकि इससे उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. हाल में प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के बेहद जरूरी लक्ष्य की घोषणा की, जिसका भारत दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है. महामारी के प्रकोप के पहले उनकी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च, कृषि सुधार और निजीकरण के जरिए सरकारी संपत्तियों के मौद्रीकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की भारी योजना बनाकर सही दिशा में कदम उठा रही थी. सरकार ने दिखाया है कि वह कल्याणकारी काम कर सकती है, अब उसे संपत्ति निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की दरकार है, जिससे जरूरतमंदों की और ज्यादा मदद की जा सके. देश को अब अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाने के लिए मजबूत हाथ की दरकार है, ताकि टिकाऊ वृद्धि को गति दी जा सके. मोदी सरकार को मतदाताओं का सामना 2024 में करना है. यानी अभी तीन साल बाकी हैं. लोग अभी भी मोदी को ऐसा नेता मानते हैं, जो काम कर सकता है. यकीनन, यही वाजिब वजहें हैं कि वे रफ्तार तेज करें.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

Only books magazine

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अभिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशर: विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेड: सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 39; 19-25 अगस्त 2021;; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादक: राज चेंगप्पा

सुर्खियां

कोविड-19: क्या तीसरी लहर आ रही है?
पेज 5

भीतर

फुरसत

सिनेमा: महामहिम के खानदान से
पेज 48

अर्थात्: आएगा आने वाला
पेज 13

सवाल-जवाब/विश्वमोहन भट्ट: मोहन वीणा और कोविड पर
पेज 50

देश का मिज़ाज सर्वेक्षण 18

आवरण कथा

अर्थव्यवस्था की गंभीर आशंकाएं

रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी हैं लेकिन लोग अब भी देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मोदी पर भरोसा जता रहे हैं

28 अर्थव्यवस्था
32 विपक्ष
36 सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री
38 कोविड
41 सामाजिक-राजनैतिक मुद्दे
44 विदेश मामले
46 मनोरंजन

इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

भाजपा

14 ओबीसी पर दांव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने इस वोट बैंक को लुभाने के लिए उठाए कदम

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

Only books magazine

समाचार सारः
दिग्गी राजा का दमखम
पेज 8

नजरियाः पवित्र इतिहास से छेड़छाड़ के पीछे आखिर मंशा क्या है!
पेज 9

सुर्खियां

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सः
निगलनी ही पड़ी कड़वी गोली
पेज 10

राजस्थानः कांग्रेस में जारी खींचतान
पेज 12

पीटीआई

वायरस की निगरानी
5 अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होती कोविड टेस्टिंग

कोविड-19

Only books magazine

क्या तीसरी लहर आ रही है?

सोनाली आचार्जी

अगस्त के पहले हफ्ते में, भारत में लगातार आठ दिनों तक कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कोरोना वायरस के कुल 2,55,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए जो इसके पिछले हफ्ते के मुकाबले 8 फीसद की उछाल थी. 9 अगस्त को 24 घंटों के भीतर महज 27,421 नए मामले सामने आए, जो मार्च के बाद सबसे कम थे. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, कोविड की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी महज तीव्रता में कमी आई है. अगर एहतियातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा तो एक दिन में सामने आ रहे मामलों में गिरावट का आंकड़ा सिर के बल खड़ा हो सकता है. मिसाल के तौर पर, 8 मार्च को, जब 18,000 रोज से केस घटकर 15,000 रोजाना पर आ गए, तो उसके बाद ठीक एक हफ्ते में ही यह संख्या 40,000 रोजाना पर पहुंच गई और दूसरी लहर की शुरुआत हो गई थी.

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) के अध्यक्ष प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, ''जब तक आबादी का बड़ा

हिस्सा टीकाकृत न हो जाए, हमें सावधान रहने की जरूरत है. हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमने सामुदायिक प्रतिरोध हासिल कर लिया है, अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां वायरस का प्रसार नहीं हो पाया है. तीसरी लहर की तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमने कोविड अनुरूप बर्ताव को कितना अपनाया है.'' जुलाई में रिलीज आइसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) का चौथा सीरो सर्वे बताता है कि करीब 68 फीसद भारतीयों में कोविड के खिलाफ ऐंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं. वहीं, इस सर्वे में पाया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में सीरो पॉजिटिविटी अधिक पाई गई, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में यह दर कम थी. अधिक सीरोपॉजिटिविटी दर बताती है कि आबादी के बड़े हिस्से में कोविड के खिलाफ ऐंटीबॉडी मौजूद है.

इस सर्वे के परिणामों से कइयों को सुरक्षा के भाव का एहसास हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अभी सावधानी कम करने का वक्त नहीं है. सेंटर फॉर सेल्युलर ऐंड मोलिक्युलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के पूर्व निदेशक डॉ. राकेश मिश्र कहते हैं, ''अंतरराज्यीय सफर जारी है. अधिक सीरोपॉजिटिविटी वाले राज्यों के लोग अगर कम सीरोपॉजिटिविटी वाले राज्य में जाएंगे तो उन पर संक्रमण का खतरा रहेगा. भारत जैसे बड़े देश में यह राज्यस्तरीय सीरोपॉजिटिविटी है—कोई राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है—जिससे हर्ड इम्युनिटी तैयार होती है.'' सीसीएमबी, इंडियन सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसॉर्शियम या आइएनएसएसीओजी का हिस्सा है.

तीसरी लहर राष्ट्रीय होगी या स्थानीय?

हालांकि, राष्ट्रीय स्तर का कुल आंकड़ा ही यह तय करेगा कि तीसरी लहर आई है या नहीं. विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक आंकड़े उन राज्यों से आएंगे जहां वायरस के डेल्टा स्ट्रेन का अभी तक प्रसार कम हुआ है. अध्ययन बताते हैं कि डेल्टा वैरिएंट भारत में पहले संक्रमण फैला रहे अल्फा स्ट्रेन से 40 से 60 फीसद अधिक संक्रामक हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के वक्त में संक्रमण के मामलों में आई बढ़ोतरी उन राज्यों से हैं जो मई की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के आंकड़ों के खतरनाक अंदाज में उच्च स्तर तक पहुंचने वाले राज्यों की सूची में नहीं हैं. मौजूदा वक्त में, केरल में सक्रिय मामलों की संख्या सर्वाधिक है, जो कुल राष्ट्रीय स्तर पर रोज आ रहे संक्रमणों का करीब आधा हैं. यहां पर आइसीएमआर के सर्वे में सीरोपॉजिटिविटी सबसे कम (44 फीसद) वाले राज्यों में था.

मिजोरम में 25 जुलाई को 938 नए मामलों के साथ अब तक का एक दिन का सबसे अधिक संक्रमण का आंकड़ा दर्ज किया गया है. इससे पहले, राज्य में नए केसों में मामूली वृद्धि देखी जा रही थी. मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं. इस वजह से कुछ विशेषज्ञों को यह लगता है कि तीसरी लहर उन क्षेत्रों में असर करेगी जहां डेल्टा वैरिएंट प्रभावी रूप से फैल नहीं पाया था. डॉ. मिश्र कहते हैं, ''चूंकि, अब जगहें अनलॉक होती जा रही हैं और गतिविधियों पर लगी बंदिशें हट रही हैं, इसलिए अगर कोविड अनुरूप बर्ताव नहीं किया गया तो डेल्टा स्ट्रेन का फैलाव होगा.''

Only books magazine

विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर में अधिक केस उन राज्यों से आएंगे जहां वायरस के डेल्टा स्ट्रेन का प्रसार अभी तक कम हुआ है

खतरे के संकेत क्या हैं?

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे तो एक एकल संख्या बिंदु ही कोविड के वक्र में चढ़ाव को दिखा सकता है—आर (रिप्रोडक्टिव) नंबर. 4 अगस्त का केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि भारत का आर नंबर 1 से ऊपर है और ऐसा 7 मई को दूसरी लहर के पीक पर आने की शुरूआत के बाद पहली बार हुआ है. आर-नंबर के 1 से अधिक होने का मतलब है कि किसी संक्रमित व्यक्ति से एक से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं. मिसाल के लिए, 100 संक्रमित लोग अब सौ अन्य लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं. प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट टी. जैकब जॉन कहते हैं, ''संक्रमण में उतार का वक्र दिखाने या वायरस का प्रसार नहीं रहा, यह दिखाने के लिए आर-नंबर 1 से नीचे होना चाहिए.'' हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर आर नंबर 1.4 है. लक्षदीव में यह 1.3, तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में 1.2, और केरल तथा नगालैंड में 1.1, मेघालय, हरियाणा, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में आर-वैल्यू 1 से अधिक है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 18 जिलों में संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है और महाराष्ट्र, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अलावा उनमें से ज्यादातर केरल (10 जिले) के जिले हैं. इसके साथ ही 44 जिलों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 10 फीसद से ऊपर है. टेस्ट पॉजिटिविटी दर का अर्थ है कि जांच किए गए लोगों में संक्रमितों की संख्या. अन्य 53 जिलों में पॉजिटिविटी दर 5 से 10 फीसद है. एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), दिल्ली के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ''उच्च पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में हमें फौरन कंटेनमेंट उपाय करने चाहिए. वायरस का प्रसार अभी रोका जाना जरूरी है.'' विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) किसी भी महामारी के नियंत्रण में रहने के लिए टेस्ट पॉजिटिविटी दर 5 फीसद से कम होने की सिफारिश करता है. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर की वायरोलॉजिस्ट डॉ. गगनदीप कंग कहती हैं, ''5 फीसद से अधिक पॉजिटिविटी दर वायरस के बढ़ते संचरण का संकेत देती है. लिहाजा यही कार्रवाई का वक्त है.''

केरल में हालात कितने बुरे हैं?

पिछले सात हफ्तों से केरल में पॉजिटिविटी दर 10 फीसद से ज्यादा रही है. कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में इंटर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्र कहते हैं, ''हम उस अंदेशे से तैयारी कर रहे हैं कि अस्पताल में दाखिल होने वालों की संख्या जल्द बढ़ सकती है. यहां तक कि आज के मामलों में हल्की सी वृद्धि एक हफ्ते के बाद बड़ी संख्या में बदल सकती है क्योंकि कोविड में धारण क्षमता लंबी होती है.'' 20 अप्रैल को केरल में एक दिन में 19,000 नए मामले दर्ज किए गए थे. दो हफ्ते के बाद यह रोजाना 41,000 मामले में बदल गए थे.

केरल सरकार के पिछले महीने ईद के लिए कोविड प्रतिबंधों में ढील देने के नतीजे आने वाले दिनों में अधिक मामलों के रूप में सामने आए. 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी समूह के दबाव में तीन दिन की छूट की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की और इसे ''चिंताजनक स्थिति'' कहा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता है कि ओणम के बाद मामले और बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य के लिए केरल के नोडल अधिकारी डॉ. अमर फेटले कहते हैं, ''हमारी प्रभावी कंटेनमेंट रणनीतियों के कारण आबादी का बड़ा हिस्सा

अशुभ संकेत

44
जिलों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 10% से अधिक

53
जिलों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 5-10% से अधिक

चिंता वाले राज्य
केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर

सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर वाले राज्य
- केरल **12.8%**
- सिक्किम **11.6%**
- मणिपुर **11.1%**
- मिजोरम **9.9%**
- मेघालय **9.7%**

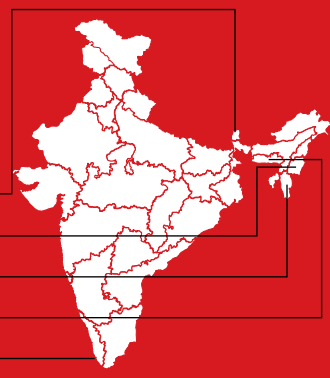

आर नंबर
(27-31 जुलाई)
- भारत (अनुमानित) **1.03**
- हिमाचल प्रदेश **1.4**
- जम्मू-कश्मीर **1.4**
- लक्षद्वीप **1.3**
- तमिलनाडु **1.2**
- मिजोरम **1.2**
- कर्नाटक **1.2**

सीरो पॉजिटिविटी दर*
राष्ट्रीय औसत **67.6%**

सबसे ज्यादा
- मध्य प्रदेश **75.9%**
- राजस्थान **76.2%**
- बिहार **75.9%**

सबसे कम
- केरल **44%**
- असम **50.3%**
- महाराष्ट्र **58%**

टीकाकरण कार्यक्रम
राष्ट्रीय (दो डोज) योग्य आबादी का **8.6%**

शीर्ष पांच राज्य
(दोनों डोज)
- महाराष्ट्र **12** करोड़
- पश्चिम बंगाल **91.3** लाख
- गुजरात **90.5** लाख
- उत्तर प्रदेश **85.2** लाख
- राजस्थान **83.8** लाख

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; कोविड19इंडिया.ओआरजी

* आइसीएमआर जुलाई 2021 रिपोर्ट; अन्य सभी आंकड़े 10 अगस्त के

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

कोविड से अप्रभावित है. हमें मास्क कवरेज और सामाजिक दूरी पर जोर देने के अलावा टेस्टिंग और ट्रेसिंग जारी रखनी होगी.''

राज्य सरकार ने आइएएस अफसरों को कासरगोड़, कोझिकोड, मल्लापुरम, पलक्कड़ और त्रिशूर में विशेष अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया जहां टेस्ट पॉजिटिविटी दर काफी ऊंची है. डॉ. चंद्रा कहते हैं, ''केरल का कंटेनमेंट मॉडल इतना ज्यादा प्रभावी था कि हमारी आबादी में वायरस को लेकर वही प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो सकी. संक्रमण में एकाएक उभार की बजाए लोगों में हम धीरे-धीरे संक्रमण देख रहे हैं. इसलिए अस्पतालों पर भीड़ का प्रबंधन किया जा सकता है.''

क्या तीसरी लहर डेल्टा से आएगी?

अध्ययन बताते हैं कि डेल्टा वैरिएंट वैक्सीन या पहले के संक्रमण से हासिल इम्युनिटी को भी तोड़ सकता है. नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स ऐंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आइजीआइबी) के एक शोध के मुताबिक, 10 फीसद से अभी अधिक ऐसे लोग, जो राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी लहर के समय कोविडग्रस्त हुए थे, उन्हें फिर से संक्रमण हो सकता है.

आइसीएमआर का अध्ययन बताता है कि टीकाकृत लोगों में हुए संक्रमण में से 80 फीसद लोगों में डेल्टा वैरिएंट की वजह से संक्रमण हुआ. डॉ. मिश्र कहते हैं, ''ऐसा नहीं लगता है कि डेल्टा वैरिएंट उन जगहों पर भी एक अन्य लहर का कारण बनेगा, जहां यह प्रभावी रह चुका है, पर अगर नया स्ट्रेन आता है, तो पहले से संक्रमित हो चुकी आबादी में भी प्रसार हो सकता है.''

हैदराबाद और कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक नई, लेकिन छोटी लहर का अनुमान लगाया है जिसका चरम अक्तूबर में आएगा. इसी टीम ने दूसरी लहर के पीक की सटीक भविष्यवाणी भी की थी. तीसरी लहर में अच्छी स्थिति में रोजाना के संक्रमण के केस 1,00,000 होंगे जबकि बदतर हालत में रोज 1,50,000 तक हो सकते हैं. टीम का कहना है कि स्थितियां बहुत कुछ नए वैरिएंट के उभरने, टीकाकरण की रफ्तार और कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर निर्भर करेंगी. पहली स्थिति में इस पूर्वानुमान की बदतर स्थिति आ सकती है जबकि बाकी दो स्थितियों में प्रसार को ठोस तरीके से रोका जा सकेगा और अस्पताल में भर्ती होने, मृत्यु दर और कोविड-बाद की जटिलताओं पर रोक लगेगी.

टीके कितने असरदार होंगे?

जुलाई में देशभर में आइसीएमआर ने 677 नमूनों का अध्ययन किया, और उससे पता चलता है कि टीकाकृत लोगों में संक्रमण की स्थिति में महज 0.8 फीसद लोग मरे और 9.8 फीसद लोगों को ही अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी. एक अन्य अध्ययन, जिसे जून में अपोलो अस्पताल ने 31,621 स्वास्थ्यकर्मियों के बीच कराया था, उसमें पता चला कि टीकाकरण ने 95 फीसद उत्तरदाताओं की रक्षा की थी. अपोलो अस्पताल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अनुपम सिब्बल कहते हैं, ''कई लोग यह सोचते हैं कि चूंकि टीका संक्रमण नहीं रोक सकता इसलिए यह जरूरी नहीं है. लेकिन टीका बिला शक अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति को कम करता है और बीमारी की गंभीरता और मृत्यु दर रोककर रखता है.''

कई ऐसे राज्य हैं जहां मामले बढ़ते जा रहे हैं और वहां की आबादी में काफी संख्या टीकाकृत है. मिजोरम में 45 वर्ष और अधिक उम्र के 76 फीसद लोगों को टीका लग चुका है. नगालैंड में वयस्क आबादी में 37 फीसद और केरल में 21 फीसद आबादी का टीकाकरण हो चुका है. उम्मीद की जा रही है कि तीसरी लहर में कम संक्रमण और मौतें होंगी. लेकिन डॉ. चंद्रा कहते हैं, ''महामारी को अब लहरों में मत बांटिए, इस संख्या को स्थायी तौर पर नीचे रखना होगा. नए वैरिएंट को उभरने से रोकना होगा और कोविड-बाद जटिलताओं को कम करना होगा.'' ■

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

Only books magazine

समाचार सार

दिग्गी राजा का दमखम

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री **दिग्विजय सिंह** को तीन महीने पहले कोविड संक्रमण हुआ था लेकिन आप उनकी हालिया गतिविधियों से ऐसा समझ नहीं पाएंगे. 74 साल के इस बुजुर्ग नेता ने पुलिस बैरिकेड्स को उछलकर पार किया और संसद के सामने विपक्ष के प्रदर्शन में अपनी गिरफ्तारी दी. इससे पहले, वे पुलिसवालों से उलझते दिखाई दिए थे और भोपाल में एक सियासी प्रदर्शन के दौरान वॉटर कैनन का सामना करते भी दिखे. कुछेक साल पहले, कांग्रेस के इस दिग्गज ने पैदल 3,000 किमी की नर्मदा परिक्रमा भी की थी. तो उनकी सेहत का राज क्या है? वे कभी राष्ट्रीय स्तर के स्क्वैश खिलाड़ी रहे थे और रोजाना 30 मिनट तक योग करते हैं. जाहिर है, राजनीति के दांव-पेचों से निबटने के लिए वे फिट हैं.

एक और ठाकरे के लिए भूमिका

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निकट सहयोगी **मिलिंद नारवेकर** ने हाल ही में, शिवसेना के मुखपत्र *सामना* में फ्रंटपेज पर एक विज्ञापन दिया था. इसमें मुख्यमंत्री के छोटे बेटे तेजस ठाकरे का गुणगान किया गया था और उनकी तुलना वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से की गई थी. बाद में, नारवेकर ने बड़े बेटे आदित्य की तुलना सुनील गावस्कर से की थी. इसके पीछे का रहस्य क्या है? फुसफुसाहटें हैं कि नारवेकर आदित्य को खुश करके उनके चचेरे भाई वरुण सरदेसाई को पार्टी के युवा मोर्चे, युवा सेना का मुखिया बनाने से रोकना चाहते हैं. मोटे तौर पर हिंट यही है कि तेजस अधिक योग्य हैं.

–संदीप उन्नीथन, साथ में राहुल नरोन्हा, किरण डी. तारे और अमिताभ श्रीवास्तव

बाहरी

भाजपा ने गुजरात में संगठन महासचिव पद के लिए **रत्नाकर** को भेजा है. यह पद पार्टी को संघ के साथ जोड़े रखता है. उत्तर प्रदेश के निवासी रत्नाकर ने भीकूभाई दलसानिया की जगह ली है, जो किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले महासचिव थे. खबर है कि संघ के पूर्णकालिक पूर्व नेता को लाया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पार्टी के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं.

भाषा का झगड़ा

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के पास मुख्यमंत्री **हेमंत सोरेन** से नाखुश होने की कई वजहें हैं. पिछले हफ्ते उन्हें एक वजह और मिल गई. सोरेन सरकार ने दास की 2016 की रोजगार नीति बदल दी है. नई नीति में ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थी को बंगाली, ओड़िया और उर्दू के साथ एक दर्जन जनजातीय भाषाओं में से एक आना अनिवार्य किया गया है. दास ने चेतावनी दी है कि अगर हिंदी को इसमें शामिल नहीं किया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे. एक जंग की आहट है.

अंशुमान पोयरेकर/गेट्टी इमेजेज

राजमोहन गांधी

मेहमान का पन्ना

पवित्र इतिहास से छेड़छाड़ के पीछे आखिर मंशा क्या है!

साबरमती आश्रम को ''विश्वस्तरीय स्मारक'' में तब्दील करने की सरकारी परियोजना पर राष्ट्रव्यापी आपत्तियां शुरू करने वाले तीन व्यक्ति—प्रकाश शाह, आनंद पटवर्धन और गणेश एन. देवी—गहरी अंतरात्मा वाले कलाकार हैं. पटवर्धन के कुछ उल्लेखनीय वृत्तचित्रों में गांधी को दिखाया गया है, लेकिन वे न तो पारंपरिक और न गैर-पारंपरिक गांधीवादी हैं. देवी मशहूर भाषाविद-उपन्यासकार हैं और गुजराती पत्रिका *निरीक्षक* के संस्थापक-संपादक शाह फिलहाल गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं.

अगर मुझ जैसे व्यक्ति ने उनके बयान (जो अखबारों में रामचंद्र गुहा के एक जबरदस्त लेख से पहले आया) पर सहर्ष दस्तखत किए, तो इसलिए नहीं कि मैं गांधी का वंशज हूं, इसलिए भी नहीं कि मैंने गांधी का विशद अध्ययन किया है. असल कारण जल्द बताऊंगा, पर अकाट्य वजह यह विचार था कि साबरमती के किनारे लगातार बढ़ता ही जा रहा पर्यटकीय ढांचा उस आश्रम को निगल नहीं तो बौना तो कर ही रहा था.

लाखों दूसरे लोगों की तरह मुझे भी आश्रम की हैरतअंगेज सादगी अच्छी लगती है. नदी, पेड़ और एक सदी से ज्यादा पुराने कुटिया सरीखे आवासों की ढलवां छतें, वह हृदयकुंज सहित जहां गांधी और कस्तूरबा रहते थे, अहमदाबाद आने वालों के लिए देखने लायक हैं. इतनी ही गरिमापूर्ण साथ की इमारतें हैं, जिनकी अभिकल्पना 1960 के दशक में चार्ल्स कोरिया ने की थी और जिनके भीतर आगंतुक आश्रम और उससे जुड़े आंदोलनों के इतिहास चित्र देख सकते हैं.

यह साबरमती आश्रम ही था जहां निर्भीकता; अस्पृश्यता उन्मूलन; सर्वधर्म समभाव; और मेहनत करके रोजी कमाने की खूबसूरती जैसी अहम नई प्रतिज्ञाओं के साथ जोड़कर प्राचीन नैतिक-आध्यात्मिक संकल्पों को नए अर्थ दिए गए. नतीजा: यह सीधा-सादा, साफ-सुथरा आश्रम सामाजिक क्रांति की क्यारी बन गया. और एक राजनैतिक क्रांति भी इसी आश्रम में हुई थी, जहां इतिहास को बदल देने वाले तीन आंदोलनों ने जन्म लिया. इनमें से हरेक अंततः भारत की आजादी के लिए बेहद अहम था. एक, 1919 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने वाले रॉलेट ऐक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, एक ऐसा विद्रोह जिसका जवाब ब्रिटिश राज ने जलियांवाला बाग के रूप में दिया. दूसरा, 1920 से 1922 तक साम्राज्य के साथ असहयोग के लिए था. तीसरा (1930-33) नमक मार्च से शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा के लिए था.

हम इस पवित्र इतिहास के साथ बगैर सोचे-विचारे छेड़छाड़ चाहते हैं?

मेरा सबसे बड़ा ऐतराज इसी से जुड़ा है. मैं यह मान ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी की सरकार गांधी के विचारों को वापस लाना या लागू करना चाहती है. अमेरिका के राष्ट्रपति रहते ट्रंप को और चीन के नंबर एक शी जिनपिंग को साबरमती ले जाना और उनके साथ गांधी-कस्तूरबा की कुटिया में फोटो खिंचवाना महात्मा का नहीं, मोदी का नगाड़ा पीटने की कवायदें थीं.

गांधी के लक्ष्य कोई छिपे या गुप्त नहीं थे. न साबरमती में, न डांडी मार्च के दौरान, न उन जेलों में जहां साम्राज्य ने उन्हें कैद करके रखा, न 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, न नोआखली और बिहार में—हिंदू नोआखली में रहते थे और मुसलमान बिहार में—संकट से घिरी जिंदगियों को बचाने के लिए 1846-47 की उनकी तीर्थयात्राओं में. न उनके जीवन के निर्णायक अंतिम वर्ष 1947-48 में, जब नेहरू और पटेल के समर्थन से गांधी ने पक्का किया कि स्वतंत्र भारत सबका राष्ट्र होगा, केवल हिंदू बहुसंख्यकों का नहीं. बराबरी और बहुलता की यह वचनबद्धता आंबेडकर के बनाए संविधान में प्रतिष्ठापित है.

बेहतर होगा कि कोई सरकार या कोई पार्टी आश्रम को न 'गढ़े', और कम से कम गांधी के मूल लक्ष्यों के विरोधी तो नहीं ही गढ़ें

इस वचन के प्रति मोदी सरकार की निष्ठा पर मुझे संदेह है. प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सात से ज्यादा साल में, और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और भी लंबी पारी में, नरेंद्र मोदी दर्जनों स्थितियों से दोचार हुए जब वह वचन दोहराए जाने के लिए चीख-चीखकर पुकार रहा था. इनमें भीड़ के हमले और उसके हाथों पीट-पीटकर मार डालने के मौके भी शामिल हैं, जब पुलिस को तमाम जिंदगियों को बचाने और सभी अपराधियों पर मुकदमा चलाने का खुला आदेश देने, लोगों को भरोसा दिलाने और अपराधियों की भर्त्सना करने की जरूरत थी.

क्या ऐसा आदेश, आश्वासन या डांट एक बार भी सुनी गई? आप एक ओर बहुसंख्यक सर्वोच्चता पर आंख मटकाएं और दूसरी ओर गांधी की प्रतिमा के आगे सिर झुकाएं, यह संभव है? आप लोगों को ''उनके कपड़ों से पहचानने'' के लिए कहकर भी उस शख्स का गुणगान कर सकते हैं जो *ईश्वर अल्ला तेरे नाम* गाता था? यह पाखंड घृणास्पद है.

गांधी के लिए वाणी की स्वतंत्रता उतनी ही बुनियादी थी जितनी सभी भारतीयों की बराबर हिफाजत. बीसियों निःस्वार्थ कार्यकर्ता सीखचों के पीछे हों तो क्या आप खामोश रह सकते हैं? जब हत्या-बलात्कार की खबर जुटाने जा रहा रिपोर्टर गिरफ्तार कर लिया जाता है? फिर भी आप दावा करते हैं कि आप गांधी को दुनिया के सामने ला रहे हैं? उस गांधी को जो अपनी ज्यादातर जिंदगी एक पत्रकार भी था?

साबरमती आश्रम को सार्वजनिक धन की जरूरत है और रहेगी. सुधार करने ही हैं तो आश्रम के न्यासियों, गांधी अध्येताओं और तमाम वास्तुविदों और पर्यावरणविदों को जोड़ें. कोई सरकार या कोई पार्टी आश्रम को न 'गढ़े', गांधी के मूल लक्ष्यों के विरोधी तो न ही गढ़ें.

राजमोहन गांधी *इतिहासकार हैं*

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स

निगलनी ही पड़ी कड़वी गोली

श्वेता पुंज

मे जेम्स/गेट्टी इमेजेज

बरसों की टालमटोल के बाद केंद्र ने कुख्यात रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स या पूर्वप्रभावी कर कानून से आखिर पिंड छुड़ा ही लिया. यह कानून 2012 में तब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी लाए थे. इसे भारत में कारोबार करने में एक प्रमुख अड़चन बताया गया. हाल में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालतों ने वोडाफोन पीएलसी और केयर्न एनर्जी पीएलसी से जुड़े मामलों में भारत सरकार के खिलाफ दो फैसले दिए. इसके बाद वैश्विक निवेशक समुदाय में इस कानून के खिलाफ चीख-पुकार कई गुना बढ़ गई, जिससे सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था.

राज्यसभा ने 9 अगस्त को कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया. केंद्र ने कड़वी गोली जरूर निगली है पर यह कदम भारत को निवेशकों के माकूल देश के तौर पर पेश करने में उसकी मदद करेगा. यह इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि महामारी के चलते कम वृद्धि दर, कम निजी निवेश और बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां जाने सरीखी परेशानियों से तार-तार अर्थव्यवस्था को फिर आगे बढ़ाने के लिए देश को विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है.

आयकर कानून में संशोधन के जरिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तब लाया गया था, जब जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन पीएलसी के पक्ष में फैसला सुनाया. मामला यह था कि ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी ने 2007 में बिचौलिया कंपनियों के एक जाल के जरिए हचिसंस की भारतीय संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया. सरकार ने उसके खिलाफ 2 अरब डॉलर (आज 14,600 करोड़ रुपए) के कर का दावा ठोक दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आयकर कानून में संशोधन करके भारत में अपनी परिसंपत्तियों का बड़ा हिस्सा रखने वाली विदेशी कंपनियों के बीच विलय और अधिग्रहणों पर कर लगाने का अधिकार हासिल कर लिया.

औद्योगिक समूह सरकारी नीतियों की खुलेआम आलोचना से सामान्यत: बचते हैं. फिर भी उनमें से कई ने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की. खबरों के मुताबिक, अमेरिका में बिजनेस लॉबी समूहों ने तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि ''इस अचानक और अभूतपूर्व कदम (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स संशोधन विधेयक) ने विदेशी निवेश और कराधान को लेकर भारत सरकार की नीतियों में भरोसे की जड़ें हिला दी हैं और कानून के शासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.''

निवेशकों को डराने के अलावा रेट्रोस्पेक्टिव कर का नतीजा यह भी हुआ कि भारत सरकार के खिलाफ कई मामले अंतरराष्ट्रीय पंचाटों में ले जाए गए. सितंबर 2020 में हेग स्थित एक पंचाट ने फैसला दिया कि वोडाफोन से भारत की रेट्रोस्पेक्टिव कर की मांग भारत और नीदरलैंड के बीच निवेश संधि का उल्लंघन है. ऐसे ही एक फैसले के बाद ब्रिटिश तेल फर्म केयर्न एनर्जी ने इस साल जुलाई में 2 करोड़ यूरो (करीब 175 करोड़ रुपए) से ज्यादा की फ्रांस स्थित भारतीय संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया. एक और मध्यस्थता मामले में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र की फर्म देवास मल्टीमीडिया, जिसने एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शाखा) के खिलाफ केस जीता था, भारत सरकार के खिलाफ मध्यस्थता में जीते गए 1.2 अरब डॉलर (करीब 8,800 करोड़ रु.) से ज्यादा की मांग कर रही है और सरकार की संपत्ति जब्त करने पर विचार कर

रही है (देवास का केस हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव कर से नहीं जुड़ा है पर अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी तो है ही).

कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र इन मामलों का जवाब कैसे देता है. केयर्न के मामले में वित्त मंत्रालय ने 'देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान' खोजने के लिए 'रचनात्मक बातचीत' का भरोसा दिलाया. मोदी सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून वापस लेने से जुड़े सवालों से यही कहकर निपटती रही कि यह कानून भविष्य के मामलों पर लागू नहीं किया जाएगा. कई सालों से वह इस मुद्दे पर बहुत संभलकर चल रही थी. 2015 में तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाशिंगटन डीसी में कहा था, ''जहां तक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात है, मैं समझता हूं कि भारत का अनुभव बहुत बुरा रहा है. अगर भविष्य में कोई सरकार ऐसा करती है तो भारी कीमत चुकानी होगी.'' कारोबार करने की सहूलत में सुधार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अगस्त को कहा कि केंद्र इन मामलों में अदा की गई रकम लौटने की पेशकश करता है. लौटाने योग्य कुल रकम 8,100 करोड़ रुपए

अतीत की समस्या वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव केस दरअसल कंपनी के 2007 में हचिसन की भारतीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है

होने का अनुमान है.

इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट फर्म फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा कहते हैं कि राजनैतिक लोकतंत्र देखना हो तो भारत अच्छी जगह है, लेकिन वोडाफोन के मामले जैसी स्थितियों में पता चलता है कि यह आर्थिक तानाशाही है. वे कहते हैं, ''कागजों पर होने और जमीन पर घटने में भारी फर्क है'' और नियम अक्सर मनमाने ढंग से बदल दिए जाते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स संशोधन विधेयक भी इसी का उदाहरण है. वे कहते हैं, ''सरकार अब इस तरह (पेश करेगी) कि समस्या हल हो गई है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अपनी छवि सुधार सके.'' ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से जुड़े एक और अर्थशास्त्री बताते हैं कि संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उनके फोन की घंटी रुकने के नाम ही नहीं ले रही. वे कहते हैं, ''निवेशक स्पष्टता चाहते हैं कि दूसरे मामलों में क्या होगा.'' रिपोर्टों के मुताबिक, रेट्रोस्पेक्टिव कर कानून हटाने का असर केयर्न एनर्जी और वोडाफोन के अलावा 15 अन्य मामलों पर पड़ेगा.

कुछ लोगों का कहना है कि फ्रांस में भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने के केयर्न के लड़ाकू फैसले के चलते सरकार यह कदम उठाने को मजबूर हुई हो सकती है. वजह चाहे जो हो, भारत सरकार ने आखिरकार ऐसे कानून से अपना पिंड छुड़ा लिया है जिसका विरोध एमएनसी ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय न्यायिक अदालतें भी कर रही थीं. इस कदम से निवेश में फौरन उछाल भले न आए पर निवेशों पर नजर रखने वालों का कहना है कि यह तब देश के हक में काम करेगा जब वह चीन से सप्लाइ चेन भारत लाने के बारे में विभिन्न कंपनियों से

रेट्रोस्पेक्टिव कराधान खत्म करने के फैसले से केंद्र सरकार को भारत की छवि निवेशकों के अनुकूल वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी

बातचीत करेगा.

भारत 2014 से 2019 के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार लाया है—वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में वह समग्र 63वीं पायदान पर था—पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट या अनुबंध प्रवर्तन में पीछे—109 देशों में 163वीं पायदान पर—है. आगे बढ़ने के लिए कानून में इस बदलाव की भावना को जमीन पर उतारना जरूरी है. भारत को नीतिगत अनिश्चितता के देश से अवसरों का देश बनना होगा.

चौतरफा मुश्किलों से घिरी टेलीकॉम फर्म वोडाफोन आइडिया के लिए यह कदम बड़ी घटना है. सूत्रों का कहना है कि राहत योजना पर काम पर पहले से चल रहा था, अब उस पर अमल का बहुत अच्छा संदेश गया है. जिस दिन विधेयक पारित हुआ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआइएल) का शेयर कंपनी बोर्ड की तरफ से चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का इस्तीफा स्वीकार करने के ऐलान के बाद आई 24 फीसद की गिरावट से उबरकर 7.10 रुपए पर बंद हुआ. विश्लेषकों का कहना है कि विधेयक का सीधा फायदा वोडाफोन पीएलसी को होगा और संभावना है कि मातृ कंपनी नकदी का संकट झेल रही मातहत भारतीय कंपनी में पैसा डालेगी. प्राइवेट इक्विटी फंड भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं. टीआरएआइ या ट्राइ (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2020 को वीआइएल की बाजार हिस्सेदारी 24.6 फीसद थी और इस पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था. कंपनी का कर्ज मार्च 2016 के बाद तेजी से बढ़ा, जब उसे 35 फीसद की बाजार हिस्सेदारी वाले सबसे बड़े खिलाड़ी रिलायंस जियो की तरफ से छेड़े गए टैरिफ युद्ध के बीच मुश्किल बाजार में रास्ता बनाना पड़ा. वीआइएल को वायुतरंगों के इस्तेमाल और लाइसेंस फीस के तौर पर अगले 10 सालों में सरकार को करीब 6.74 अरब डॉलर (49,876 करोड़ रुपए) चुकाने हैं.

विवादास्पद रेट्रोस्पेक्टिव कानून को खत्म करके केंद्र सरकार ने दुनिया भर के निवेशकों को बहुत सही संदेश दिया है. अगर भारत सरकार ग्रोथ और रोजगारों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती है तो उसे अब उसे ऐसे कई और कदम उठाने होंगे जिनसे भारत वैश्विक कंपनियों के लिए ज्यादा आकर्षक ठिकाना बन सके, साथ ही इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी मिल सके. ■

राजस्थान

कांग्रेस में जारी खींचतान

रोहित परिहार

एएनआइ

असहज स्थिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट

राजस्थान कांग्रेस में पिछले दो महीनों में काफी हलचल देखी गई. वरिष्ठ नेताओं ने कई बार दिल्ली से जयपुर नाप दिया, पर आलाकमान ने अभी तक यह बताया नहीं कि इस पूरी कवायद का नतीजा क्या रहा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी नेता सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान की कहानी पुरानी है, लेकिन बीच-बीच में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे अटकलों के नए दौर शुरू हो जाते हैं. गांधी परिवार—सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी—में से किसी ने भी, इसका कोई संकेत नहीं दिया है कि दिसंबर 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाएगा. इससे यथास्थिति तो बनी हुई है, लेकिन गहलोत सरकार और पायलट के भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी बनी रहती है.

उधर, बागी नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद पायलट खेमे ने राजस्थान सरकार और संगठन में बड़ी भूमिका मिलने की उम्मीद लगा रखी है. लेकिन गहलोत गुट का कहना है कि पंजाब और राजस्थान को एक ही पलड़े में नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा, गहलोत ने आलाकमान को अश्वासन दिया है कि अगर उन्हें अपनी रणनीति के मुताबिक चलने दिया गया तो वे अगले साल खाली हो रही भाजपा के कब्जे वाली राज्यसभा की चार में से तीन सीटें कांग्रेस की झोली में डाल देंगे. पिछले साल राज्यसभा चुनाव से पहले मार्च में गहलोत ने अपने खिलाफ भाजपा की तख्तापलट की साजिश को भांप लिया था. हालांकि चुनाव को कोविड लॉकडाउन की वजह से जून के लिए टाल दिया गया. फिर, कांग्रेस में अंतिम विद्रोह जून में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ और तुरंत बाद पूर्ण शक्ति प्रदर्शन में बदल गया. गहलोत का कहना है कि चुनाव इसलिए टाले गए ताकि विद्रोहियों को साधने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए राजी करने का वक्त मिल जाए. अगले राज्यसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस के बागियों के वोट न हासिल कर ले, इसे लेकर आलाकमान सतर्क है.

आलाकमान और राज्य कांग्रेस के बीच कोई अलग खिचड़ी पक रही है, इन अटकलों को इसलिए हवा मिली क्योंकि दो पीसीसी प्रमुख, कर्नाटक से डी.के. शिवकुमार और हरियाणा से कुमारी शैलजा, भी क्रमशः 1 और 3 अगस्त को गहलोत से मिलने आए. इन बैठकों को तो निजी मुलाकात बताया गया पर गहलोत विरोधी खेमे ने कहा कि ये बैठकें गहलोत पर दबाव बनाने के लिए थीं कि वे पायलट और उनके विधायकों को समायोजित करें. वहीं, गहलोत के सहयोगियों ने बताया कि दोनों बैठकें राहुल गांधी को मजबूत करने सहित कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई थीं. लेकिन गहलोत विरोधी खेमे की मांगों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत समझते हुए महासचिव अजय माकन और के.सी. वेणुगोपाल, गहलोत से मिलने के लिए 24 जुलाई की देर शाम दिल्ली से जयपुर पहुंचे थे.

राजस्थान के प्रभारी महासचिव माकन के सामने कुछ विधायकों ने संगठन की नियुक्तियों और सियासी पोस्टिंग में हो रही बहुत अधिक देरी की शिकायत दर्ज कराई

राजस्थान के प्रभारी महासचिव माकन ने पिछले पखवाड़े विधायकों के साथ बैठक की और उनकी राय दर्ज की. एक सामान्य फीडबैक यह रहा कि अधिकतर विधायकों ने गहलोत में अपना भरोसा दोहराया. पर कुछ विधायक जो गहलोत के साथ हैं और पायलट के साथ नहीं, उन्होंने भी कुछ मंत्रियों के खराब प्रदर्शन, अहंकार और विधायकों से मिलने से कतराने की शिकायत करते हुए मंत्रिपरिषद में फेरबदल की मांग की. उन्होंने संगठन में नियुक्तियों और सियासी पोस्टिंग में हो रही बहुत देरी की भी शिकायत दर्ज कराई.

माकन की विस्तृत कवायद के नतीजे क्या रहे, इसका इंतजार कांग्रेसियों, प्रशासन और यहां तक कि जनता को भी है. ऐसे संकेत हैं कि दोनों खेमों में इस बात पर सहमति बहुत कम है कि पहले कैबिनेट फेरबदल और विस्तार किया जाए या पहले कम महत्वपूर्ण सियासी और संगठनात्मक नियुक्तियां की जाएं. पायलट खेमे को छह से आठ मंत्रिपद और समकक्ष पदों की उम्मीद है और वह कुछ मंत्रियों को हटाना चाहता है. लेकिन गहलोत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के लिए इतनी दरियादिली को तैयार नहीं हैं. माना जाता है कि गहलोत विस्तार को टालने के इच्छुक हैं, पर वे कुछ विधायकों और अन्य प्रमुख नेताओं को बोर्ड और निगमों के साथ-साथ पार्टी के अहम पदों पर समायोजित करने के इच्छुक हैं. गहलोत खेमा इस बात पर भी जोर देता है कि कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले भी कुछ इनाम की तलाश में रहे हैं. गहलोत भी विधायकों की मांगों को मानने में काफी नरमी दिखा रहे हैं. कुछ मंत्रियों के रवैये को अगर छोड़ दें तो सरकार जिस तरह विधायकों की मांगें सुन रही है, उससे ज्यादातर विधायक खुश हैं. लेकिन, ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस में खींचतान अभी खत्म नहीं होने जा रही है. ■

अर्थात्

आएगा आने वाला

अंशुमान तिवारी

अगर आपने बीते एक साल के दौरान यूपीआइ (यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस) का इस्तेमाल किया है या मोबाइल वालेट से भुगतान किया है तो आप प्रसिद्ध जर्मन भौतिकीविद मैक्स प्लैंक को सही सिद्ध कर रहे हैं जो कहते थे कि विज्ञान और तकनीक से लोगों की सोच नहीं बदलती. बड़े परिवर्तन इसलिए होते हैं क्योंकि बदलावों का प्रतिरोध मर चुका होता है और नई पीढ़ी इन नए उपायों के अलावा और कुछ नहीं जानती.

भारतीय बैंकों के निजीकरण का तो पता नहीं लेकिन बैंकिंग बदल चुकी है. ओपन बैंकिंग या निओ बैंकिंग का आगाज हो चुका है. बात इतनी ही नहीं कि 2017 से 2021 बीच भारत में यूपीआइ के जरिए पेमेंट 388 फीसद सालाना की दर से बढ़ा है, या भारत में डिजिटल पेमेंट सालाना बीते एक दशक में 55 (संख्या) और 43 (विनिमय का मूल्य) फीसद की गति से बढ़े हैं बल्कि भारत की समग्र बैंकिंग ही पुराने कूल-किनारे तोड़ कर बहने को तैयार है.

तकनीकें अपने लिए माहौल खुद बना लेती हैं. जब बैंकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए 'सहमति' (ओपन फाइनेंशियल डेटा नेटवर्क), कैशलेस भुगतानों के लिए यूपीआइ, आइएमपीएस, मोबाइल वालेट जैसी नए प्रयोग हो रहे थे या कि आधार के जरिए ऑनलाइन प्रमाणन की प्रणाली बनाई जा रही थी तब यह नहीं सोचा गया था कि यह भविष्य की बैंकिंग की बुनियाद होगी. बाजार जरूरतें बदलीं, ग्राहकों की विविध जरूरतों के लिए नए उत्पादों का अवसर बना तो नए उद्यमियों (स्टार्ट-अप) ने 'सहमति, यूपीआइ, ईआधार' की मदर फिनटेक पर केंद्रित ओपन बैंकिंग का बिगुल बजा दिया.

बदलाव का नक्शा

कारोबारी रिश्तों के मामले में भारतीय बैंकिंग, बैंकों के झुंड से बाहर नहीं निकलने के हक में नहीं रही है लेकिन मामला कारोबार बढ़ाने का था तो उन्हें ऐप्लिकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस (एपीआइ) के बाजार में कूदना पड़ा. इसके जरिए बैंकिंग सेवाएं और ग्राहकों की सूचनाएं उन कंपनियों के लिए खुल गईं जिनके इतिहास में बैंकिंग का कोई तजुर्बा दर्ज नहीं है. यही फिनटेक है जिसके जरिए कोई कंपनी, बैंकों के समानांतर ही उनकी सेवाएं (जमा, लोन, कार्ड भुगतान आदि) ग्राहकों दे सकती है.

इस बदलाव ने भारतीय बैंकिंग को अचानक अमेरिका, यूरोप, जैसे आधुनिक बैंकिंग मुल्कों की पांत में खड़ा कर दिया. कोटक, आइसीआइसीआइ, एचडीएफसी और येस बैंक ने नए तकनीक प्लेटफॉर्म बनाकर फिनटेक कंपनियों को नए अवसर दिए. सनद रहे कि यूपीआइ में सरकारी बैंक आगे आए हैं लेकिन एपीआइ मे सरकारी बैंक पिछड़ गए हैं क्योंकि इसके लिए कोर बैंकिंग ढांचे में व्यापक और महंगे तकनीकी बदलावों की जरूरत है.

मंदी के बीच भारत में आई स्टार्ट-अप की नई खेप फिनटेक पर केंद्रित है. यह बाजार करीब 15,000 करोड़ रुपए का है. डिजिटल फिफ्थ की रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में 112 स्टार्ट-अप को करीब 1.4 अरब डॉलर का निवेश मिला. फिनटेक स्टार्ट-अप 2016 से अब तक 10 अरब डॉलर उठा चुके हैं. आठ कंपनियां यूनीकॉर्न (एक अरब डॉलर) बन चुकी हैं. बीते एक वित्त वर्ष में इस बाजार में करीब नौ बड़े अधिग्रहण हो चुके हैं. फ्लिपकार्ट वाले सचिन बंसल के नवी (वित्त वर्ष 2020 में 221 करोड़ का कारोबार) का डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस को लपक लेना खासा चर्चित रहा है.

दो दर्जन इंस्टा लोन और डिस्काउंट ब्रोकिंग स्टार्ट-अप आ चुके हैं. अब ऑनलाइन बीमा बेचने और उद्योग को कर्ज बांटने की बारी है.

बाजार बदला तो नियामक भी जागे. रिजर्व बैंक ने ई पेमेंट और डिजिटल सेवाओं के लिए बैंकों को नियम व नीति बनाने को कहा है. ई वालेट बैंक पर एनईएफटी/आरटीजीएस की इजाजत दे दी गई है. बीमा नियामक (इरडा) और रिजर्व बैंक, दोनों ही वीडियो आधारित केवाइसी की छूट देने लगे हैं. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनने वाली है जो कर्ज लेने वालों की पूरी सूचना एक जगह रखेगी.

खतरों भरा खालीपन

इस संभावनामय क्रांति के बीच एक खतरनाक खालीपन हमें डराता है. चाइनीज ऐप लोन घोटाले ने बताया है कि फिनटेक और ओपन बैंकिंग आने के बावजूद सूचनाओं की सुरक्षा (डेटा प्रोटेक्शन) को लेकर सरकार की नींद नहीं टूटी है. नया कानून अधर में है. डेटा इंपावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (दीपा) पर नीति आयोग की सिफारिश मंत्रालयों के बीच अब भी भटक रही है.

बैंकों का निजीकरण हो न हो लेकिन भारत की बैंकिंग पूरी तरह बदल चुकी है

तकनीकें सुविधा और सहजता लाती हैं, इसलिए वे बेहद खामोशी के साथ संस्कृतियां बदल देती हैं. या कि 2020 में भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश (25.5 अरब विनिमय) देश हो गया है. चीन भारत से पीछे है.

तकनीकें, जैविक विकास जैसी होती हैं, मनुष्य का वापस वानर बन जाना असंभव है. पुरानी बैंकिंग की वापसी भी अब नामुमकिन है लेकिन भारत के लोग इस क्रांति का लाभ लेने से पहले निजता और सूचनाएं गंवाकर लुट पिट न जाएं, इसके लिए राजनीति पर निर्णायक दबाव बनाना होगा. नहीं तो ओपन बैंकिंग हमारी वित्तीय निजता लूट में भी बदल सकती है. @anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

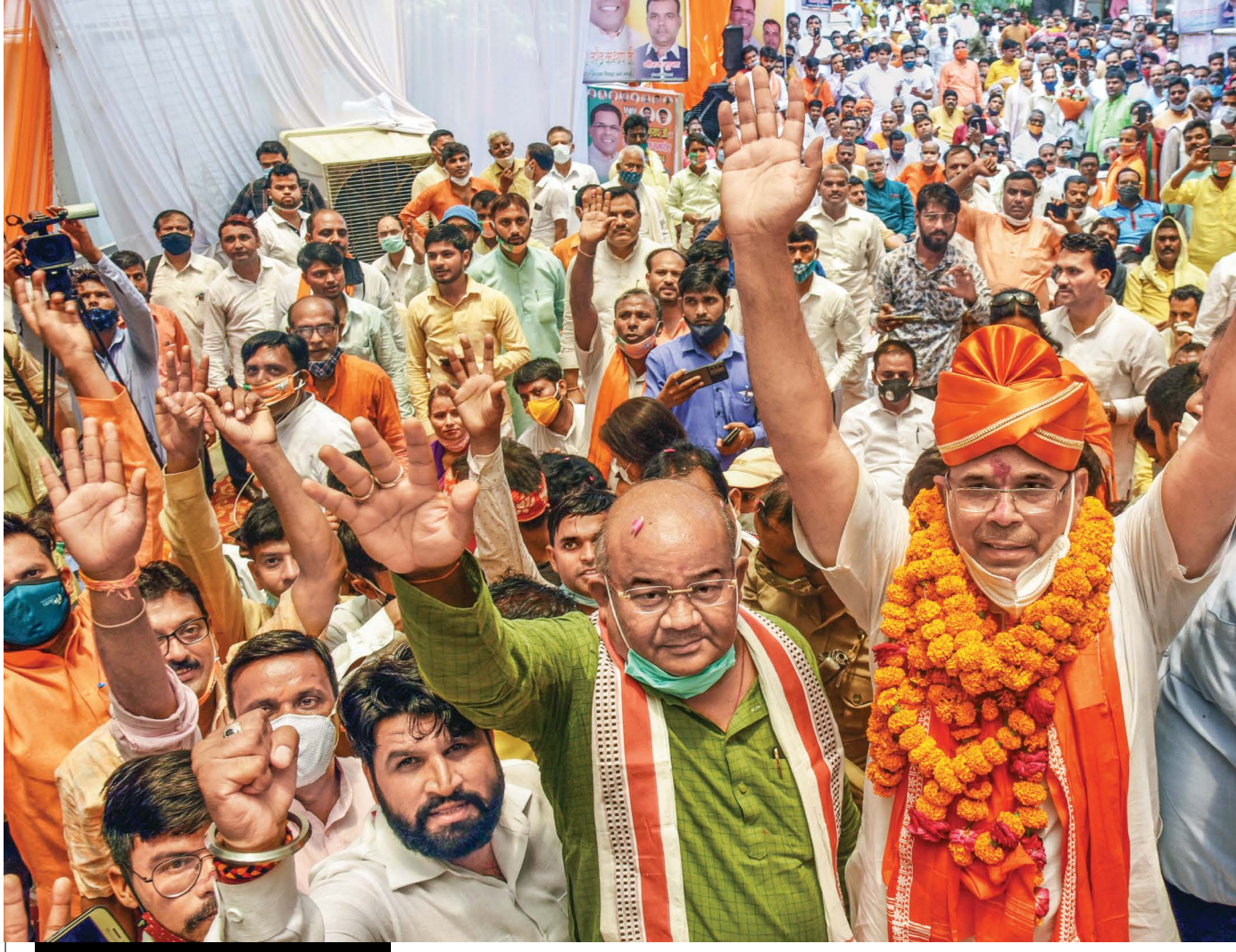

उत्तर प्रदेश | भाजपा

आगे रहने को पिछड़ा दांव

आसन्न विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए भाजपा ने उठाए कई निर्णायक कदम

आशीष मिश्र

शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर लखनऊ के कांशीराम ईकोगार्डन में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों ने पहली जुलाई से प्रदर्शन शुरू कर दिया था. 2020 में बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी. अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी को शिक्षकों की भर्ती में निर्धारित 27% की बजाय 4% से भी कम आरक्षण मिला है. आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने 20 जुलाई को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. फिर भी प्रदर्शन जारी था.

2 अगस्त की सुबह 10 बजे ये अभ्यर्थी राजधानी में ही 7, कालिदास मार्ग स्थित उप-मुख्यमंत्री केशव

मनीष अग्निहोत्री

दो हाथ ऊपर
भाजपा प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने पर नरेंद्र कश्यप लखनऊ में समर्थकों के बीच

प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयोगवश उसी समय पड़ोस में ही 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे. हाल की खिड़की से उन्होंने अभ्यर्थियों को नारेबाजी करते देखा तो अधिकारियों के जरिए उन्हें बुलाया और उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने तुरंत बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दस दिन के भीतर शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के आरोपों की जांच करते हुए अभ्यर्थियों की शिकायतें दूर करने का आदेश दिया. प्रदर्शनकारियों में से एक रामसागर पटेल बताते हैं, ''शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी हुई है. मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों का रवैया सकारात्मक है. 15 अगस्त से पहले समाधान की उम्मीद जगी है.''

यूपी में 2022 के विधानासभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अब छह महीने से भी कम का समय है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जातिगत समीकरणों को हर तरह से दुरुस्त कर लेना चाहती है.

इसी क्रम में 29 जुलाई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मेडिकल एजुकेशन से जुडे अखिल भारतीय कोटे (एक्यूआइ) में ओबीसी समुदाय के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब एक्यूआइ योजना में ओबीसी के लिए 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी. 12 दिन बाद मोदी सरकार ने ओबीसी के हितों से जुड़ा 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया. लोकसभा और राज्यसभा से पारित इस विधेयक में प्रावधान है कि राज्य अपने हिसाब से ओबीसी का निर्धारण कर सकेंगे.

मोदी सरकार के इन फैसले को अगले विधानसभा चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि यूपी में ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा (54%) है. लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. एस.के. द्विवेदी बताते हैं, ''2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुसंख्य ओबीसी मतदाताओं का समर्थन मिला था. तभी तो पार्टी के 312 विधायकों में से 101 पिछड़ी जाति के जीते थे. सरकार में ओबीसी नेताओं को पर्याप्त तवज्जो न दिए जाने और आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसी मांगों पर पिछड़े वर्ग में नाराजगी है. यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग को लुभाने में जुट गयी है.''

वर्ष 2001 में पेश हुई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में पिछड़ी जाति की आबादी 54% है. इन जातियों में सबसे ज्यादा यादव हैं. इसके बाद कुर्मी, लोध, पाल, निषाद जैसी जातियों का नंबर आता है. 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़ी जातियों का बहुसंख्य वोट भाजपा को मिला था. उसी बूते भाजपा विधानसभा की 403 में 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी.

ओबीसी में यादवों के बाद प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाली कुर्मी जाति को साधने के लिए भाजपा ने केंद्र की सरकार में दो नए मंत्री बनाए हैं

प्रदेश में पिछड़े वर्ग का समर्थन बरकरार रखने को भाजपा ने जुलाई, 2019 में कुर्मी जाति के स्वतंत्रदेव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरों के कारण ओबीसी मतदाताओं में दुविधा पनप रही थी. 22 जून को योगी ने मौर्य के घर पहुंचकर मनमुटाव को विराम देने की कोशिश की थी. मार्च 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे. उन्हें मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर पिछड़ी जातियां नाराज चल रही हैं. मौर्य स्पष्ट करते हैं, ''अपेक्षाओं को मैं गलत नहीं मानता. यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों को वह सम्मान नहीं दिया है जो भाजपा ने दिया है. मुझे जिस प्रकार का स्थान भाजपा ने दिया है वैसा कभी किसी और पार्टी ने किसी को नहीं दिया'' (देखें इंटरव्यू). आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं में पकड़ मजबूत करने के लिए फिर से मौर्य को आगे किया है. जनता की समस्याएं सुलझाने को वे हर सोमवार अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन आयोजित कर रहे हैं. विभिन्न जिलों का दौरा कर वे विकास योजनाओं की शुरुआत करने में भी व्यस्त हैं.

मोदी सरकार के 7 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी में ओबीसी मतों को सहेजने की चिंता साफ दिखाई दे रही थी. मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से पूरे सात नए मंत्री शामिल हुए. इनमें से तीन पिछड़ी जाति से हैं. गैर-यादव पिछड़ी जातियों में कुर्मी कुल ओबीसी आबादी का करीब सात फीसदी हैं. कुर्मी जाति को साधने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल और महराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को जगह दी गई है. पूर्वांचल में बस्ती से लेकर बलिया जिले की 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर कुर्मी बिरादरी काफी प्रभावी है. इसीलिए पूर्वांचल से दोनों मंत्री इसी बिरादरी से हैं.

मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार लोध जाति को भी स्थान देते हुए राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को शामिल किया गया है. पिछड़ों में करीब पांच प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली लोध जाति को भाजपा का सबसे बड़ा

बातचीत

‘‘भाजपा पिछड़ा विरोधी होती तो मैं डिप्टी सीएम न बन पाता’’

क्या समस्या है? लखनऊ में अपने आवास पर जनता दर्शन में समस्याएं सुनते उप-मुख्यमंत्री मौर्य

*उत्तर प्रदेश के **उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य** ने एसोसिएट एडिटर **आशीष मिश्र** से भाजपा और पिछड़ी जातियों के बीच संबंध पर विस्तार से बात की. पेश हैं बातचीत के चुनिंदा अंशः*

● ओबीसी मतदाता भाजपा को वोट क्यों दे?
पिछड़ा वर्ग ही नहीं, अनुसूचित वर्ग, सामान्य वर्ग भाजपा की वे शक्तिशाली भुजाएं हैं जिसे तोड़ने की कोशिश सारा विपक्ष एक साथ मिलकर कर रहा है. लेकिन इनके मंसूबे कभी सफल न होंगे.

● विपक्षी दल भाजपा को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं.
भाजपा अगर पिछड़ा विरोधी होती तो केशव प्रसाद मौर्य कभी उपमुख्यमंत्री नहीं बन पाते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते. भाजपा सरकार की योजनाएं समान रूप से सभी जातियों तक पहुंची हैं.

● 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद आपको मुख्यमंत्री न बनाने पर पिछड़ी जातियों में निराशा है.
अपेक्षाओं को मैं गलत नहीं मानता. यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों को वह सम्मान नहीं दिया जो भाजपा ने दिया है. मुझे जिस प्रकार का स्थान भाजपा ने दिया है वैसा कभी किसी और पार्टी ने किसी को भी नहीं दिया.

● चुनाव से पहले आप भी काफी सक्रिय हैं. विकास योजनाओं के उद्घाटन के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं. यह पिछड़े वर्ग के मतदाताओं पर डोरे डालने की पार्टी की योजना तो नहीं?
मैं अति पिछड़ी जाति और बहुत गरीब परिवार में जन्मा हूं. इस नाते भले ही लोग मुझे पिछड़ों का नेता मानते हों पर मैं सभी वर्गों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रहा हूं. विकास योजनाएं जनता की हैं, सरकार में होने के कारण जिन्हें जनता को सौंपना मेरी जिम्मेदारी है.

● ओबीसी जनगणना और आरक्षण की मांग हो रही है. क्या कहेंगे?
पिछड़े वर्ग के लोग कई क्षेत्रों में पीछे छूट गए हैं. उन्हें बराबरी पर लाना भाजपा का सिद्धांत है. विपक्षी दलों को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा.

● अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा यादव मतदाताओं को सपा से दूर करने में कामयाब नहीं हो पाई है?
यह कहना गलत होगा. 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में बड़ी संख्या में यदुवंशियों और राजवंशियों का वोट मिला. ये लोग अब समझ चुके हैं कि विपक्षी दल इनका समर्थन लेकर सत्ता तो प्राप्त करते हैं लेकिन इनके जीवनस्तर में कोई सुधार नहीं करते.

● आपके और मुख्यमंत्री योगी के बीच मनमुटाव की बातें बीते साढ़े चार साल से चल रही थीं.
यह अफवाह विपक्षी दल फैला रहे थे. मुख्यमंत्री योगी और मैं मिलकर काम कर रहे हैं. मेरे घर सुख-दुख के हर अवसर पर मुख्यमंत्री का हमेशा साथ मिला है. पिछले वर्ष उनके पिताजी के निधन पर आयोजित शोक सभा का संचालन मैंने किया था.

● 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस में से कौन-सा दल भाजपा के लिए खतरा है?
सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिल जाएं तो भी भाजपा के लिए कोई खतरा नहीं. भाजपा का नारा है ‘‘100 में से 60 प्रतिशत हमारा, 40 प्रतिशत में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा’’. पार्टी इसे जमीनी रूप दे चुकी है.

● आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे?
भाजपा तो विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है. हम जब विकास और सुशासन की बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां जातिवाद और तुष्टीकरण की राह पकड़ लेती हैं. हम गरीब और किसान की बात करते हैं तो विपक्षी परिवार की बात करने लगते हैं. प्रदेश की 24 करोड़ जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की हिम्मत विपक्ष के पास नहीं है.

● चुनाव से पहले प्रदेश की सड़कों में गड्ढों को विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले 15 वर्ष के दौरान विपक्षी दलों की सरकार से बहुत अच्छा काम हमारी सरकार के दौरान हुआ है. उम्दा सड़कें कम लागत में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं.

● अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो क्या पिछड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री बन सकता है?
यह प्रश्न काल्पनिक है. अभी हमारा लक्ष्य वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटों पर कमल खिलाने का है.

समर्थक माना जाता है. पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह इस जाति के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. गंभीर स्वास्थ्य के कारण वे बीते डेढ़ महीने से लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआइ) में भर्ती हैं. कल्याण सिंह की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ आने वाला भाजपा का हर केंद्रीय नेता एसजीपीजीआइ जाकर पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी अवश्य लेता है. 1 अगस्त को लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह भी कल्याण सिंह को देखने पहुंचे थे. अलीगढ़ में भाजपा के पूर्व जिला सचिव संजय लोध बताते हैं, ''जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह जी के इलाज की निरंतर निगरानी कर रहे हैं उसकी मिसाल दूसरी नहीं है. इससे लोध जाति में एक सकारात्मक संदेश गया है.''

ओबीसी की जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को चुनौती मिल रही है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष विकास पटेल कहते हैं, ''भाजपा केवल ओबीसी नेताओं का चेहरा दिखाकर ही अगले विधानसभा चुनाव में वोट लेना चाहती है. जातिगत जनगणना जैसे जरूरी मुद्दे पर पार्टी कोई भी पहल नहीं करना चाहती.'' भाजपा को सबसे ज्यादा चुनौती सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मिल रही है. 2017 का विधानसभा चुनाव सुभासपा और भाजपा ने मिलकर लड़ा था. सुभासपा ने चार सीटें जीती थीं. भाजपा सरकार बनने के बाद राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. उन्होंने जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय समिति-2001 की रिपोर्ट लागू करवाने जैसी मांगों को लेकर बगावती तेवर अपना लिए थे. लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही मई, 2019 में मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया था.

पिछड़ी जातियों में 2.44 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले राजभर समाज के प्रभावशाली नेता ओम प्रकाश राजभर अब मुख्यमंत्री योगी को अपना दुश्मन नंबर वन मानते हैं. तल्ख लहजे में वे कहते हैं, ''2022 का विधानसभा चुनाव भाजना ने अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा तो सारी मांगें मान लेने के बावजूद मेरी पार्टी भाजपा से कोई गठबंधन नहीं करेगी.'' राजभर ने पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले नेता बाबूसिंह कुशवाहा, रामधनी बिंद, बाबूराम पाल, प्रेमचंद्र प्रजापति और अनिल सिंह चौहान आदि को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह का दावा है कि ''योगी सरकार की विकास योजनाओं से राजभर समेत सभी पिछड़ी जातियों को लाभ मिला है. राजभर समाज में घटते समर्थन के चलते ही ओम प्रकाश ऊलजुलूल बक रहे हैं.''

अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को देने संबंधी संविधान संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद यूपी में भी ओबीसी आरक्षण की कवायद शुरू हो गई है. प्रदेश में ओबीसी सूची में 79 जातियां शामिल हैं. उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए हैं जिनमें से 39 को मानकों के आधार पर विचार के लिए चयनित किया गया है. जल्द ही इन 39 जातियों को भी ओबीसी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया जा सकता है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की तपिश दूर करने के लिए भाजपा ने ओबीसी कार्ड खेला है. सैनी और कश्यप पश्चिमी यूपी की दो प्रमुख पिछड़ी जतियां हैं. सहारनपुर निवासी जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष तो गाजियाबाद के रहने वाले नरेंद्र कश्यप को भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. भाजपा ओबीसी मोर्चा की 25 सदस्यीय कार्यकारिणी में निषाद, प्रजापति, तेली, गुर्जर, सैनी, सराहू, जाट जैसी अलग-अलग पिछड़ी जातियों के एक-एक नेता को जगह दी गई है. ये पिछड़ी जातियां भाजपा को कितना समर्थन देती हैं, यह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे. तब तक उन्हें मनाने-रिझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा. ■

यूपी की ओबीसी जनसंख्या में विभिन्न जातियों का प्रतिशत

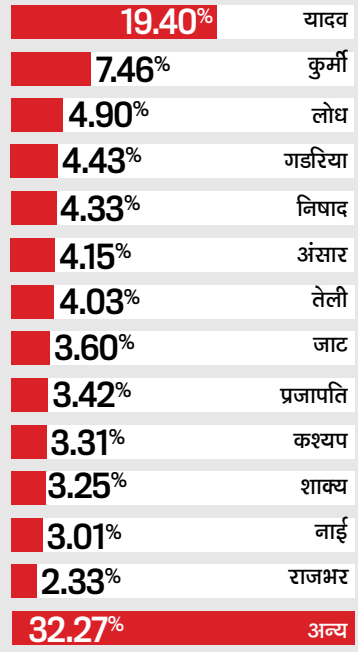

नोटः ये आंकड़े यूपी सामाजिक न्याय समिति–2001 के हैं. इसके मुताबिक, यूपी की कुल आबादी में पिछड़ी जाति –54 फीसद है. अन्य में पिछड़े वर्ग की बढ़ई, लोनिया, मौर्य, फकीर, लोहार, गूजर, कोइरी, धुनिया, सैनी, भुर्जी, दर्जी जैसी जातियां आती हैं

भगवा दल में बढ़ गई पिछड़ी जाति के विधायकों की तादाद

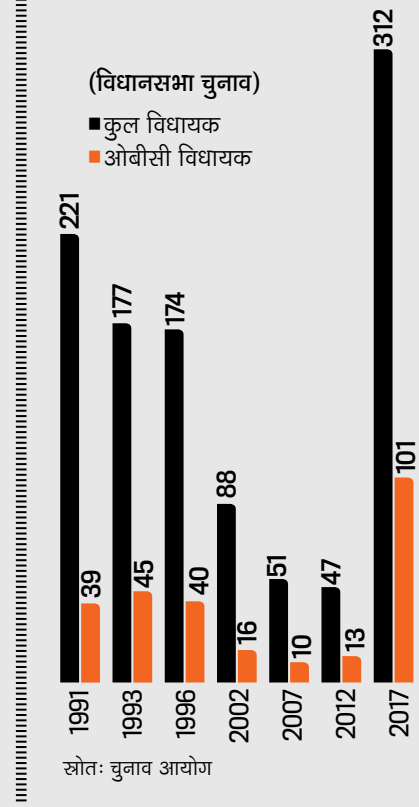

स्रोतः चुनाव आयोग

ग्राफिकः असित रॉय

अर्थव्यवस्था बड़ी दुखती रग

रोजगार-नौकरियों की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतों से लोगों के माथे पर गहरी लकीरें उभरीं, मगर देश को आर्थिक तंगहाली से बाहर निकालने के लिए अभी भी मोदी पर भरोसा

राज चेंगप्पा

इस मुश्किल समय में ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा इस बात की मिसाल हैं कि कैसे कठिनाइयों पर विजय हासिल करके चैंपियन बना जा सकता है. चाहे वह उनकी कोहनी की चोट हो या फिर तोक्यो खेलों का स्थगित होना, जितनी मुश्किलें आती गईं, भाला फेंकने वाले इस एथलीट में जीत की जिद उतनी ही बढ़ती गई. उन्होंने कठिन परिश्रम किया, प्रशिक्षण लिया और इतिहास रचा. ऐसा करते हुए, चोपड़ा ने कड़ी मेहनत, आत्म-विश्वास, उत्कृष्टता की भूख, इसे प्राप्त करने की योजना, फौलादी दृढ़ संकल्प और गंभीर विफलताओं से निबटने का आत्मविश्वास जैसे उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों का परिचय दिया. कोविड महामारी के प्रकोप, विशेष रूप से दूसरी लहर जिसने लोगों के जीवन और आजीविका दोनों को तबाह कर दिया, के बीच हमें सामूहिक रूप से जिस चीज की जरूरत है वह है लोगों का खोया आत्मविश्वास वापस लौटाना. जैसा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, ''आप अगर यह मान लें कि इसे आप ही कर सकते हैं तो समझिए आपने आधा काम कर लिया है.''

चंद्रदीप कुमार

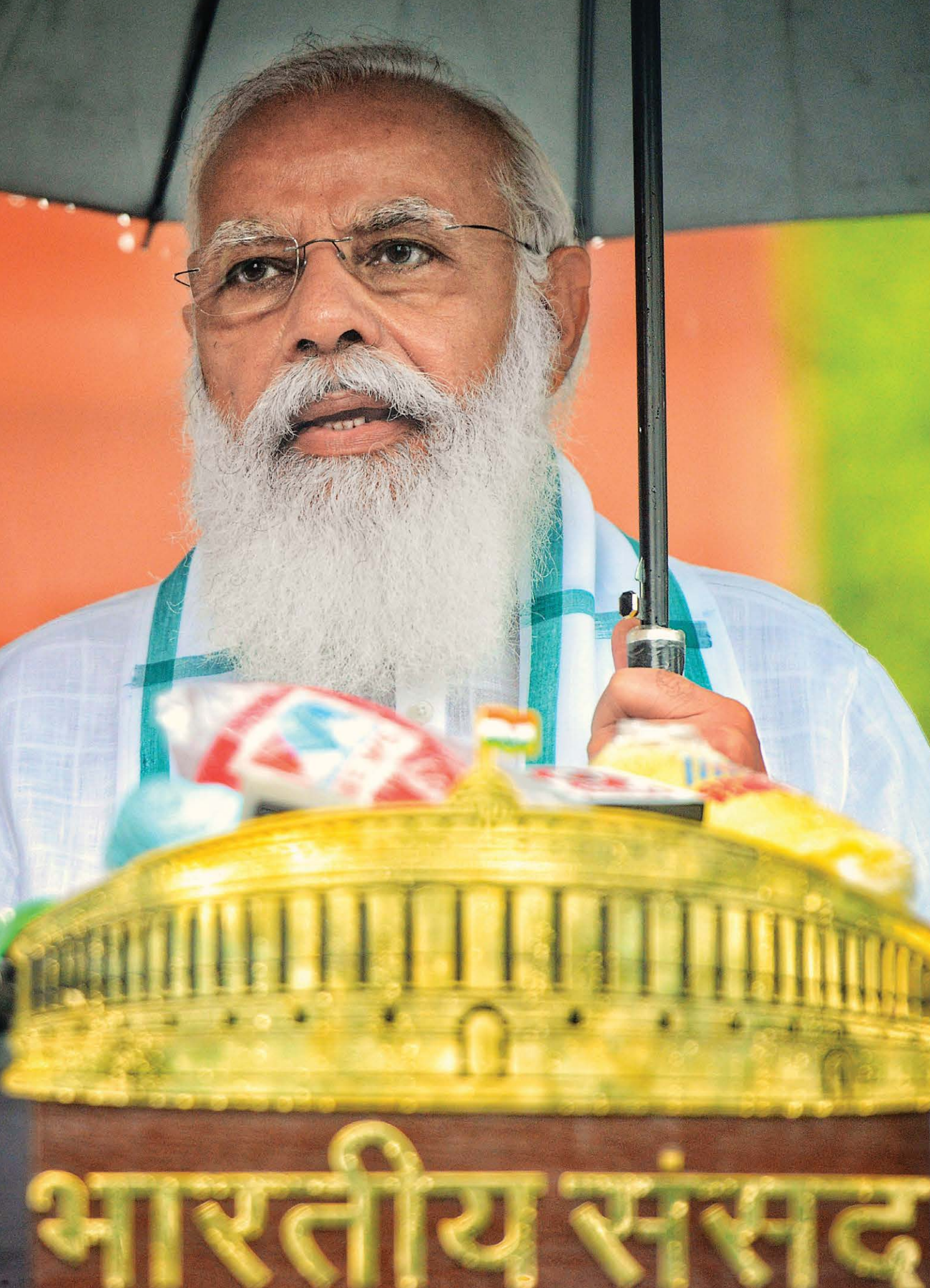
भारतीय संसद

इंडिया टुडे देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण 2021

आज लोकसभा चुनाव हुए तो संभावित नतीजों का अनुमान

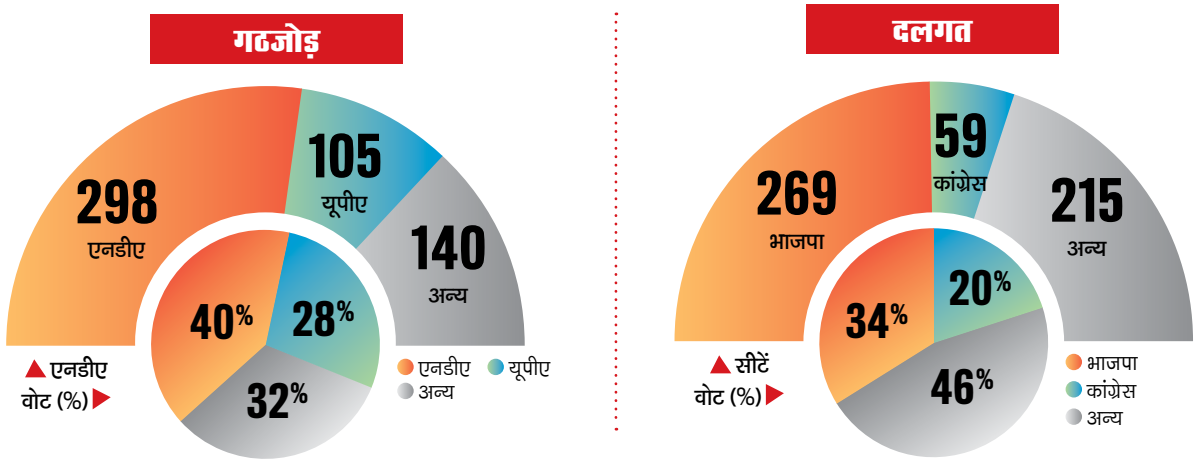

एनडीए: भाजपा, अपना दल, एजीपी, एआइएडीएमके, एआइएनआरसी (ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस), एजेएसयू, बीडीजेएस (भारत धर्म जन सेना), डीएमडीके, जेडी (यू), केसी-टी (केरल कांग्रेस-थॉमस), एलजेपी, एनडीपीपी (नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी), एनपीएफ (नगा पीपुल्स फ्रंट), पीएमके, पीएनके (पुथिया नीधि कचि), आरएलपी, एसएडी, टीएमसी-एम (तमिल मनीला कांग्रेस), एचएएम (एस);

यूपीए: कांग्रेस, एआइएमआइएम, डीएमके, आइयूएमएल, जेएमएम, जेवीएम, केसी-एम (केरल कांग्रेस-मणि), एनसीपी, आरजेडी, जेकेएनसी, आरएसपी, एसडब्ल्यूपी (सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी), वीसीके (विदुथलै चिरुथैगल कचि);

अन्य: आप, फॉरवर्ड ब्लॉक, टीएमसी, एएमएमके, एआइयूडीएफ, बीजेडी, बीएसपी, बीवीए (बहुजन विकास अघाड़ी), सीपीआइ, सीपीएम, जीजीपी, आइएनएलडी, जेसीसी (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़), पीडीपी, एमडीएमके, एमएनएफ, एमएनएम (मक्कल नीधि मैअम), आरएलडी, शिवसेना, आरएसपी (बंगाल में लेफ्ट और केरल में यूपीए के साथ गठबंधन में), एसपी, टीडीपी, टीआरएस, वाइएसआरसीपी, आइएनडी, अन्य

यह एक बड़ा संदेश है जो इंडिया टुडे-कार्वी के ताजातरीन देश का मिजाज (एमओटीएन) सर्वेक्षण के निष्कर्षों से झलकता है. सर्वे ऐसे समय में किया गया है जब भारत, दूसरे तमाम देशों की तरह खुद को एक द्वंद्व भरे दोराहे पर खड़ा पाता है. साल में दो बार होने वाला यह सर्वेक्षण विभिन्न राजनीतिक धाराओं से आने वाले नेताओं के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम कर सकता है कि वे अपने आपसी मतभेदों को दूर करें और देश को उस दलदल से बाहर निकालने की दिशा में साथ मिलकर कड़ी मेहनत करें. देश जिन बड़े संकटों का सामना कर रहा है और उनसे उबरने के लिए जो काम करने चाहिए, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, इसकी थाह सर्वे के परिणामों से मिल सकती है. यहां सभी के लिए कुछ न कुछ सबक है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों के लिए, देश का मिजाज सर्वेक्षण में एक स्पष्ट संकेत है—भले वे अब भी मोदी सरकार को देश के सामने आने वाली परेशानियों को हल करने

22

सीटों का भाजपा को नुक्सान देश का मिज़ाज सर्वेक्षण जनवरी 2021 से अगस्त 2021 के बीच होने का अनुमान

8

सीटों का कांग्रेस को फायदा होने का अनुमान देश का मिज़ाज सर्वेक्षण के उसी अवधि में, भाजपा को नुक्सान का बड़ा फायदा अन्य दलों को

में सबसे सक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हों, लेकिन उत्तरदाता पिछले छह महीनों में केंद्र के प्रदर्शन से नाखुश हैं. यदि अभी चुनाव होता है तो सर्वे के अनुमान के मुताबिक, एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी करेगा, लेकिन उसकी सीटों की संख्या कम हो जाएगी. 2019 के आम चुनाव में जीती गई 353 सीटों से घटकर वे अब 298 रह सकती हैं यानी 55 सीटों का नुकसान संभावित है. भाजपा के लिए व्यक्तिगत रूप से भी चिंता की कुछ बातें नजर आती हैं. सर्वे का अनुमान है कि 2019 में भाजपा की जीती गई 303 सीटें घटकर 269 रह सकती हैं जो साधारण बहुमत से तीन कम है. यानी उसे अपने गठबंधन सहयोगियों पर अधिक आश्रित होना पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता रेटिंग में भी भारी गिरावट आई है. जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन को 'अच्छा' और 'उत्कृष्ट' बताते हुए 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उनके पक्ष में जोरदार समर्थन जताया था. यह संख्या अब घटकर

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती और असित रॉय
इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

लोगों का मूड कैसा

पिछले और मौजूदा देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण में सीटों और वोट प्रतिशत का अनुमान

गठजोड़

सीटों का अनुमान

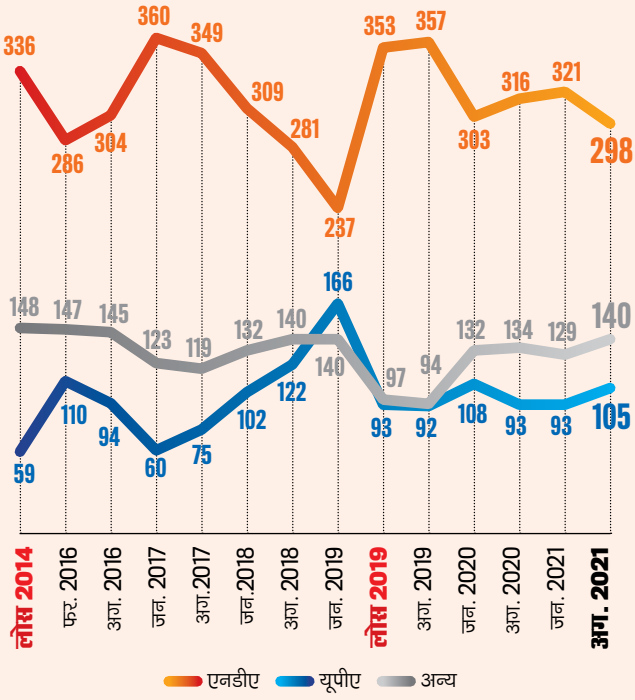

वोट हिस्सेदारी अनुमान (%)

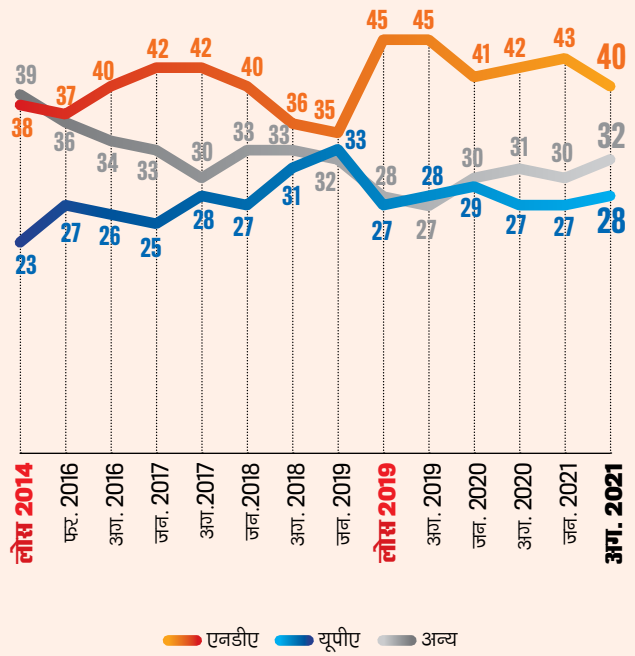

दलगत

सीटों का अनुमान

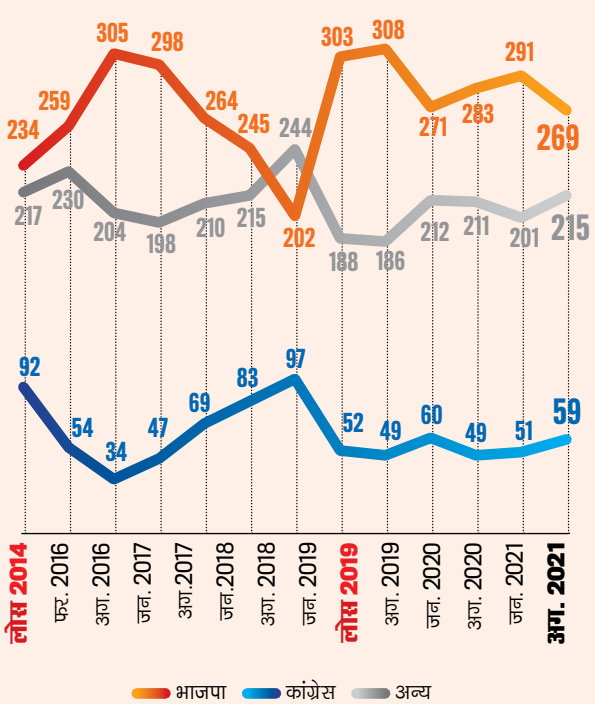

वोट हिस्सेदारी अनुमान (%)

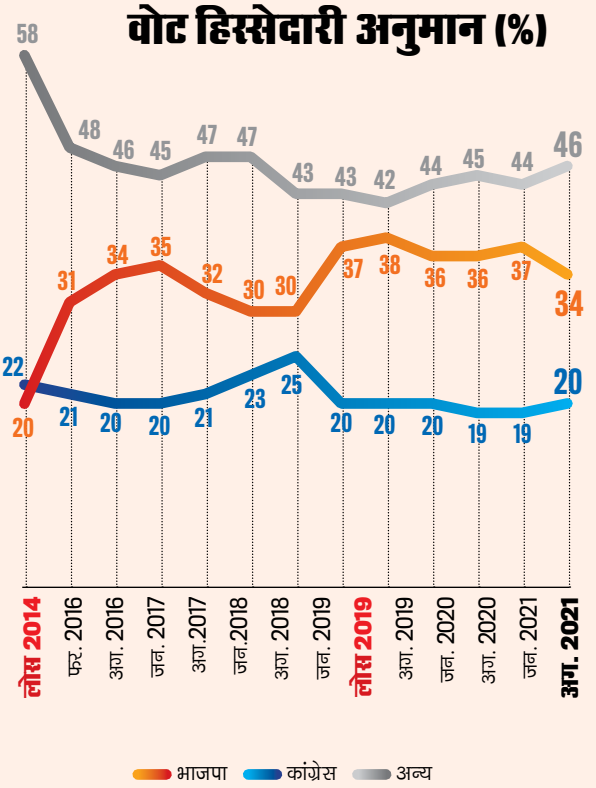

54 प्रतिशत हो गई है. फिर भी कहा जा सकता है कि बहुमत अभी भी देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता में विश्वास रखता है. टीम मोदी के लिए यह भी खुशी की बात होनी चाहिए कि सीटों में गिरावट उतनी तेज नहीं है, जितनी गिरावट का अनुमान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष की शुरुआत यानी 2011 में लगाया गया था. इंडिया टुडे के अगस्त 2011 के देश का मिजाज सर्वे ने यूपीए के लिए 72 सीटों का नुकसान दिखाया था और इसकी सीटें 259 से घटकर 187 होने का अनुमान था. इस आधार पर यह निष्कर्ष लगाया गया था कि उस वर्ष अगर आम चुनाव होते तो यूपीए के हाथ से सत्ता फिसल सकती थी.

मोदी और एनडीए को मौजूदा सर्वे से उभरती चेतावनियों पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर वे उसी तरह की हार से बचना चाहते हैं जो 2014 में यूपीए को अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में मिली थी. कथित घोटालों की बाढ़ और भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा आर्थिक मंदी ने मनमोहन सिंह सरकार को सातवें साल में बहुत परेशान कर दिया था. मोदी सरकार के मामले में, कोविड की दूसरी लहर ने राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की सेहत को एक विनाशकारी झटका दिया है और इसका असर सर्वे के निष्कर्ष में दिखता है. जहां जनवरी 2021 में 73 प्रतिशत की उच्च अनुमोदन रेटिंग के साथ पहली लहर को संभालने के लिए मोदी की सराहना की गई, वहीं दूसरी लहर के दौरान भोगी दुश्वारियों ने यह आंकड़ा 49 प्रतिशत तक गिरा दिया.

विपक्षी पार्टियां अभी तक कोई ऐसा वैकल्पिक अफसाना नहीं पेश कर पाई हैं, जिस पर लोगों को यकीन हो सके और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी पार्टी को पछाड़ दे

हालांकि दूसरी लहर से निबटने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों को लेकर उत्तरदाताओं में अस्वीकृति दिखती है, फिर भी राजनीतिक प्रभाव 2011 में यूपीए के लिए देश का मिजाज सर्वे के अनुमानों से कम गंभीर हैं. यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि महामारी केवल भारत की नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. इतना ही नहीं, उत्तरदाताओं ने केंद्र और राज्यों दोनों को कोविड की दूसरी लहर के खराब प्रबंधन के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया. जबकि जिन लोगों का मानना था कि केंद्र ने महामारी का अच्छा प्रबंधन किया उनकी संख्या में भी गिरावट आई है. जनवरी 2021 में 67 प्रतिशत उत्तरदाता केंद्र के प्रयासों से संतुष्ट नजर आते थे लेकिन ताजा सर्वे में उनकी संख्या 51 प्रतिशत रह गई है. उसी तरह राज्यों की अपनी रेटिंग में भी भारी गिरावट दिखी है और जनवरी के 70 प्रतिशत से गिरकर अब 55 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इसके अलावा, जब लोगो से यह पूछा गया कि दूसरी लहर के दौरान लोगों

प्र. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर आपकी राय क्या है?

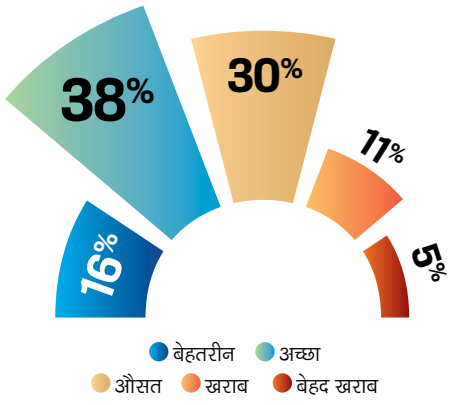

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते

मोदी का कामकाज साल-दर-साल

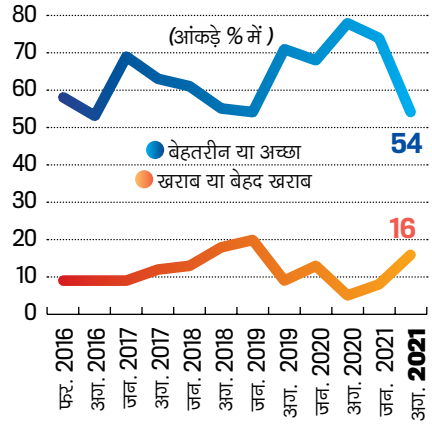

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते

प्र. एनडीए सरकार के कुल कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं?

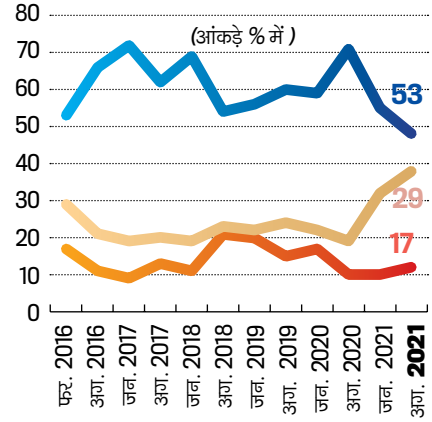

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते

प्र. देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन ?

(आंकड़े % में)

	अगस्त 2021	जनवरी 2021	जनवरी 2020
नरेंद्र मोदी	24	38	66
योगी आदित्यनाथ	11	10	3
राहुल गांधी	10	7	8
अरविंद केजरीवाल	8	5	3
ममता बनर्जी	8	4	2
अमित शाह	7	8	4
सोनिया गांधी	4	4	5
प्रियंका गांधी	4	3	2

चंद्रदीप कुमार

प्र. अब तक देश का बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन?

- नरेंद्र मोदी 27%
- अटलबिहारी वाजपेयी 19%
- लालबहादुर शास्त्री 6%
- इंदिरा गांधी 14%
- पी.वी. नरसिंह राव 3%
- मनमोहन सिंह 11%
- विश्वनाथ प्रताप सिंह 2%
- जवाहरलाल नेहरू 8%
- मोरारजी देसाई 2%
- राजीव गांधी 7%

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते

नरेंद्र मोदी बनाम इंदिरा गांधी

देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक बड़ी बदलावकारी पहल करने वाले दो प्रधानमंत्रियों की लोकप्रियता का रुझान

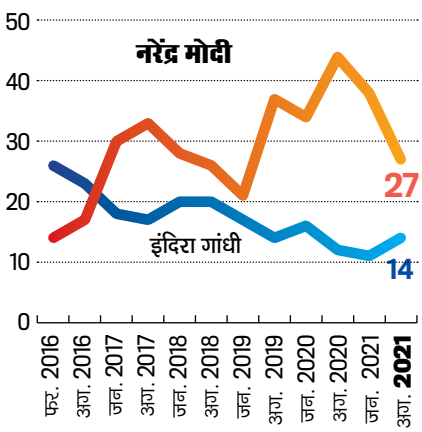

नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी

देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक, दो राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के बारे में बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार लोगों की राय

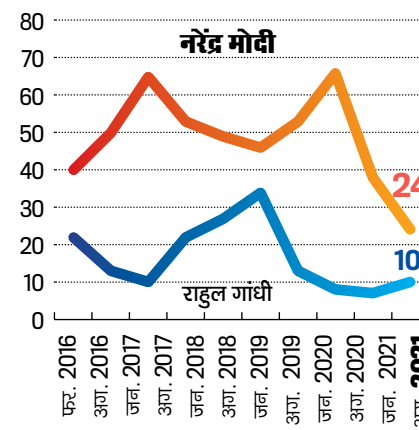

को हुई परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार था, तो 44 प्रतिशत ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी दोषी ठहराया. केवल 13 प्रतिशत का कहना था कि इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार दोषी है.

मोदी सरकार के लिए असल चिंता यह होनी चाहिए कि सर्वे में देश में व्यापक आर्थिक संकट को लेकर नाराजगी दिखती है. अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना उतनी ही बड़ी चुनौती होगी, जितना आज कोविड पर काबू पाना.

मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने को क्रमश: 29 फीसदी और 22 फीसदी की रेटिंग मिली है. इससे पता चलता है कि भाजपा का हिंदूवादी मूल वैचारिक वोट बैंक उसके साथ डटा हुआ है. यही कारण है कि देश भर में व्यापक असंतोष (कोविड और उसके बाद के आर्थिक तनाव पर) के बावजूद भाजपा के वोट शेयर में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में केवल तीन प्रतिशत आंकड़ा—37 से 34 प्रतिशत—घटने का अनुमान है. भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर 14 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना हुआ है.

68%

लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आर्थिक मोर्चे पर रही है, जिनमें आसमान छूती कीमतें, बेरोजगारी, नोटबंदी और धीमी आर्थिक वृद्धि खास हैं

भाजपा के मूल मतदाता अभी भी उसके साथ हैं यह उसके लिए खुशी की बात हो सकती है, पर अगस्त 2021 के देश का मिजाज सर्वे में उत्तरदाताओं ने मोदी सरकार की कई विफलताएं भी गिनाईं जो उसके लिए खतरे की घंटी बजाते हैं. 52 प्रतिशत लोगों का कहना है कि बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी सबसे बड़ी विफलताएं हैं. इसके साथ किसानों के विरोध जैसी दूसरी आर्थिक चिंताओं को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 76 प्रतिशत तक पहुंच जाती है जो कि आर्थिक मोर्चे पर केंद्र के प्रदर्शन को लेकर भारी असहमति दर्शाता है. सरकार के लिए चिंता इसलिए भी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि यह धारणा देश के सभी चार क्षेत्रों में दिखती है. इन मुद्दों में से हरेक के बारे में साफ-साफ प्रश्न पूछे जाने पर भी उत्तरदाताओं ने यही राय दोहराई. 60 फीसदी का मानना है कि केंद्र ने महंगाई पर काबू पाने को पर्याप्त काम नहीं किया. वहीं 59 फीसदी लोग देश में बेरोजगारी की स्थिति को भयावह मानते हैं.

तो कथित व्यापक असंतोष के बावजूद, मोदी और उनकी सरकार को अभी भी जनता का समर्थन क्यों मिल रहा है? प्रधानमंत्री के खिलाफ मजबूत विपक्ष की कमी की ओर इशारा कर देना, इसका आसान जवाब होगा. इस सर्वे में कांग्रेस के लिए पिछले सर्वे के मुकाबले एक प्रतिशत अधिक स्वीकार्यता दिखी है और इसका वोट शेयर 19 प्रतिशत हो गया है. भाजपा के वोट प्रतिशत में आई गिरावट अन्य विपक्षी दलों के खाते में गई है,

मनीष अग्निहोत्री

प्र. एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?

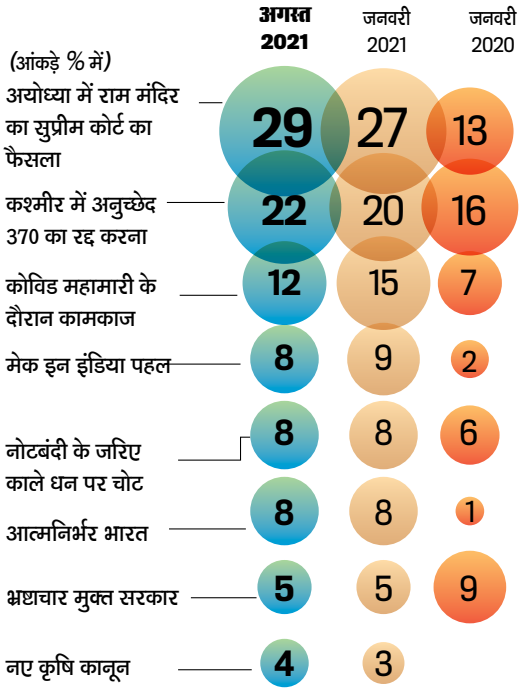

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते, और अन्य

सबसे बड़ी कामयाबी?
अयोध्या में राम की पैड़ी का दृश्य

प्र. फिलहाल देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है?

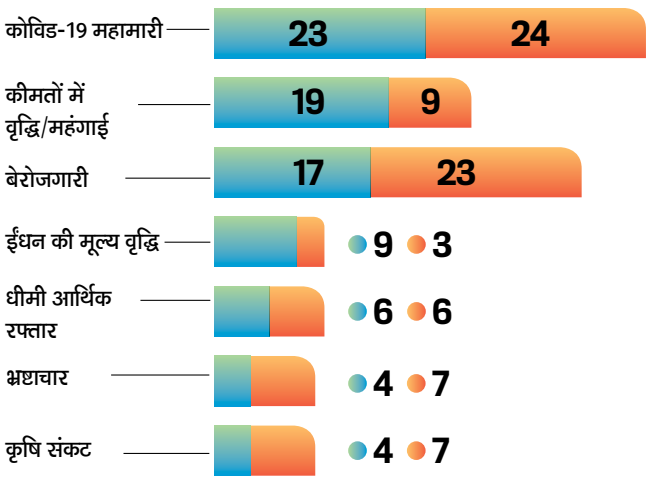

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते, और अन्य

प्र. कोविड-19 महामारी से निबटने के प्रधानमंत्री मोदी के तौर-तरीकों पर आपकी राय?

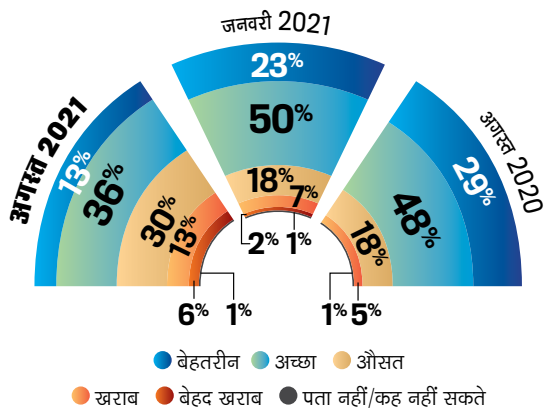

नोटः आंकड़े निकटतम पूर्णांक तक किए गए हैं इसलिए योग 100 नहीं भी हो सकता है

प्र. एनडीए सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या रही है?

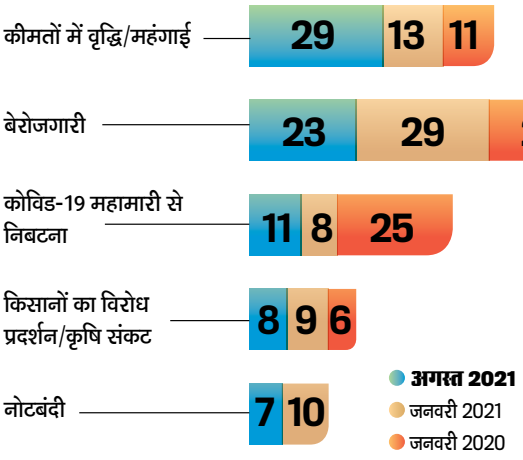

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते, और अन्य

प्र. मोदी सरकार में बेहतरीन कामकाज किस मंत्री का रहा है?

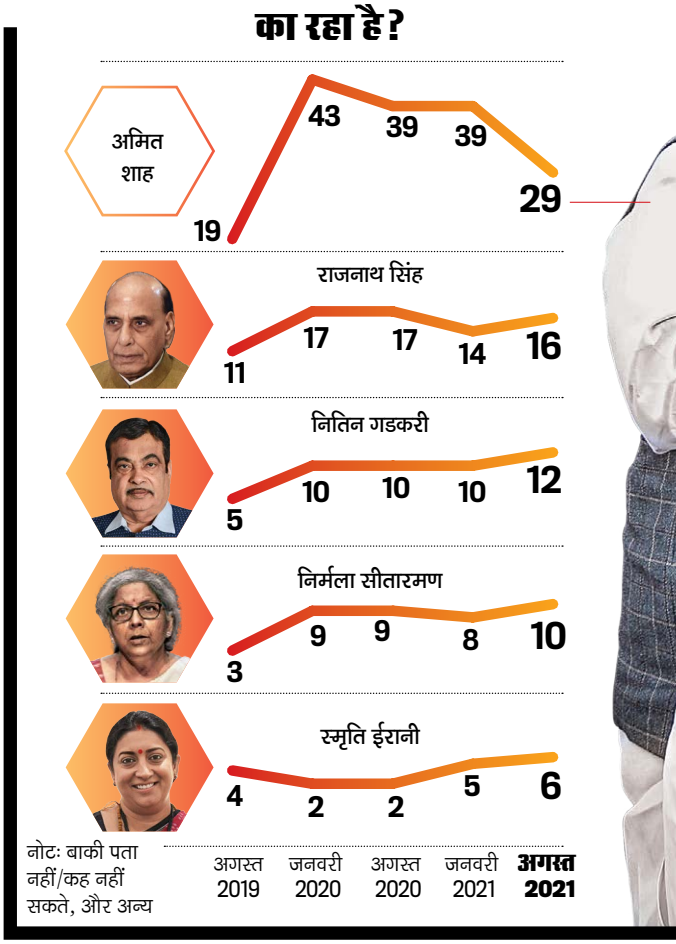

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते, और अन्य

जो खंडित हैं. संयुक्त विपक्ष मोदी का मुकाबला कर सकता है? उत्तरदाता इस बात को लेकर बंटे हुए हैं. 49 फीसदी इसका उत्तर 'हां' में और 43 फीसदी 'ना' में देते हैं. सो, सियासी मंच पर मोदी का दबदबा कायम है. हालांकि इसमें पहले के मुकाबले कमी आई है. टीना (कोई विकल्प नहीं) कारक मोदी के लिए काम कर रहा है.

ऐसा इसलिए है, क्योंकि अभी तक विपक्षी दल कोई ऐसा ठोस वैकल्पिक नैरेटिव लेकर नहीं आए हैं जो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को पछाड़ सके. यह विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस सर्वे में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त गैर-कांग्रेसी नेताओं के रूप में उत्तरादाताओं ने अरविंद केजरीवाल को पहले स्थान पर रखा है, उसके बाद ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव का नंबर आता है. लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अभी तक दिल्ली से बाहर अपनी छाप नहीं छोड़ी है. इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत के बाद ममता का कद बढ़ गया है, लेकिन उन्हें पूरे देश की नेता की छवि बनानी होगी. राहुल गांधी शायद कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं, लेकिन उनकी खुद की रेटिंग में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है.

मौजूदा रैंकिंग में मोदी के शीर्ष पर बने रहने के और भी कई कारण हैं. हालांकि दूसरी लहर की तीव्रता ने जनहानि ज्यादा की है, लेकिन आर्थिक क्षति को पहले जितना बुरा नहीं माना गया है. लगता है मोदी सरकार ने सबक लिया है और बढ़ते दबाव के बावजूद दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय लॉकडाउन का विरोध किया है. इसने

सर्वे किस तरह से हुआ

इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वेक्षण (एमओटीएन) कार्वी इनसाइट्स की ओर से 10 जुलाई और 22 जुलाई 2021 के बीच किया गया. कोविड से उपजी पाबंदियों के कारण 50 फीसद मामलों में आमने-सामने बैठकर सवाल-जवाब करने और 50 फीसद मामलों में टेलीफोन पर बात करने की मिली-जुली पद्धति अपनाई गई. इसके तहत क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित एक मानक और सुव्यवस्थित प्रश्नावली काम में लाई गई.

इस सर्वे में कुल 14,559 लोगों के इंटरव्यू किए गए, जिनमें से 71 फीसद लोग ग्रामीण और 29 फीसद शहरी इलाकों में थे. ये इलाके 19 राज्यों—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 115 संसदीय और 230 विधानसभा क्षेत्रों में फैले थे.

हर विधानसभा क्षेत्र में तय संख्या में इंटरव्यू किए गए. फील्डवर्क कार्वी इनसाइट्स के चेयरमैन रंजीत चिब की देखरेख में वाइस-प्रेसीडेंट गिंटो कैनथ और उनकी टीम की सहायता से किया गया.

प्र. भाजपा में प्रधानमंत्री पद पर मोदी का उत्तराधिकारी बनने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है?

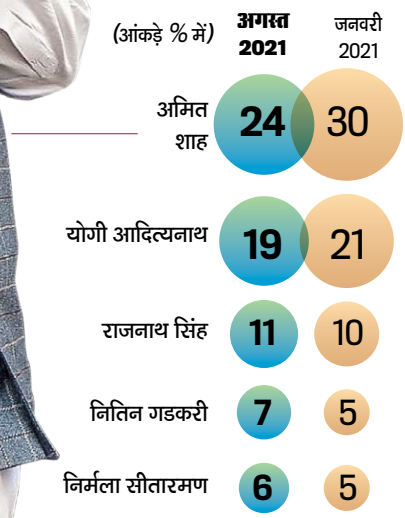

नोटः बाकी पता नहीं/कह नहीं सकते, और अन्य

विक्रम शर्मा

अर्थव्यवस्था के पहिये को चालू रखा, भले ही गति धीमी रही.

अनुमानित जीडीपी में अभी भी गिरावट होगी लेकिन बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और राजस्व संग्रह (जुलाई में एक अस्थाई कमी को छोड़कर) जैसे सभी प्रमुख संकेतक तेजी से आगे बढ़े हैं. 2020-21 में लगातार अच्छी खरीफ और रबी फसल के साथ ग्रामीण संकट उतना नहीं है. वास्तव में, कोविड ने मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में महानगरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया. जहां तक विदेशी मामलों का सवाल है, सीमा पर चीनी घुसपैठ के बावजूद जनता की नजर में मोदी सरकार ने इसे अच्छे से संभाला है और सर्वे के उत्तरदाताओं ने इस दिशा में सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है.

नि:संदेह, एनडीए सरकार में निरंतर विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण कारण केवल मोदी हैं. उनके प्रदान किए गए मजबूत नेतृत्व और 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही विकास के प्रमुख मुद्दों पर निरंतर ध्यान, इन दोनों ही वजहों से यह विश्वास बना है. मोदी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि अधिकांश राजनेताओं के विपरीत उन्होंने यह दिखाया है कि विकास के संदर्भ में उनकी दृष्टि लघु या मध्यम अवधि के उपायों तक सीमित नहीं है. इसके बजाय वे दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिनकी देश को आकांक्षा है. हर घर के लिए शौचालय, सभी के लिए बैंकिंग सुविधाएं, किसानों और युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता, गांवों का विद्युतीकरण, जरूरतमंदों के लिए घर और अब हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाना, गरीबों के लिए शुरू की गई उनकी प्रमुख विकास योजनाओं ने गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा है.

महामारी के दौरान भी कारोबारी तबके के केंद्र की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता को लगातार नाकाफी बताने के बावजूद, मोदी इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि वे किसी भी व्यवसाय के हाथ में सीधे पैसे नहीं रखेंगे बल्कि उन क्षेत्रों में पैसा निवेश करेंगे जिससे कुछ ठोस परिणाम निकल सकें. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2021 में कई साहसिक सुधारों के प्रस्ताव थे जिनमें प्रमुख क्षेत्रों में निजीकरण को तेजी से बढ़ाने और एफडीआइ मानदंडों में छूट शामिल हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश और सरकारी संपत्तियों के मोनेटाइजेशनन के लिए भी भारी प्रतिबद्धता जताई गई थी.

देश का मिजाज सर्वेक्षण से पता चलता है कि रोजगार की समस्या और महंगाई दो ऐसे मुद्दे हैं जिसने लोगों को सबसे ज्यादा चिंतित किया है और मोदी सरकार को फौरन इनका समाधान करने की जरूरत है. चाहे सड़क निर्माण हो या पानी उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है. बीमार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकार ने न केवल ऋण तक पहुंच को आसान बनाया है बल्कि उद्यमिता और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने को युवाओं के लिए स्टार्ट-अप और उद्यमों को भी समर्थन दिया है.

मोदी की विकास के प्रति प्रतिबद्धता ही उनका सबसे मजबूत पक्ष बना हुआ है. वे राहत भत्ते और खैरात देने की जगह उद्यमशीलता को बढ़ावा देना पसंद करेंगे

फिर भी यह धारणा है कि मोदी सरकार पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही. उसे अब वे सभी वादे पूरे करने होंगे जो उसने बजट के दौरान जरूरी आर्थिक विकास तुरंत शुरू करने को किए थे.

जो लोग मोदी को जानते हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री हर चीज पर अपनी पूरी नजर बनाए रखते हैं, अपने निर्णय के साथ डटे रहते हैं (पुरानी कर प्रथा समाप्त करना इसकी एक मिसाल है), हर चीज की पूरी और विस्तृत जानकारी चाहते हैं और काम को समय से पूरा कराने के लिए अधीरता रहती है (मंत्रिमंडल में हालिया साहसी फेरबदल इसका उदाहरण है जिसमें कुछ लोगों की छुट्टी हुई और कुछ नए लोगों को जोड़ा गया). लेकिन वे जिस संकट का सामना कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है और स्वास्थ्य और आर्थिक सुनामी से राष्ट्र को सफलतापूर्वक और सुरक्षित बाहर निकाल लाने और विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए उन्हें अपने सारे हुनर का इस्तेमाल करना होगा. वे विज्ञान-कथा उपन्यासकार ब्रैंडन सैंडरसन के शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं: ''एक महान व्यक्ति की निशानी है कि उसे पता होता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए कब और किस कम महत्वपूर्ण काम को छोड़ना है.'' ■

सावधान! आगे खतरनाक मोड़ है

छीजती बचत, घटती आमदनी और नौकरियों के जाने से पैदा जबरदस्त तंगहाली के चलते सरकार की आर्थिक नीतियों में लोगों का भरोसा डगमगाया

श्वेता पुंज और एम.जी. अरुण

शशिकर इकबाल

इंतजार में आंखें
दिल्ली के चावड़ी बाजार में 20 अप्रैल, 2021 को खाली बैठे बेरोजगार दिहाड़ी मजदूर

अ

ड़तालीस वर्षीय डाली रानी दास दक्षिण दिल्ली में लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती हैं. महामारी से पहले वे और उनके पति मिलकर करीब 30,000 रुपए महीना कमा लेते थे. यह चिराग दिल्ली में एक छोटे-से कमरे का किराया और बेटे की कॉलेज फीस चुकाने के लिए काफी था. बेटे के लिए लैपटॉप खरीदने के वास्ते भी वे कुछ बचा लेती थीं. अब परिवार की आमदनी घटकर करीब आधी रह गई है. स्कूल बस चलाने वाले उनके पति के पास साल भर से काम नहीं है. हालांकि उन्हें सस्ता राशन मिल जाता है, पर वे कहती हैं कि किराया चुकाना और जरूरी खर्च चला पाना मुश्किल हो गया है.

दास उन लाखों हिंदुस्तानियों में से एक हैं जो महामारी के चलते नौकरियां जाने और आमदनियां घटने के साथ गहरी आर्थिक दुश्वारियां झेल रहे हैं. कइयों का मानना है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि इंडिया टुडे देश का मिज़ाज सर्वेक्षण दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के मोदी सरकार के तौर-तरीकों में अगस्त 2020 के बाद लोगों के भरोसे में तेज गिरावट आई है. अगस्त 2019 में करीब 71 फीसद लोगों ने एनडीए सरकार के अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को असाधारण या अच्छा आंका था. दो साल बीतने पर महज 47 फीसद का आकलन ऐसा है. यही नहीं, 20 फीसद ने सरकार के प्रबंधन को खराब या बहुत खराब आंका, जो जनवरी 2021 के 10 फीसद से दोगुने हैं. भरोसे में यह कमी इसलिए भी गौरतलब है क्योंकि पिछले साल अगस्त में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को लेकर उम्मीदें 72 फीसद की ऊंचाई पर थीं.

भरोसे में इस कमी की कई वजहें हैं. भारत की जीडीपी वृद्धि चार दशकों में पहली बार 2020-21 में शून्य से नीचे चली गई और पूरे वित्त वर्ष के दौरान 7.3 फीसद सिकुड़ गई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के मुताबिक, घर-परिवारों की बचत दिसंबर 2020 में खत्म तिमाही में जीडीपी के 8.2 फीसद पर आ गई, जबकि उससे पिछली तिमाही में यह जीडीपी की 10.4 फीसद थी. यह इसी की झलक है कि देश का मिज़ाज सर्वे में महज 28 फीसद लोगों ने अपनी आर्थिक हालत में सुधार की बात कही, जबकि जनवरी 2021 में 49 फीसद ने ऐसा कहा था. वहीं, जनवरी 2021 के मुकाबले दोगुने, करीब 24 फीसद लोगों ने अपनी आर्थिक हालत और बिगड़ने की बात कही. (हालांकि यह आंकड़ा 2016 और 2018 में आर्थिक हालत बिगड़ने की बात कहने वाले लोगों के प्रतिशत से कम है.) कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीदें काफी कम हुई हैं.

प्र. एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से संभाला है, उस बारे में आपकी क्या राय है?

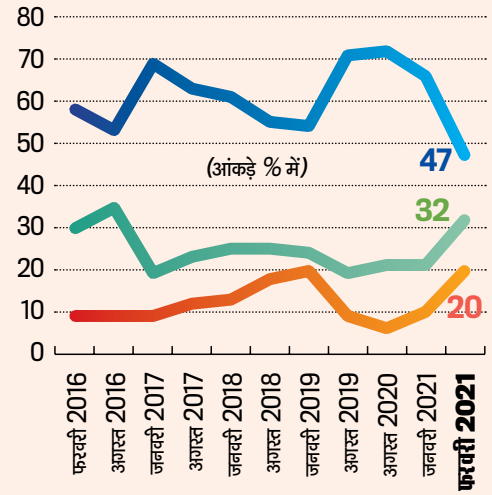

अर्थव्यवस्था संभालने को लेकर केंद्र के प्रदर्शन को अच्छा या बेहतरीन बताने वालों का प्रतिशत (47%) 2016 के बाद सबसे कम है

प्र. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आपकी माली हालत में किस तरह की तब्दीली आई है?

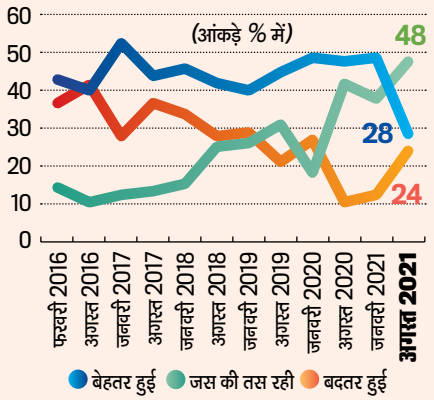

(निकटतम पूर्णांक तक किए जाने की वजह से आंकड़ों का योग 100 आए, यह जरूरी नहीं)

जनवरी 2021 में जब पहली लहर में उतार आना अभी शुरू ही हुआ था, ऐसी उम्मीदें कहीं ज्यादा थीं. उस समय सर्वे में 41 फीसद लोगों ने यह माना था कि अर्थव्यवस्था अगले छह महीनों में बेहतर हो जाएगी.

तंगहाल और परेशान

ताजा सर्वे में महज 21 फीसद लोग अगले छह महीने में अर्थव्यवस्था में सुधार आने को लेकर आशान्वित हैं. कोविड की दूसरी लहर में मौजूदा उतार से पहले इस साल मई और जून में इसकी आर्थिक मार कमर तोड़ देने वाली थी. जून 2021 में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआइ (औद्योगिक गतिविधियों को मापने वाला खरीद प्रबंधकों का सूचकांक) मई 2021 के 50.8 से गिरकर 48.1 पर आ गया, जो इसका 11 महीनों का सबसे निचला स्तर था. वहीं सर्विस पीएमआइ लगातार दूसरे महीने जुलाई 2020 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर तक सिकुड़कर मई के 46.4 से गिरकर 41.2 पर आ गया. सवारी वाहनों की बिक्री में भी गिरावट कायम है और उनकी बिक्री मार्च 2021 के स्तर से घटकर आधी रह गई है. जीएसटी (माल और सेवा कर) का संग्रह घटकर अप्रैल 2021 में 1,41,384 करोड़ रुपए की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जून में घटकर 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया.

प्यू रिसर्च सेंटर के एक अनुमान के मुताबिक, कोविड-19 से पैदा गिरावट के चलते 2020 में भारत का मध्यम वर्ग 3.2 करोड़ तक सिकुड़ा, जबकि गरीबों यानी रोज 2 डॉलर (148 रुपए) या उससे कम कमाने वालों की तादाद में करीब 7.5 करोड़ का इजाफा हुआ. दुनिया भर में जितने गरीब बढ़े, उनमें से करीब 60 फीसद अकेले भारत में बढ़े.

महामारी से पैदा आर्थिक विघ्नों के नतीजतन बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी, जब सरकारी लॉकडाउनों के चलते बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण के काम रुक गए, कई एमएसएमई (सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम) बंद हो गए और तमाम क्षेत्रों की फर्मों ने कामगारों की छंटनी और तनख्वाहों में कटौतियां कीं. सीएमआइई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बावजूद कम से कम 32 लाख लोग नौकरियां गंवा बैठे. लॉकडाउन हटने के बाद असंगठित क्षेत्र में तो कुछ काम-धंधे लौट रहे हैं, पर संगठित क्षेत्र ने कर्मचारियों की तादाद पर अब भी कड़ी लगाम कस रखी है. फिर आश्चर्य क्या कि देश का मिज़ाज सर्वे में 59 फीसद लोगों ने कहा कि भारत में बेरोजगारी की हालत 'बहुत गंभीर' है. इसके अलावा 24 फीसद ने कहा कि यह 'कमोबेश गंभीर' है. केवल 17 फीसद ने कहा कि उन्हें लगता है निकट भविष्य में उनकी घरेलू आमदनी या तनख्वाह बढ़ेगी, जबकि 45 फीसद ने कहा कि जस की तस रहेगी और 34 फीसद को लगता है कि यह और कम होगी.

कीमतों में लगी आग

महंगाई हिंदुस्तानियों की तकलीफों की आग में घी डाल रही है. तेल के ऊंचे दामों और मैन्युफैक्चर्ड सामान की बढ़ती कीमतों के चलते थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) महंगाई मई में साल-दर-साल आधार पर 12.94 फीसद की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई (डब्ल्यूपीआइ खुदरा बाजार में पहुंचने से पहले सामान की कीमतों में बदलाव बताता है). इस बढ़ोतरी में पिछले साल के निचले आधार प्रभाव का भी योगदान है. उधर, सीपीआइ (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से नापी जाने वाली खुदरा महंगाई खाने-पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में तेजी के चलते मई में बढ़कर 6.3 फीसद पर पहुंच गई. इसने आरबीआइ की छह फीसद की सीमा भी पार कर ली. सर्वे में करीब 60 फीसद लोगों को लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई पर नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं कर रही हैं. पेट्रोल के खुदरा दाम में 55 फीसद और डीजल के खुदरा दाम में करीब 50 फीसद टैक्स हैं. मगर न केंद्र और न ही राज्य सरकारें टैक्स में कटौती करती दिखाई देती हैं और उन्होंने इसका बोझ सहने के लिए उपभोक्ता को

प्र. एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है?

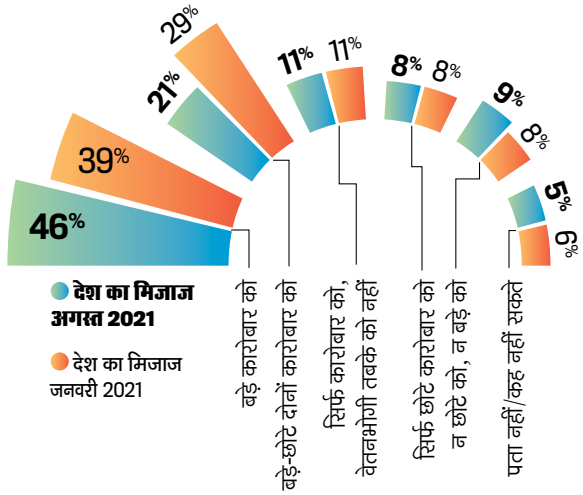

प्र. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में आपकी क्या राय है?

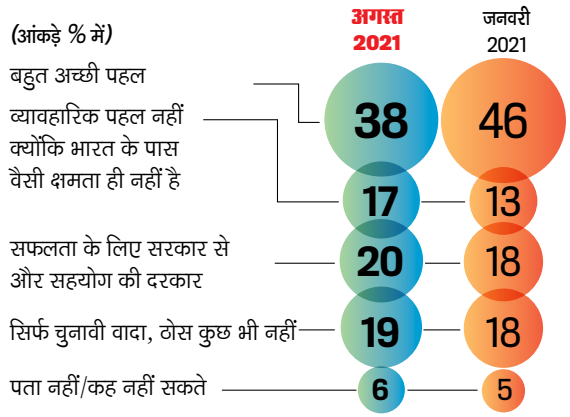

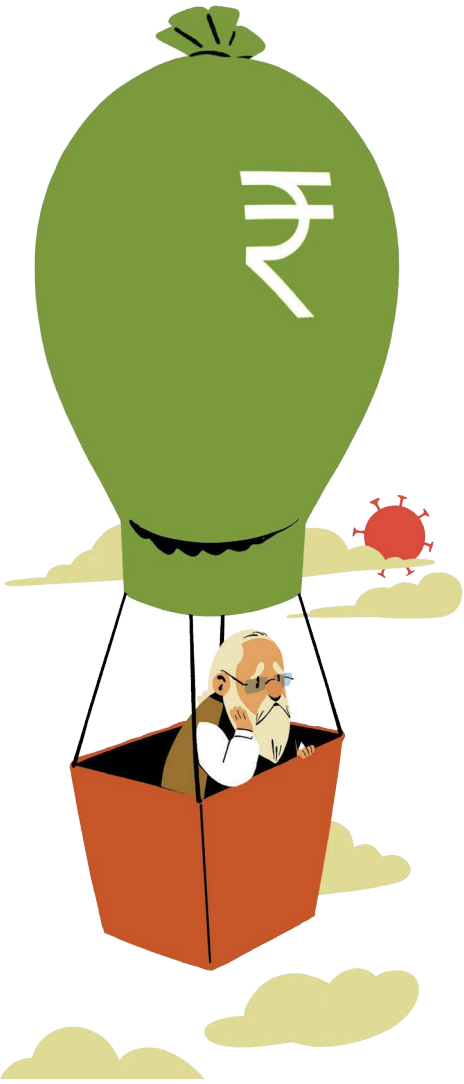

(निकटतम पूर्णांक तक किए जाने की वजह से आंकड़ों का योग 100 आए, यह जरूरी नहीं)

प्र. अगले छह महीने में आप अर्थव्यवस्था को कहां खड़ा देखते हैं?

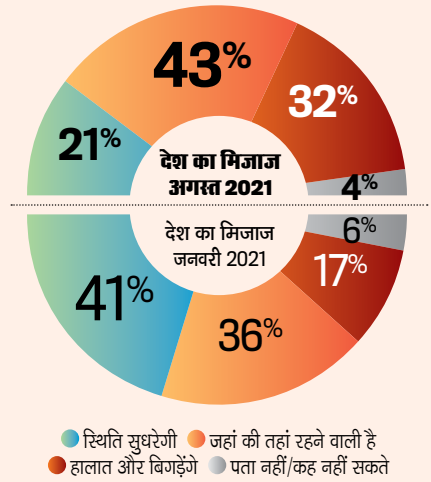

प्र. केंद्र ने महंगाई रोकने के लिए क्या पर्याप्त उपाय किए हैं?

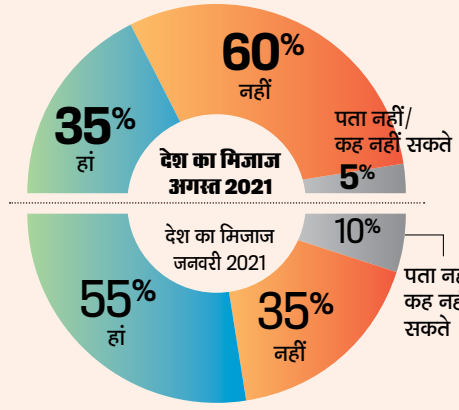

प्र. आपकी नजर में देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है?

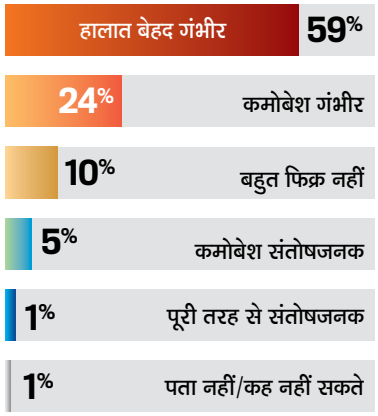

प्र. क्या आपके परिवार की आय/तनख्वाह बढ़ने की कोई उम्मीद है?

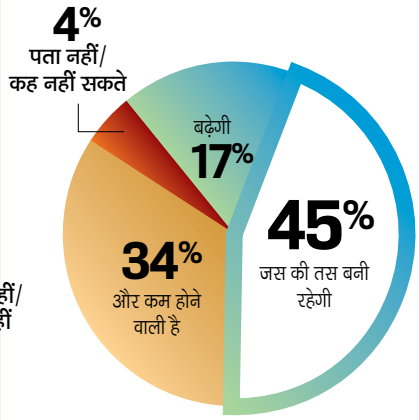

अकेला छोड़ दिया है.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान यह धारणा बढ़ी है कि सरकार की नीतियों का मकसद मोटे तौर पर बड़ी कंपनियों की मदद करना है. सर्वे में 46 फीसद लोगों ने कहा कि केंद्र की नीतियों से केवल बड़े कारोबारों को फायदा हुआ, जबकि जनवरी में ऐसे लोग 39 फीसद थे. मई में मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि 2020-21 की चौथी तिमाही में इंडिया इनकॉर्पोरेशन के राजस्व में एक साल पहले के मुकाबले साल-दर-साल आधार पर 20 फीसद की बढ़ोतरी हुई, जबकि मांग के लौटने और लागत में बचत के उपायों की बदौलत मुनाफा 62 फीसद बढ़ा. ऐसे समय जब आम हिंदुस्तानी नौकरियां जाने, आमदनियों में गिरावट और तेज बढ़ती कीमतों से बदहाल है, कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन और शेयर बाजारों की तेजी ने इस धारणा को बढ़ाया है कि सरकारी नीतियों का मुख्य फायदा बड़े कारोबारों को हो रहा है. यह अर्थव्यवस्था के लिए शुभ है, लेकिन जमीन पर यह कंपनियों की तरफ से निवेश में नहीं बदला.

जहां तक केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात है, 38 फीसद लोगों ने कहा कि यह फायदेमंद कोशिश है, हालांकि उनकी तादाद पिछले सर्वे के 46 फीसद से कम है. वहीं 19 फीसद ने कहा कि यह महज खोखला राजनैतिक वादा भर है, जबकि 17 फीसद की राय में यह व्यावहारिक पहल नहीं है.

जमीनी रिपोर्टों से यह लगातार साफ होता जा रहा है कि महामारी का असर ज्यों-ज्यों लोगों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उनमें बेचैनी साफ बढ़ती जा रही है. केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कई उपाय किए हैं, पर यह सर्वे आर्थिक राहत के मामले में रही-सही कमियों को सामने लाता है. गद्दीनशीन निजाम के लिए यह चेतावनी होनी चाहिए. ■

सेंध लगाने की कमतर सरगर्मी

देश को हलकान कर देने वाली कोविड की मुसीबतों के बावजूद देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक विपक्ष का प्रदर्शन औसत, मगर मोदी से भिड़ने के लिए उनकी एकजुटता होगी दमदार

कौशिक डेका

संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के नेताओं की कम से कम तीन संयुक्त बैठकें हुईं—इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आयोजित नाश्ते पर मुलाकात शामिल है—ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को कथित रूप से सरकार-समर्थित पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन के मुद्दों पर घेरने की साझा रणनीति बनाई जा सके. लगता है कि कोविड महामारी और अर्थव्यवस्था पर उसके असर से लोगों में व्याप्त निराशा के सामान्य भाव ने मोदी के प्रतिद्वंद्वियों को भाजपा की चुनावी अजेयता का घेरा तोड़ पाने की नई उम्मीद दी है. इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के हाथों भगवा पार्टी को मिली हार ने भी इस भाव को गहरा किया है.

अगस्त 2021 के *इंडिया टुडे* देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण की आम धारणा के मुताबिक, विपक्षी दलों का यह मिलन एक मजबूत गठजोड़ के रूप में तैयार हो सकता है. सर्वेक्षण में लगभग आधे लोगों का मानना है कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी गठबंधन बनना संभव है. अधिकांश विपक्षी नेताओं के लिए, यह संभावना न केवल उनके अपने चुनावी/राजनैतिक अस्तित्व, बल्कि देश में लोकतंत्र के वजूद के लिए भी अहम है. कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी कहते हैं, ''साफ है कि सत्तारूढ़ दल से निराशा लोगों की विकल्प की तलाश में बदल जाएगी. विपक्षी दलों की मौजूदा एकजुटता ही विकल्प है तो समय के साथ जनमत धीरे-धीरे

एएनआइ

तालमेल की कोशिशें
3 अगस्त को राहुल गांधी के साथ नाश्ते पर मुलाकात के दौरान 14 विपक्षी दलों के नेता

प्र. विपक्षी दल के रूप में आप कांग्रेस के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस तरह करेंगे?

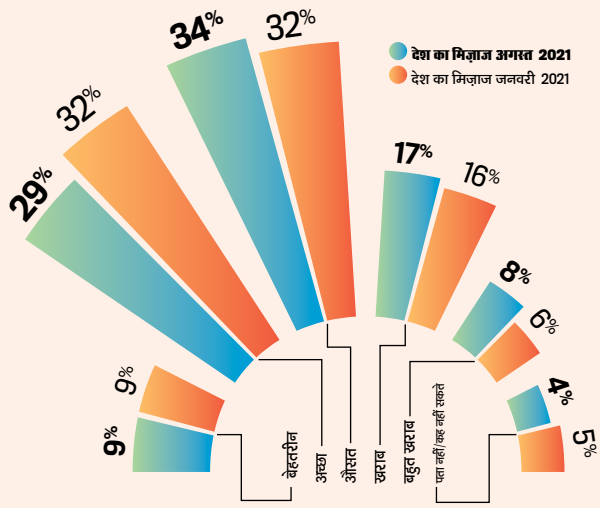

प्र. क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की स्थिति बेहतर रहेगी?

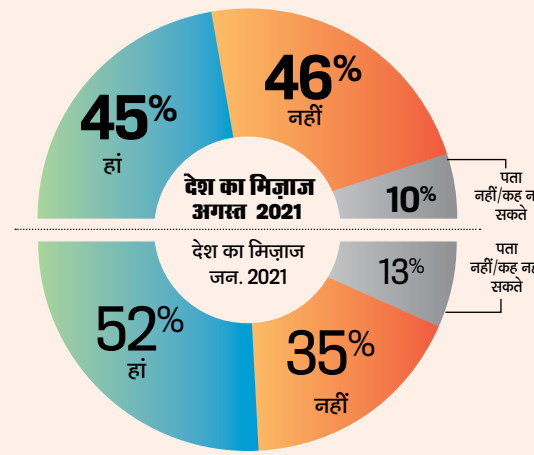

उसके इर्द-गिर्द जुड़ने लगेगा. संविधान में अभिव्यक्त भारत के बुनियादी विचार को एनडीए के हमले से बचाने की जरूरत के बारे में खास बातें तय हो जाने पर बाकी का काम प्रक्रिया दुरुस्त रखने भर का है.''

लेकिन मोदी की बाजीगरी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ विपक्षी एकता ही काफी नहीं होगी. इसके कथ्य को प्रधानमंत्री की आलोचना से आगे बढ़ना होगा. महामारी की दूसरी लहर के दौरान, लोग देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरी तरह नाकाम हो जाने से दुखी थे, लेकिन उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के अभियान बहुत ठीक नहीं लग रहे थे. 50 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना था कि विपक्ष सरकार की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसे आलोचना ही करनी है. हालांकि, इस बात से विपक्षी खेमे के उत्साह पर असर नहीं पड़ा है क्योंकि उनमें से अधिकांश मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय और गोला-बारूद है. राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन कहते हैं, ''देश की चिंता का मुद्दा निश्चय ही विपक्षी दलों की एकता नहीं है. लोग सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री से कुछ कठिन सवालों के जवाब मांग रहे हैं. ये कठिन सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा (पेगासस), अर्थव्यवस्था, नौकरियों, मूल्य वृद्धि और किसानों से जुड़े हैं.''

हालांकि तृणमूल कांग्रेस भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने में सबसे आगे रही है, फिर भी ऐसे किसी गठबंधन की स्थिरता कांग्रेस की भूमिका पर निर्भर करेगी क्योंकि यह सबसे पुरानी पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है. लगभग 60 प्रतिशत लोगों की नजर में कांग्रेस का प्रदर्शन औसत से खराब तक होने का मतलब है कि पार्टी को जल्दी से खुद को व्यवस्थित करना चाहिए. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि वे चुनौती के लिए तैयार हैं. लोकसभा सांसद और कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य मणिकम टैगोर का कहना है, ''राज्य चुनावों में जहां भी हम सीधे भाजपा के खिलाफ लड़े, हमारी पार्टी या तो जीती है या कम से कम

प्र. कौन-सा कांग्रेस नेता पार्टी में जान फूंकने के लिए के लिए आपको मुफीद लगता है?

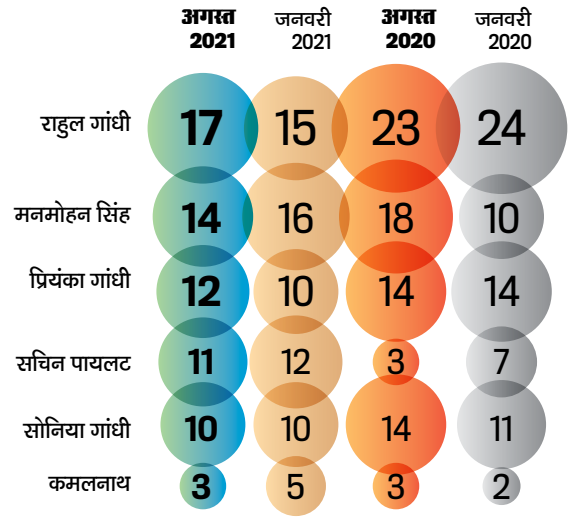

(आंकड़े %में)

भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की अगुआई तृणमूल कांग्रेस ने की है लेकिन गठबंधन की स्थिरता इसमें कांग्रेस की भूमिका पर निर्भर करेगी क्योंकि यह सबसे पुरानी पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है

(आंकड़े %में; कोष्टक में दी गई संख्या देश का मिज़ाज सर्वेक्षण जनवरी 2021 की है)

प्र. गैर-गांधी नेताओं में कौन कांग्रेस को बेहतर नेतृत्व दे सकता है?

1. मनमोहन सिंह **18** [27]
2. सचिन पायलट **17** [17]
3. कमल नाथ **9** [8]
4. पी. चिदंबरम **7** [8]
5. अशोक गहलोत **6** [6]
6. दिग्विजय सिंह **6** [6]
7. कैप्टन अमरिंदर सिंह **5** [6]
8. गुलाम नबी आजाद **5** [4]

प्र. महामारी के दौरान विपक्षी दलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन आप किस तरह करते हैं?

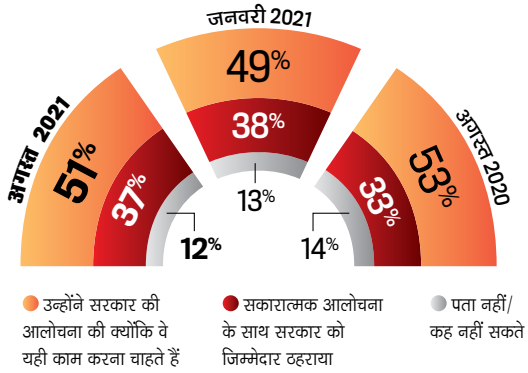

प्र. क्या आपको लगता है कि केंद्र में मोदी की अगुआई वाली भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी गठबंधन संभव है?

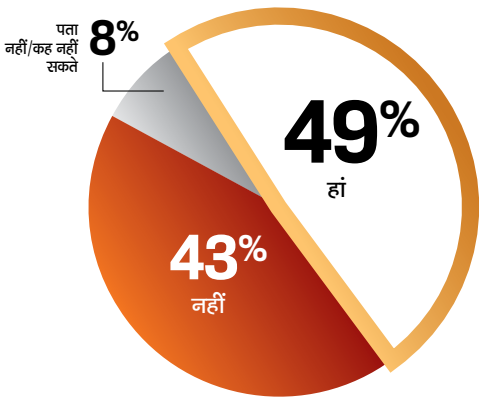

प्र. गैर कांग्रेसी-गैर भाजपाई नेताओं में से कौन विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है?

(आंकड़े %में; कोष्टक में दी गई संख्या देश का मिज़ाज सर्वेक्षण जनवरी 2021 की है)

कड़ा मुकाबला किया है. देश में मौजूदा मूड के साथ मुझे यकीन है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आने वाले चुनावों में भाजपा को हराने में सक्षम होंगे.''

कांग्रेस और उसके पहले परिवार के लिए बड़ी राहत की बात यह हो सकती है कि सर्वेक्षण में लोगों के एक बड़े हिस्से—46 फीसद, जो छह महीने पहले 35 फीसद था—का मानना है कि गांधी परिवार पार्टी के लिए अपरिहार्य है. यह बात निर्विवाद नेता के रूप में पार्टी के भीतर राहुल गांधी की स्थिति को मजबूत कर सकती है और वे अभी भी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेसी नेताओं में सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन हो सकता है कि वे विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सर्वसम्मत विकल्प न हों.

ममता बनर्जी की हाल की दिल्ली यात्रा उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की महीन दावेदारी थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अब तक राहुल की ओर से बुलाई गई विपक्षी बैठकों से दूर रहे हैं. देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में पाया गया था कि गठबंधन का नेतृत्व करने के लिहाज से केजरीवाल और ममता दोनों गैर-कांग्रेसी नेताओं में सबसे आगे हैं.

लेकिन कांग्रेसी नेता विपक्ष के बीच किसी तरह की प्रतिस्पर्धी राजनीति होने से इनकार करते हैं. कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह कहते हैं, ''कोई भी नेतृत्व के लिए लालायित नहीं है. इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है. इसलिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी सहित सभी नेता देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा के प्रयास में एक साथ हैं.'' ■

फिसलती जमीन पर भी टिके पांव

योगी आदित्यनाथ ने नंबर एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है; केजरीवाल और ममता उनके पीछे-पीछे हैं

अमरनाथ के. मेनन

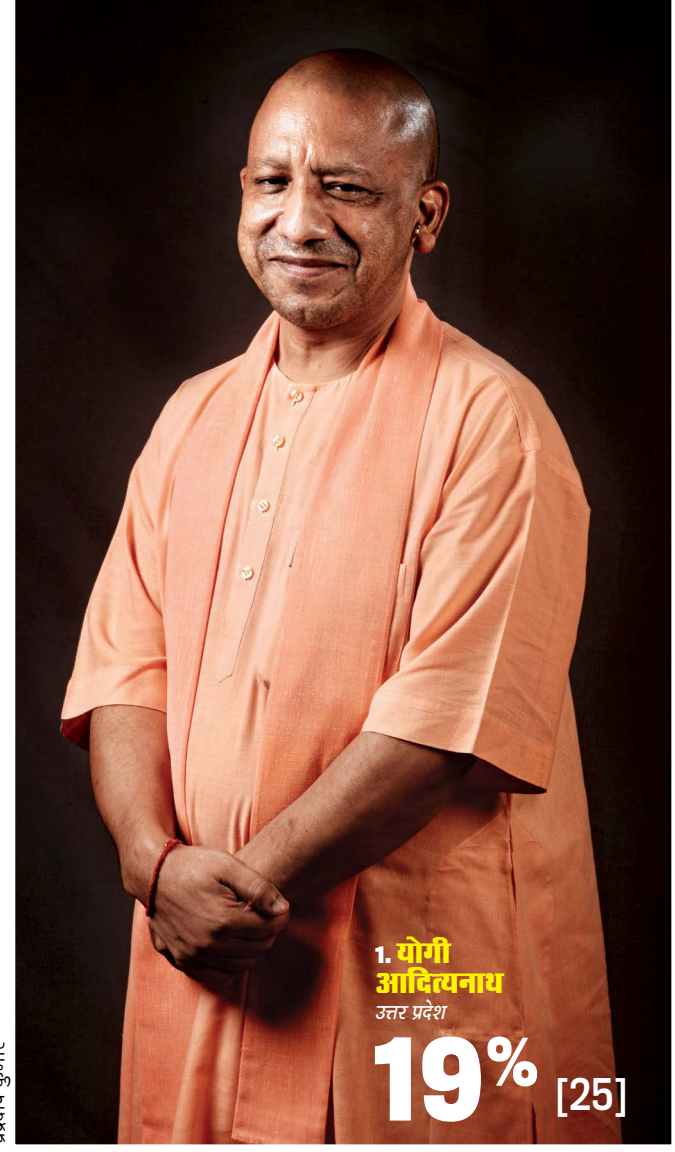

इंद्रदीप कुमार

को

ई मुख्यमंत्री लोगों की धारणा को जितना अधिक अपने पक्ष में कर लेता है, वह उतना ही लोकप्रिय होता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर इसकी मिसाल कहां मिलेगी, जिन्हें अगले छह महीने में विधानसभा चुनावों में उतरना है. अगस्त 2021 के देश का मिजाज सर्वेक्षण में वे एक बार फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं. हालांकि, उनकी लोकप्रियता में उल्लेखनीय गिरावट भी देखी गई है. जनवरी 2021 के सर्वेक्षण में उनकी लोकप्रियता 25 प्रतिशत अंक थी जो अब 19 प्रतिशत रह गई है.

फायरब्रांड नेता और काम करने वाले मुख्यमंत्री की अपनी छवि के साथ आदित्यनाथ कई मायनों में अपने पूर्ववर्तियों से अलग नजर आते हैं. जहां उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर उनका जोर रहा है वहीं राष्ट्रवाद तथा सूक्ष्मस्तर पर जाति प्रबंधन के मिश्रण के साथ उन्होंने एक नया सामाजिक

उम्दा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री

2. अरविंद केजरीवाल
दिल्ली
14% [14]

3. ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल
11% [8]

4. वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी
आंध्र प्रदेश
6% [6]

5. नीतीश कुमार
बिहार
5% [6]

6. उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र
5% [6]

7. नवीन पटनायक
ओडिशा
5% [5]

जनवरी 2021 के सर्वे के आंकड़े () में

उन्नीस राज्यों में लोगों से देश के 30 मुख्यमंत्रियों के कामकाज की रेटिंग करने को कहा गया था. यह रेटिंग उन्हीं की धारणा है. मसलन, जवाब देने वालों में से 19 फीसद ने योगी आदित्यनाथ को अव्वल मुख्यमंत्री माना

अंकगणित तैयार किया है. उनके मंत्रिमंडल के कुछ लोग आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खुद को भाजपा के 'मुख्यमंत्री चेहरे' के रूप में पेश किए जाने की मांग कर रहे थे. पर अब लगता है, आदित्यनाथ के लिए चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने का रास्ता साफ हो गया है.

देश का मिजाज सर्वे में शामिल लोगों ने देश के दूसरे और तीसरे अव्वल मुख्यमंत्रियों के रूप में अरविंद केजरीवाल (14 प्रतिशत) और ममता बनर्जी (11 प्रतिशत) को चुना है. केजरीवाल की लोकप्रियता में पिछले सर्वे की तुलना में कोई बदलाव नहीं आया है, वहीं ममता की लोकप्रियता में सुधार हुआ है. उनके बाद पहली बार के सीएम वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी (6 प्रतिशत) का नंबर आता है जिनकी लोकप्रियता में एक साल पहले के मुकाबले काफी गिरावट (अगस्त 2020 के देश का मिजाज सर्वे में उनकी लोकप्रियता 11 प्रतिशत थी) आई है. ऐसा आंध्र प्रदेश में उनके कई कल्याणकारी योजनाओं और खैरात वाले उपायों की घोषणाओं के बावजूद हुआ है. हर राज्य के उत्तरदाताओं के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के आकलन में रेड्डी टॉप 10 में शामिल नहीं हैं.

हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 7 मई को ही कुर्सी संभाली है, फिर भी वे अपने-अपने गृह राज्यों के सबसे लोकप्रिय सीएम का चयन वाली सूची में सबसे ऊपर हैं. उनकी सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है. मक्कलाई थेडी मारुथुवम कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को लोगों के द्वार पर उपलब्ध कराना है, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए द्रमुक सरकार के सात सूत्री दृष्टिकोण का हिस्सा है. इस योजना में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों और अन्य विकलांगों का चेक-अप, घर-घर जाकर होगा. एकीकृत जन शिकायत निवारण मंच उंगल थोगुधियिल मुथलमैचर, मुख्यमंत्री की एक अन्य पहल है. चावल राशन कार्ड धारकों को 4,000 रु. की कोविड-19 नकद राहत कुर्सी संभालने के दिन स्टालिन की घोषित योजनाओं में से एक थी.

देश का मिजाज सर्वे के अनुसार, मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन करते समय लोगों के लिए महामारी से निबटने को किया गया काम एक प्रमुख बेंचमार्क था. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की मिशन शक्ति एक बड़ी पहल साबित हुई है, जिसमें 70 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है. पटनायक उन्हें राज्य के आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति मानते हैं. उन्होंने उन समूहों को अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र चलाने, फेस मास्क की सिलाई करने और कोविड पर जन जागरूकता फैलाने के लिए वित्तीय अनुदान दिया है.

जन-केंद्रित विकास कार्यक्रमों और लोकलुभावन योजनाओं की भी मुख्यमंत्रियों की छवि गढ़ने में प्रमुख भूमिका रहती है. सर्वे से पता चलता है कि पिनाराई विजयन (केरल), उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र) और ममता बनर्जी का उनके अपने राज्यों में कम से कम 30 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया है. जबकि एक प्रमुख योजना से बहुत बड़ी संख्या में नए समर्थक बनते हैं, फिर भी किसी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में अच्छा-खासा इजाफा तो उन कल्याणकारी उपायों से होता है जो वंचितों की स्थिति में, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुधार लाते हैं. जो नेता ऐसा कर पाता है, मतदाता उसे सिर पर बिठाते हैं. ■

बंदीप सिंह

अपने गृह राज्य में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री

1. एम.के. स्टालिन
तमिलनाडु
42%

बंदीप सिंह

2. नवीन पटनायक
ओडिशा
38%

3. पिनाराई विजयन
केरल
35%

4. उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र
31%

5. ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल
30%

6. हेमंत बिस्वा सरमा
असम
29%

7. योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश
29%

8. अशोक गहलोत
राजस्थान
22%

9. अरविंद केजरीवाल
दिल्ली
22%

10. हेमंत सोरेन
झारखंड
19%

11. भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़
19%

सर्वे में शामिल सभी राज्यों के लोगों से उनके अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामकाज की रेटिंग करने को कहा गया था. यह रेटिंग उन्हीं की राय है. मसलन, तमिलनाडु के जवाब देने वालों में से 42 फीसद ने और ओडिशा के जवाब देने वालों में से 38 फीसदी ने क्रमशः एम.के. स्टालिन और नवीन पटनायक को अव्वल मुख्यमंत्री माना

मनीष अग्निहोत्री

सांस का सवाल
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लखनऊ में एक मेडिकल ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर के बाहर का दृश्य

सरकार से भरोसा उठा

महामारी की जानलेवा दूसरी लहर के भयावह कहर के लिए लोगों ने केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया

सोनाली आचार्जी

कोविड -19 की दूसरी लहर भारत में जंगल की आग की तरह फैली. 25 मार्च को देश में 59,000 नए संक्रमण दर्ज किए गए. दस दिन बाद दुनिया में हर छह नए संक्रमण में से एक हमारे देश में हो रहा था. 5 मई और भी बुरी खबर लेकर आया, जब भारत एक दिन में 4,00,000 से अधिक नए संक्रमण का आंकड़ा छूने वाला पहला देश बन गया. हालांकि उसके बाद मामले घटने लगे थे, लेकिन 1 जून तक देश में दूसरी लहर के दौरान कुल 1.6 करोड़ पुष्ट मामले हो गए थे. इसके विपरीत 13 महीने पहली लहर के दौरान कुल 1.1 करोड़ मामले ही थे.

इन चौंकाने वाले आंकड़ों से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, ताकि इस तरह के अभूतपूर्व संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उस जानकारी का उपयोग किया जा सके. सबसे अहम यह था कि दूसरी लहर किन वजहों से विकराल हो गई. भारतीय मेडिकल रिसर्च काउंसिल (आइसीएमआर) के जुलाई के अध्ययन में कहा गया है कि वायरस के डेल्टा स्ट्रेन के चलते दूसरी लहर में संक्रमण के शिकार लोगों की तादाद 80 फीसद थी. इसमें टीकाकरण के बावजूद लोगों को संक्रमण लगा. लेकिन *इंडिया टुडे* देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण में शामिल लोगों का मानना है कि इसके लिए दूसरी वजहें अधिक जिम्मेदार थीं.

सर्वेक्षण में 12 फीसद लोगों ने कहा कि वायरस के नए स्ट्रेन्स से दूसरी लहर आई, जबकि 27 फीसद के मुताबिक, बड़े धार्मिक आयोजन और भारी-भरकम चुनावी रैलियां इसके लिए जिम्मेदार थीं. 26 फीसद लोगों का मानना था कि कोविड रोकथाम के लिए जरूरी आचरण में लोगों की भारी लापरवाही दूसरी लहर का कारण बनी. 32 फीसद के मुताबिक, इन तीनों वजहों से दूसरी लहर भयावह हुई.

दरअसल यह मानने की पर्याप्त वजहें हैं कि अप्रैल-मई में संक्रमण में उछाल सिर्फ कोविड के नए स्ट्रेन से नहीं हुआ था. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मई में 25 शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि सिर्फ 50 फीसद ही मास्क पहन रहे थे, और बदतर यह कि सिर्फ 14 फीसद ही सही तरीके से मास्क पहन रहे थे. शोध और अनुसंधानों में पक्का पता चला है कि मास्क डेल्टा स्ट्रेन सहित कोविड के संक्रमण के प्रसार को 70-90 प्रतिशत तक कम कर देते हैं. इस तरह भले देश में नया स्ट्रेन मौजूद था, लेकिन शारीरिक दूरी का पूरी तरह ख्याल न रखने और मास्क न पहनने से दूसरी लहर तेजी से फैली.

दूसरी लहर का असर पिछले साल की पहली लहर के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक था. बड़ी संख्या में कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की बेइंतहा जरूरत पड़ी तो देश की स्वास्थ्य प्रणाली बुरी तरह हांफने लगी. मसलन, 20 अप्रैल को दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने घोषणा की कि उनके यहां 24 घंटे से भी कम समय के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति है, जिससे बहुत सारे रोगियों की जान पर खतरा मंडराने लगा. नौ दिन बाद भी स्थिति नहीं सुधर पाई थी, जब राष्ट्रीय राजधानी के एक अस्पताल ने खतरे की घंटी बजा दी कि उसके पास मुश्किल से कुछ घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है.

20 अप्रैल को पुणे के बाद बेंगलूरू में संक्रमण के 1,00,000

प्र. कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक दुश्वारियों से निबटने में केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा?

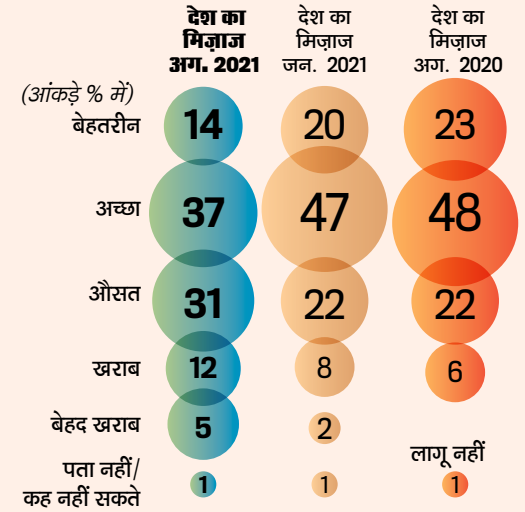

प्र. देश में कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप किन वजहों से हुआ?

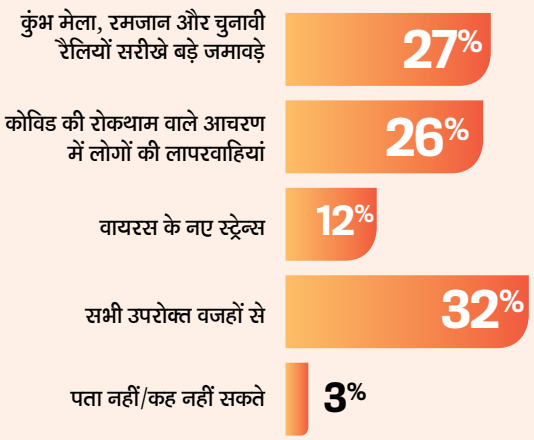

सक्रिय मामलों को पार करने वाला दूसरा शहर बन गया. देश भर के श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में शवों के अंबार लगने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो लोगों का विश्वास हिल गया. देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में 55 फीसद लोगों ने माना कि उनके राज्य की सरकार का महामारी से निपटने में कामकाज बेहतरीन/अच्छा था, लेकिन यह जनवरी 2021 के देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में 70 फीसद के आंकड़े से काफी कम था.

प्र. क्या कोविड-19 से केंद्र सरकार के आंकड़ों से ज्यादा लोग संक्रमण और मौत के शिकार हुए ?

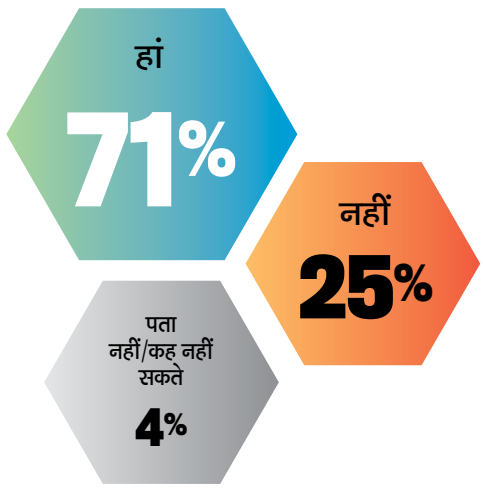

प्र. कोविड-19 ने आपकी माली हालत पर कैसा असर डाला?

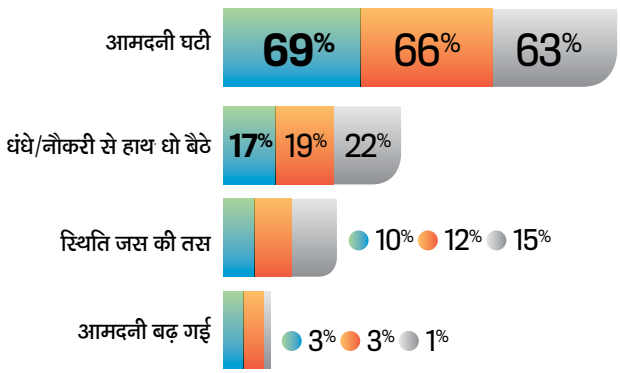

दूसरी लहर के दौरान कुछ राज्यों का कामकाज जरूर बेहतर रहा. मसलन, असम में 2 मई को संक्रमण पॉजिटिव दर 10 फीसद थी (डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 5 फीसद से कम होनी वाहिए), जो जुलाई में घटकर 1.5 फीसद पर आ गई. इसके लिए सरकार ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, उनकी टेस्टिंग, सख्त क्वारंटीन और सामुदायिक भागीदारी जैसे उपायों पर बेहतर ढंग से अमल किया. उस देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में महामारी से निपटने में दूसरा सबसे अच्छे राज्य (72 फीसद संतुष्ट लोगों)का रैंक प्रदान किया, जबकि थोड़े से अंतर से ओडिशा (73 फीसद) को शीर्ष स्थान हासिल हुआ. ओडिशा में दूसरी लहर के दौरान संक्रमण उछाल सबसे कम दर्ज की गई.

इस मामले में तमिलनाडु को चौथा स्थान हासिल हुआ, जहां 62 फीसदी लोग कोविड से निपटने में सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे, जबकि जनवरी 2021 के सर्वेक्षण में सिर्फ 43 फीसद लोगों ने ऐसी राय जाहिर की थी. दरअसल, चैन्ने में संक्रमण कुल मामलों में सिर्फ तीन हफ्ते में 70 फीसद तक कमी आ गई. वहां 12 मई को 7,564 मामले थे, जो 2 जून को 2,217 रह गए. शहर को यह कामयाबी राज्य सरकार के उपायों से हासिल हुई, जिसने संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों की पहचान, उनकी टेस्टिंग और इलाज पर फोकस के लिए समर्पित कोविड वॉर रूम की स्थापना की थी.

दूसरी लहर के दौरान लोगों की तकलीफों के लिए सर्वेक्षण में 44 फीसद लोगों ने केंद्र और राज्यों, दोनों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन 13 फीसद ने तो पूरी तरह केंद्र सरकार को और 10 फीसद राज्य सरकारों को सीधे दोषी ठहराया. तैयारी के लिए एक साल से अधिक का समय मिलने के बावजूद न तो केंद्र और न ही राज्यों ने पर्याप्त बस्तर क्षमता और ऑक्सीजन की आपूर्ति या बेहतर ट्रैकिंग और टेस्टिंग की व्यवस्था की, जिससे दूसरी लहर की तीव्रता को कम करने में मदद हो सकती थी.

दूसरी लहर का रोजी-रोजगार पर भी उतना ही बुरा असर पड़ा. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के अनुसार, एक करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी चली गई और देश में लगभग 97 फीसद परिवारों को आमदनी घट गई. देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में भी ऐसी ही निराशाजनक तस्वीर उभरती है, जिसमें 69 फीसद लोगों ने आमदनी काफी घटने (अगस्त 2020 के सर्वेक्षण के बाद से सबसे अधिक) की बात बताई और 17 फीसद ने कहा कि उनका कारोबार में भारी नुक्सान हुआ या नौकरी चली गई. (देखें, *बढ़ी दुश्वारियां*).

बड़ी संख्या में लोगों ने कोविड के सरकारी डेटा पर संदेह जताया. 71 फीसद का मानना था कि सरकार ने संक्रमण के मामलों और मौतों की संख्या को कम करके बताया. आइसीएमआर के ताजा राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के जुलाई में जारी आंकड़ों के मुताबिक, 11 राज्यों में सीरो-पॉजिटिविटी दर 75 फीसद से अधिक दर्ज हुई. मध्य प्रदेश 79 फीसद सीरो-पॉजिटिविटी दर के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद राजस्थान (76 फीसद) और बिहार (75 फीसद) का स्थान है. इसका कोविड संक्रमणों की सरकारी आंकड़ों के साथ कोई तालमेल नहीं है.

कोविड की पहली लहर ने देश को झकझोर दिया था, मगर दूसरी लहर तो स्थायी घाव दे गई. बुनियादी इलाज आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवा के चरमराने की लाचारी के साथ आर्थिक कठिनाइयां और जानमाल का नुक्सान लंबे समय तक लोगों को सालता रहेगा. भले ही आधे से अधिक लोगों ने कोविड से निपटने में सरकार के कामकाज के प्रति संतोष व्यक्त किया, लेकिन पिछले एक साल में ऐसे संतुष्ट लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है. जाहिर है, यह चिंता संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अधिक सरकारी जवाबदेही और तैयारियों की मांग करती है. ■

मनी शर्मा/गेट्टी इमेजेज

बदलाव की मांग
नई दिल्ली में नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (22 जुलाई, 2021)

सहमति और असहमति

बहुत-से लोग समान नागरिक संहिता, दो बच्चों की नीति, कृषि कानूनों में संशोधन और सोशल मीडिया पर नियंत्रण के पक्ष में, मगर कई दूसरे विरोध प्रदर्शन से आशंकित और इस पर राय बंटी कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं

अमरनाथ के. मेनन

प्र. देश में लोकतंत्र के मौजूदा हालात पर आप क्या सोचते हैं?

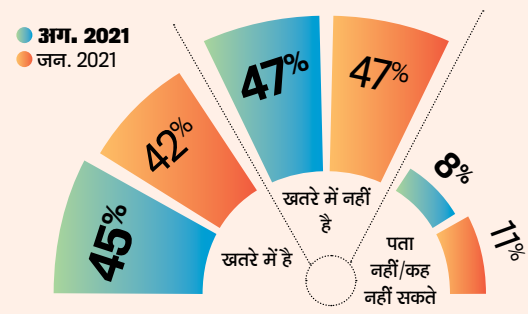

अपने अधिकारों, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर देश के लोगों में चिंताएं पहले की तुलना में आज कहीं अधिक गहरी हो गई हैं. देश में लोकतंत्र को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं. नवीनतम देश का मिज़ाज जनमत सर्वेक्षण में इसके संकेत मिलते हैं. सर्वेक्षण में शामिल 45 फीसद लोगों का मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है. इस धारणा में जनवरी 2021 के सर्वेक्षण के बाद से 3 फीसद अंकों की बढ़ोतरी हुई है. सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक (51 प्रतिशत) लोगों को लगता है कि लोग सार्वजनिक रूप से विरोध करने या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त करने से डरते हैं, जो निश्चित रूप से परेशान करने वाला रुझान है.

सर्वेक्षण में 41 फीसद लोगों की राय है कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर देना चाहिए. इसी तरह 57 फीसद लोगों का मानना है कि केंद्र को नए केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन करके किसानों के विरोध को खत्म करवाना चाहिए.

ऐसा मानने वालों में 12 फीसद अंकों की बढ़ोतरी हुई है कि मौजूदा एनडीए सरकार के राज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ गया है. जनवरी 2021 के सर्वेक्षण में उनकी संख्या 22 फीसद थी जो अब बढ़कर 34 फीसद हो गई है. बदतर तो यह है कि दक्षिण भारत में 48 फीसद और गैर-हिंदू लोगों में 45 फीसद का मानना है कि सांप्रदायिक सद्भाव की

प्र. जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए?

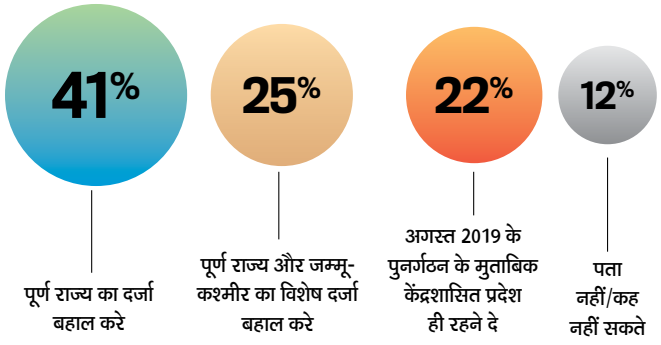

प्र. नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार को क्या करना चाहिए?

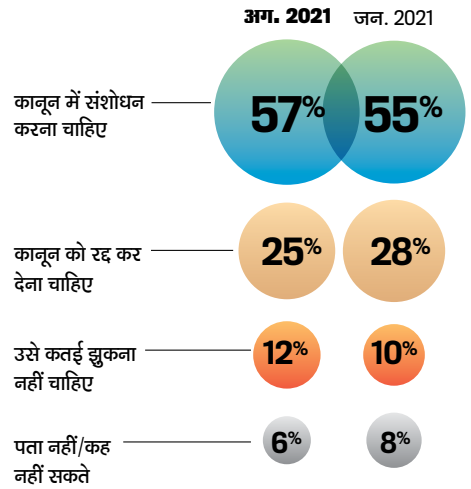

प्र. क्या आपको लगता है कि दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को नौकरियों, सरकारी योजनाओं के लाभ और चुनाव लड़ने से वंचित कर देना चाहिए?

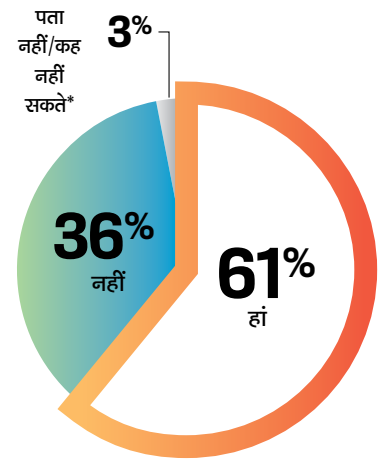

देश का मिज़ाज सर्वेक्षण में गैर-हिंदू लोगों में 51 फीसद ने दो बच्चे की नीति का विरोध किया

प्र. देश में सार्वजनिक 'विरोध प्रदर्शन के अधिकार' पर आपकी राय क्या है

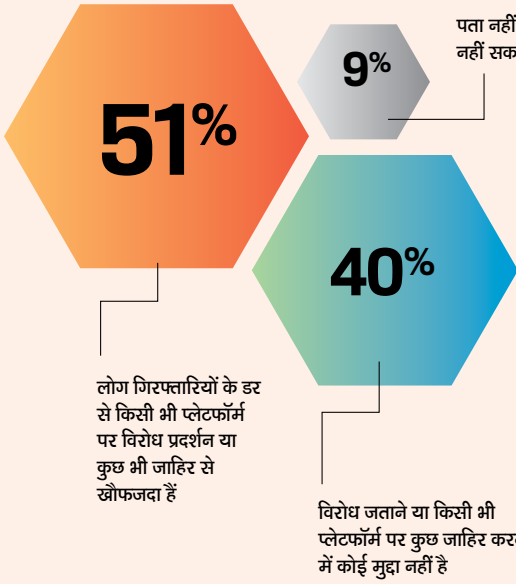

प्र. क्या केंद्र सरकार को महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहिए?

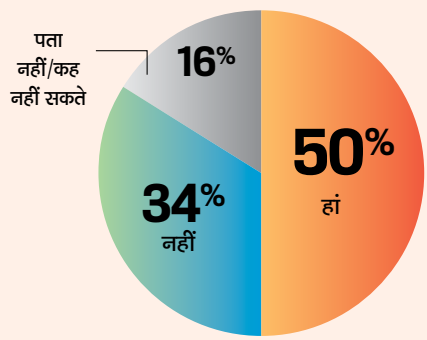

प्र. देश में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में आपकी राय क्या है?

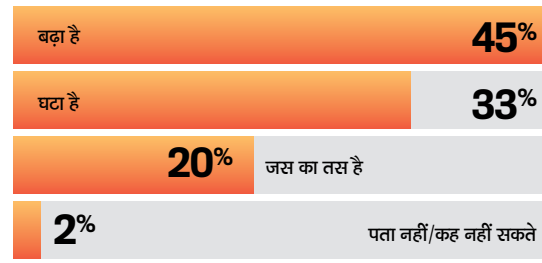

प्र. क्या देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए?

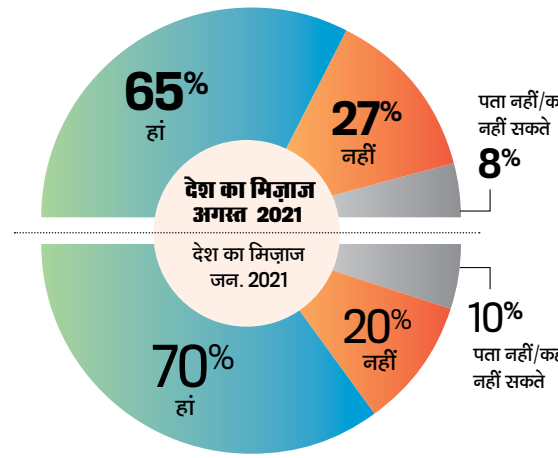

स्थिति बदतर होती जा रही है. जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, केवल 38 फीसद लोगों को ही लगता है कि देश, में महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल बन गया है; खासकर दक्षिण में तो 52 फीसद लोगों को शिद्दत से महसूस होता है कि महिलाएं पहले की तुलना में आज अधिक जोखिम में हैं. सार्वजनिक जगहों पर भी उन पर खतरे बढ़े हैं और दलित तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं.

सर्वेक्षण में अधिकांश लोगों ने दो विवादास्पद सुधारों का समर्थन किया. 65 फीसद लोग समान नागरिक संहिता बनाए जाने के पक्ष हैं और 61 प्रतिशत दो बच्चों के नियम वाली जनसंख्या नीति के हिमायती हैं. जाहिर है, इससे एनडीए सरकार के कान में कुछ मिठास घुलेगी.

लेकिन बड़े सवाल भी क्षितिज पर मंडरा रहे हैं, जिस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए. इसमें दो राय नहीं कि देश के सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में उथल-पुथल के स्पष्ट संकेत हैं और समाज को ज्यादा समावेशी बनाने के उपायों का घोर अभाव दिखता है. इस भावना ने एनडीए सरकार के प्रति अविश्वास को बढ़ाया ही है. लिहाजा, इस पर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए. ■

बातचीत का दौर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च, 2021 को क्वाड्रिलेटरल लीडर्स समिट में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद में

यासिर इकबाल

माहौल तो सही मगर...

चीन-पाकिस्तान की बढ़ती सांठगांठ भारत की विदेश नीति के लिए बनी सबसे बड़ी चुनौती. देश का मिज़ाज सर्वे में लोग इस मुद्दे पर सरकार के सख्त रवैए के साथ

संदीप उन्नीथन

साल 2020 में भारत की विदेशी नीति में तेजी से कुछ बुनियादी बदलाव आए. यूं कहें कि नई दिल्ली की विदेश नीति की दो सबसे बड़ी चुनौतियों ने अपने पाले बदल लिए. मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में बगैर किसी उकसावे के सीमा पर अतिक्रमण करके चीन इधर हाल के वर्षों में पहली बार खतरा बनकर उभरा, जबकि आर्थिक दुश्वारियों और सियासी उथल-पुथल से अपने में ही उलझा पाकिस्तान चुनौती के लिहाज से कमजोर पड़ता दिखा. मगर बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच करीबी राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य रिश्तों ने दोनों के मिले-जुले मोर्चे की संभावना को भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द बना दिया.

चीन की चुनौती और षड्यंत्रकारी पड़ोसियों से सटी दो सरहदों के सुलगने की आशंका के चलते भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चारपक्षीय सुरक्षा संवाद या क्वाड में ज्यादा उत्साह से शामिल हुआ. भारत को उम्मीद है कि क्वाड का सामूहिक वजन उस भूराजनीतिक

प्र. सीमा पर चीन की घुसपैठ से अभी तक केंद्र सरकार किस ढंग से निबटी है?

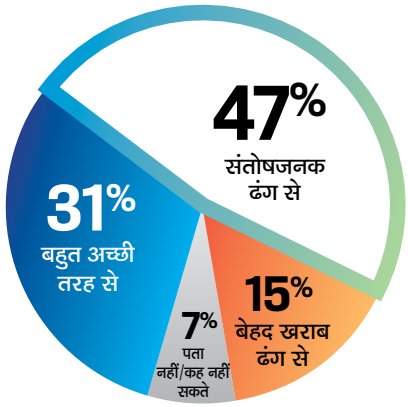

प्र. क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भारत के शुभचिंतक हैं?

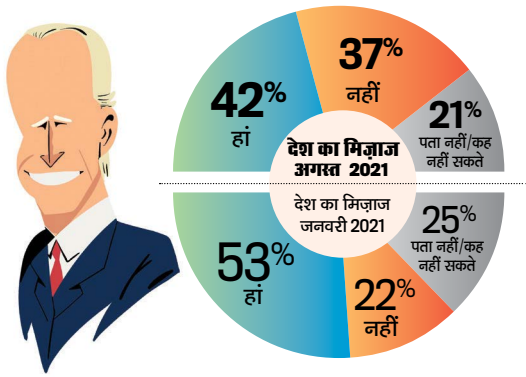

प्र. पाकिस्तान से भारत को किस ढंग से निबटना चाहिए?

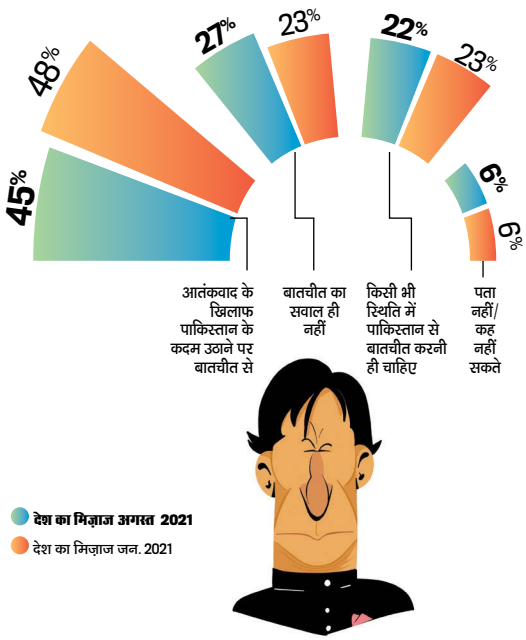

असंतुलन को दुरुस्त करेगा, जिसका सामना वह चीन से सटी विशाल पहाड़ी सरहद पर कर रहा है. सीमाई इलाकों में सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने का वक्त भी भारत को मिल जाएगा.

वाशिंगटन दूसरी ओर नई दिल्ली का सबसे अहम सुरक्षा भागीदार और सैन्य साजो-सामान का एक सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना ही हुआ है. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि देश का मिज़ाज सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की रेटिंग बीते आठ महीनों में करीब 10 फीसद अंक गिरी है. जनवरी में 53 फीसद लोग मानते थे कि बाइडन भारत के लिए अच्छे हैं. इस महीने महज 42 फीसद लोग ऐसा मानते हैं. यह इसलिए भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडन अभी तक आमने-सामने नहीं मिले हैं और न ही कोई अहम ऐलान किया है.

यह सब भी उस स्थिति में है जब बीजिंग के साथ सीमा बातचीत के नतीजे धीमे और नाकाफी हैं. मई 2020 में भारतीय और चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पांच ठिकानों पर बिल्कुल आमने-सामने थे, जिसके चलते 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ जानें गईं. नौ महीनों के गतिरोध के बाद दोनों पक्ष फरवरी 2021 में पैंगांग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हटे. 31 जुलाई को कमांडर स्तर की बातचीत के 12वें दौर के बाद दोनों सेनाएं 5 अगस्त तक गोगरा चौकी से भी पीछे हट गईं. अब वे बस एक जगह आमने-सामने हैं—पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में. एक और मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है और वह यह कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना को अक्साइ चिन से सटे देपसांग के बड़े मैदानी हिस्से में गश्त करने से रोक रही है.

देश का मिज़ाज सर्वे में 78 फीसद लोगों को लगता है कि चीन की सरहदी घुसपैठ से सरकार बहुत अच्छी तरह या संतोषजनक ढंग से निबटी. जनवरी में इससे कम 59 फीसद ने कहा था कि भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया.

सैन्य विश्लेषक इन वापसियों को तीन 'डी' का हिस्सा मानते हैं. 'डिसएंगेजमेंट' यानी टकराव की मुख्य जगहों से पीछे हटना; 'डीएस्केलेशन' यानी इलाके में सैनिकों की तादाद कम करना; और तीन, 'डीमिलिटराइजेशन' यानी उन्हें युद्धक्षेत्र से वापस बुलाकर पूर्वी लद्दाख में मई 2020 की स्थिति बहाल करना. दोनों पक्ष टुकड़ियों, टैंकों और पैदल सेना को हटाएंगे या नहीं, इसका निर्णायक सबूत आखिरी चरण होगा. चीन की मई 2020 की घुसपैठ से बीजिंग के साथ नई दिल्ली के रिश्तों पर संदेह के बादल घिर आए. चीन का कहना है कि सब ठीक-ठाक है. पर नई दिल्ली का कहना है कि ठीक-ठाक नहीं है.

अभी इसकी थाह ली जानी है कि इन घटनाओं का दोनों देशों के समग्र सीमा विवाद पर क्या असर पड़ा है. दोनों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 1990 के दशक से 3,448 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए चर्चाएं हुई हैं. दोनों देश अभी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भी सहमत नहीं हैं.

दुनिया भर में रसूख तेजी से गिरने और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर पूरा ध्यान होने के बावजूद पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में भाड़े के आतंकवादियों के मार्फत परेशानी पैदा करने में अब भी सक्षम है. भारत और पाकिस्तान के नेताओं को मिले छह साल हो गए. आखिरी बार मोदी और अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से 2015 में इस्लामाबाद में मिले थे. 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले और उसमें 40 सिपाहियों की मौत के बाद भारत ने भारतीय वायु सेना के विमानों से पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था. इस्लामाबाद के नजरिए से, अगस्त 2019 में भारत की तरफ से जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद रिश्ते रसातल में चले गए. भारत चाहता है कि संवाद दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान राज्य नीति के औजार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल बंद करे.

देश का मिज़ाज सर्वे में 45 फीसद लोग—जनवरी से तीन फीसद कम—पाकिस्तान के साथ तभी बातचीत के हक में हैं जब वह आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए. साफ है कि विदेश नीति पर लोगों की राय सरकार के लिए चिंता की बात नहीं है. ■

स्ट्रीमिंग का जलवा

महामारी के कारण बॉलीवुड के बड़े नाम अपना असर छोड़ने में नाकाम रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म और उनके सितारे लोकप्रियता में आगे बढ़े

सुहानी सिंह

फिल्मी सितारे आज उतने चमकदार नहीं दिखते जितने वे पहले हुआ करते थे. महामारी के कारण बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों के बंद होने या फिर 2021 की पहली छमाही में मात्र 50 प्रतिशत क्षमता पर चलने और ज्यादातर बड़ी फिल्मों की रिलीज रुकी होने के कारण फिल्मी सितारों को पर्दे पर आने के ही अवसर कम मिले, छा जाने की बात कौन कहे. इस साल, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार दोनों ने अपने-अपने शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा बरकरार रखा, लेकिन उनकी लोकप्रियता में क्रमश: पांच और छह प्रतिशत की गिरावट देखी गई. बच्चन-स्टारर फिल्में—*चेहरे* और *झुंड*—अभी भी रिलीज की राह देख रही हैं, इसी तरह अक्षय कुमार की *सूर्यवंशी* और *पृथ्वीराज* भी रिलीज नहीं हुईं. जिन सितारों की फिल्में रिलीज हुईं—मसलन, पिछले देश का मिज़ाज सर्वेक्षण के हीरो नंबर 1 सलमान खान जैसे स्टार जिनकी एक फिल्म *राधे* ज़ी 5 पर रिलीज हुई और यह दर्शकों का मनोरंजन करने के मामले में फुस्स साबित हुई—उनके प्रशंसकों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई है. इस सूची में एक नया नाम रजनीकांत का था, जिन्होंने फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां राजनीति को अलविदा कहने (स्वास्थ्य कारणों से) के अपने फैसले से बटोरीं.

जहां बॉलीवुड के अधिकांश अभिनेताओं के स्टारडम में कमी आई, वहीं नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण शीर्ष पर रहीं. हालांकि इस 35 वर्षीया अभिनेत्री की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और यहां तक कि कोविड से जूझने के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से विश्राम भी लिया था, लेकिन इससे उनकी रैंकिंग स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक दीपिका की कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, जिनमें वे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रभास और ह्रितिक रोशन के साथ नजर आएंगी. इस तथ्य ने पादुकोण को सूची में अव्वल नंबर पर बनाए रखा है. हालांकि यह बात कंगना रनौत के लिए नहीं कही जा सकती जो प्रियंका चोपड़ा जोनास

प्र. देश में नंबर 1 हीरो कौन है?

2. अक्षय कुमार
18% [24]

3. रजनीकांत
10% [लागू नहीं]

4. शाहरुख खान
9% [11]

5. सलमान खान
8% [7]

24%
अमिताभ बच्चन
[29%, जन. 2021]

बंदीप सिंह

प्र. देश में नंबर 1 हीरोइन कौन है?

17% दीपिका पादुकोण [17%, जन. 2021]

2. कैटरीना कैफ 11% [12]

3. प्रियंका चोपड़ा जोनास 10% [16]

4. कंगना रनौत 10% [15]

5. अनुष्का शर्मा 9% [10]

प्र. देश में ओटीटी का नंबर 1 पुरुष सितारा कौन है?

20% अभिषेक बच्चन [8%, जन. 2021]

2. मनोज बाजपेयी 12% [5]

3. बॉबी दयोल 10% [14]

4. सैफ अली खान 10% [10]

5. नवाजुद्दीन सिद्दीकी 7% [11]

बंदीप सिंह

प्र. देश में ओटीटी की नंबर 1 महिला स्टार कौन है?

2. जाह्नवी कपूर 13% [12]

3. भूमि पेडनेकर 8% [10]

4. राधिका आप्टे 7% [6]

5. शेफाली शाह 6%[7]

कोष्टक [ ] में दिए आंकड़े देश का मिज़ाज सर्वे जनवरी 2021 के हैं

21% सुष्मिता सेन [23%, जन. 2021]

प्र. क्या आपको लगता है कि ओटीटी की सामग्री को सेंसर करने की जरूरत है?

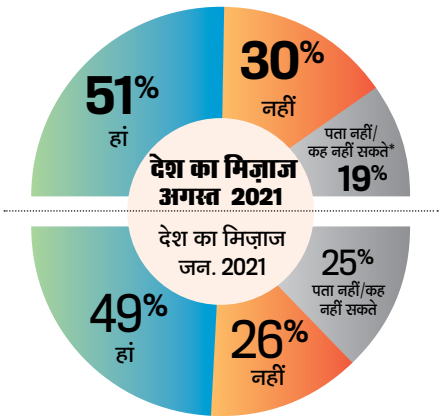

के साथ नंबर 4 स्थान पर हैं. रैंकिंग में प्रियंका की गिरावट की वजह उनके बॉलीवुड की जगह अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने को माना जा सकता है.

बॉक्स ऑफिस स्टार्स के दर्शकों को धीरे-धीरे वे अभिनेता छीनते जा रहे हैं जो ओटीटी की बढ़ती ताकत और प्रभाव को भांप चुके हैं. अगर बिग बी फिल्मों के हीरो की सूची में शीर्ष पर हैं तो अभिषेक बच्चन स्ट्रीमिंग श्रेणी में नंबर 1 पर थे. अमेजन प्राइम के शो *ब्रीद* के दूसरे सीजन और डिज्नी+हॉटस्टार फिल्म *द बिग बुल* के साथ वे सर्वे में शामिल उत्तरदाताओं की पहली पसंद हैं. दूसरे नंबर पर मनोज बाजपेयी रहे, जिनकी अमेजन प्राइम के हिट शो *द फैमिली मैन* में अपनी भूमिका के लिए खूब सराहना हो रही है. स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में भी एक खान ने दबदबा बनाए रखा है. अपने एक राजनैतिक ड्रामा सिरीज *तांडव* जो बहुत विवादों में भी रही, के साथ सैफ अली खान तीसरे स्थान पर हैं. ओटीटी श्रेणी की अभिनेत्रियों में, सुष्मिता सेन (*आर्या*), जाह्नवी कपूर, भूमि पेडनेकर, राधिका आप्टे (*ओके कंप्यूटर*) और शेफाली शाह (*दिल्ली क्राइम*) शीर्ष पांच पर रहीं.

यहां तक कि दर्शकों ने भी अपने मनोरंजन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सिरीज और फीचर्स की ओर रुख किया है, लेकिन स्ट्रीमिंग क्षेत्र के प्रोग्राम्स को लेकर मनोरंजन उद्योग के कान खड़े हैं क्योंकि यह क्षेत्र तेजी से और अक्सर मामूली दरों पर प्रोग्राम उपलब्ध कराता है. स्ट्रीमिंग क्षेत्र में सेंसरशिप की आवश्यकता है, इस राय में मामूली वृद्धि ही हुई है तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी है जो कंटेट में किसी तरह के छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं हैं. लेकिन ओटीटी प्रोग्रामिंग को लेकर सरकार अनिवार्य दिशानिर्देश पहले ही लागू कर चुकी है, अब दर्शक अपनी धारणा बनाने को स्वतंत्र हैं. ■

शशि एस. कश्यप/गेट्टी इमेजेज

महामहिम के खानदान से

नवीन कुमार

बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया बड़ी बेरहम है. पहुंच और रसूख के सहारे आप यहां कदम तो रख लें लेकिन गलाकाट स्पर्धा और जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म के बीच जगह बना पाना बहुत मुश्किल होता है. और रसूखदार पृष्ठभूमि का होने के बावजूद अगर आप उसे जाहिर न करना चाहें तो चुनौती और भी बढ़ जाती है. मुंबई में संघर्ष कर अपने पैर जमा रहे श्रेया नारायण और सोहराब खंडेलवाल से बेहतर यह बात भला कौन जानता होगा! श्रेया देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की पड़नातिन लगती हैं और सोहराब पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पड़नाती.

राजेंद्र बाबू एक-दो बार मुंबई फिल्म समारोह में शरीक हुए थे. वहीं पर बात-मुलाकात के दौरान फिल्मकार नाजिर हुसैन से उन्होंने भोजपुरी में फिल्म बनाने को कहा. हुसैन ने उन्हीं की प्रेरणा से पहली भोजपुरी फिल्म *गंगा मइया तोहे पियरी चढ़इबो* (1963) बनाई. राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के कुटुंब से श्रेया का रिश्ता है पर संयुक्त परिवार की वजह से राजेंद्र बाबू से भी संबंध जुड़ता है. श्रेया इस पर साफ कहती हैं, ''इस रिश्ते के बारे में मैं इंडस्ट्री में किसी से कुछ नहीं कह सकती थी. यहां आने का फैसला लेने पर परिवार ने साफ कह दिया था कि वे इसमें कोई मदद नहीं करेंगे. मैंने जो भी हासिल किया, खुद के बूते पर.''

बिहार में पली-पढ़ी श्रेया ने साहित्य और रंगमंच से जुड़ाव के कारण दिल्ली आकर एक्ट वन ग्रुप के साथ थिएटर करते हुए अभिनय कला को तराशा. फिर वे मुंबई आ गईं. *नॉकआउट, राजनीति, तनु वेड्स मनु, रॉक स्टार* सरीखी फिल्मों में उन्हें छोटे-छोटे रोल मिले. निरंग देसाई की आने वाली फिल्म *ताबीर* में भी वे रोशनी की भूमिका में हैं. कुछ विज्ञापनों में भी काम किया. लेकिन खुद पर भरोसे के चलते बार-बार ठुकराए जाने पर भी शुरू में वे घबराई नहीं. आखिर में अतुल सबरवाल ने यशराज फिल्म्स के बैनर पर, अपने निर्देशित टीवी सीरीज *पाउडर* (2010) में उन्हें जूली नाम के किरदार में लिया. श्रेया बताती हैं, ''उस सीरीज को देखकर ही मुकेश छाबड़ा समेत कई कास्टिंग डाइरेक्टर्स की मुझ पर नजर गई. छोटे-छोटे रोल मिले पर वे आगे बढ़ने में बहुत काम आए.'' तिग्मांशु धूलिया की *साहेब बीवी और गैंगस्टर* (2011) में वे महुआ के किरदार में थीं. बाद में धूलिया ने *यारा* में भी उन्हें लिया.

अपनी शुरुआती फिल्म *एक दस्तक* में उन्हें गाने का भी मौका मिला था. गुलाब गैंग (2014) में माधुरी दीक्षित पर फिल्माने के लिए *शर्म लाज मोह मार कर* गाना उन्होंने लिखा भी. महामारी के दौरान उन्होंने अफीम की खेती पर आधारित एक वेबसीरीज में एक गुंडी का रोल किया. श्रेया को छोटे रोल मिलने का कोई मलाल नहीं है. वे कहती हैं, ''मैंने अपना सपना खुद पूरा किया वर्ना परिवार का तो वही सपना था जो एक आम बिहारी परिवार के ख्वाम में होता है. ऐक्टिंग के साथ मैं अपनी मिट्टी से भी जुड़ी हुई हूं. बीच में मैंने बाढ़ पीड़ितों की भी मदद की.'' जीरादेई यानी राजेंद्र बाबू के गांव के लोगों की चाहत है कि वे राजनीति में आएं. ''इस पर मैं गंभीरता से सोच रही हूं.'' उनका जवाब साफ है.

इसी तरह से पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पड़नाती सोहराब भी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं. बॉलीवुड में पंजाबियों का बोलबाला रहा है, इस तथ्य से भी उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली. सोहराब के शब्दों में, ''इस इंडस्ट्री में इतनी जद्दोजहद है कि ज्ञानी जी से अपने रिश्ते की बात किसी से कहने का ख्याल मेरे जेहन में ही नहीं आया. अभी मेरी ही लिखी, बनाई, निर्देशित और अभिनीत फिल्म *के सेरा सेरा* रिलीज होने को है, उस सिलसिले में कहीं से लोगों को उनसे मेरे रिश्ते की बात पता चली. उनसे मेरा एक रिश्ता है, यह मेरी खुशकिस्मती है लेकिन इंडस्ट्री में अपने हिस्से की मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी. यहां किसी के नाम पर मुझे कोई मौका नहीं देने वाला.''

हां, परिवार से मदद के मामले में सोहराब श्रेया से थोड़ा बेहतर स्थिति में हैं. एयरफोर्स में सेवारत पिता और डॉक्टर मां ने बेटे का हौसला बढ़ाने के साथ मंजिल तक पहुंचने के लिए सहारा भी दिया. बकौल सोहराब, ''पुणे से इंफोसिस की कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर जब मैं मुंबई आया तो परिवार के लोग डर गए थे कि कैसे मैं जगह बना पाऊंगा. लेकिन मेरी लगन और मेहनत से उन्हें भरोसा हो गया.'' परिवार की मदद से ही उन्होंने के *सेरा सेरा* पूरी की जिसे पिछले दिनों लंदन के बाफ्टा क्वालिफाइंग कारमाथेन बे फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला. अब इसे ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज करने की तैयारी है. यह अंग्रजी फिल्म है लेकिन सोहराब का दावा है कि मामूली-सी अंग्रेजी जानने वाले भी इसे आसानी से समझ सकेंगे. चंडीगढ़ के और पढ़ाकू सोहराब ने नाटकों के अपने दोस्तों से अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए रंगमंच को अपनी प्रयोगशाला बनाया. फिर मुंबई आकर मशहूर पटकथा लेखक अंजुम रजब अली की वर्कशॉप ली. फिल्मकार आनंद महेंद्रू के सहायक भी बने. उन्हें अभिनेता विजयराज की यह सलाह भी काफी पसंद आई कि 'यहां मजे करो और जहां मौका मिले, ऐक्टिंग करो.' राजनीति से दूर, सत्यजीत रे से प्रभावित सोहराब अब महामारी को लेकर एक फिल्म पर काम कर रहे हैं.

पर सोहराब को सबसे पहले हॉकी खिलाड़ी *प्रिथीपाल सिंह* (2015) में अभिनय और सहायक निर्देशक का काम मिला था. इसके बाद उन्होंने *जग्गा जासूस, अनटचेबल्स, अकूरी, अपस्टार्स* और हाल ही आई सरदार का ग्रैंडसन में छोटे-छोटे रोल किए. लेकिन *के सेरा सेरा* के जरिए लीड रोल निभाने का उनका सपना भी पूरा हुआ. सोहराब को ''नेता नहीं अभिनेता बनना है.'' दोनों प्रतिभाओं की दृष्टि साफ है. ■

स्थापना मौलिक अवधारणाओं की

विजय पंडित

कहानी के रंगमंच के प्रणेता देवेंद्रराज अंकुर की किताब *रंगमंच की कहानी* रंगमंच के उद्भव से लेकर आधुनिक रंगमंच तक की यात्रा का एक विस्तृत कथा-वृत्तान्त है. अभी तक इस विषय को लेकर रंगकर्मियों, नाटककारों और शोधार्थियों को अंग्रेजी की किताबों पर ही आश्रित रहना पड़ता था. इतना ही नहीं देश के विभिन्न नाट्य संस्थानों में भी सिद्धांत, तकनीक और इतिहास के लिए बाहर की ही किताबें पढाई जाती रही हैं. यह किताब उस खालीपन को भरती है. विश्व के रंगमंच की कथा को अंकुर ने काफी श्रम और शोध करके लिखा है.

इस किताब में वे 'प्रागैतिहास का रंगमंच' के 'आदिम रंगमंच' से होते हुए पूर्व का रंगमंच, पश्चिम का रंगमंच और नेपथ्य की कहानी कहते हैं, जिसमें अभिनय, प्रेक्षागृह, मंच अभिकल्पक और दृश्यांकन से लेकर निर्देशन तक की यात्रा है. चार विशद भागों में विभक्त इस किताब में कुल उन्नीस शीर्षक हैं और हर शीर्षक नितांत तार्किक है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पाश्चात्य थिएटर की अवधारणाओं से कतई प्रभावित नहीं होते. इन सभी कहानियों में उन की अपनी अवधारणा है. विशेषकर जहां उन्हें लगता है कि भारतीय रंगमंच या इसके किसी भी पक्ष को विदेशी लेखकों और शोधकर्ताओं ने संज्ञान नहीं लिया है, वहां वे तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हैं.

पूर्व के रंगमंच में चीनी और जापानी रंगमंच के दो अध्याय हैं, वहीं भारतीय रंगमंच के चार अध्याय—भारतीय शास्त्रीय रंगमंच, लोक रंगमंच, पारसी रंगमंच और आधुनिक रंगमंच. इन सभी शीर्षकों को मिलाकर भारतीय रंगमंच की यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है. वहीं 'पश्चिम का रंगमंच' में—ग्रीक, रोमन, मध्यकालीन रंगमच, रिनेंसां कालीन (इतालवी), एलिजाबेथ कालीन, स्तानिस्लाव्स्की, ब्रेख्त और एब्सर्ड का रंगमंच है. एब्सर्डिटी या विसंगति के नाटकों का विश्लेषण करते हुए वे स्पष्ट कहते हैं कि हमारे यहां विसंगति फैशन के तौर पर आई. युद्ध की विभीषिका से हम सीधे प्रभावित नहीं थे, इसलिए हमारे नाटकों का कथ्य प्रभावशाली नहीं रहा. केवल हम फॉर्म अपना पाए और इस तरह से जैसे ही वह नाटक आया, वैसे ही चला भी गया. इस संदर्भ में वे बादल सरकार के 'तीसरा रंगमंच' का उदाहरण देते हैं कि किस तरह समय के साथ उसे लोग भूलते गए. भुवनेश्वर हिंदी एब्सर्ड नाटक के जन्मदाता या प्रथम प्रयोगकर्ता थे, इस धारणा को भी वे सिरे से नकारते हैं.

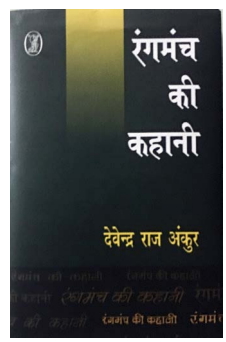

रंगमंच की कहानी
लेखकः देवेंद्र राज अंकुर
वाणी प्रकाशन,
दरियागंज, नयी दिल्ली
कीमतः 695 रुपए

अंकुर पाश्चात्य थिएटर की अवधारणाओं से कतई प्रभावित नहीं होते. जहां उन्हें लगता है कि भारतीय रंगमंच या उसके किसी पक्ष का विदेशी लेखकों ने संज्ञान नहीं लिया है, वहां वे तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हैं

कोई भी नाटक कैसे प्रासंगिक रहता है, उसके लिए वे ब्रेख्त का उदहारण देते हैं. वहीं ब्रेष्ट और ग्रोतोव्स्की को आमने-सामने रख कर वे स्पष्ट करते हैं कि ब्रेख्त की एपिक थिएटर की अवधारणा को हम प्राय: महाकाव्यात्मक शैली से जोड़ देते हैं, जबकि ब्रेख्त की सोच है कि उनके दर्शक घटनाओं को विश्लेषित भी करें और परिवर्तनों को लेकर उतने ही सक्रिय हों. स्तानिस्लाव्स्की की चरित्रपरक प्रस्तुति और ब्रेख्त की प्रस्तुतिपरक प्रस्तुति की चर्चा करते हुए वे साफ कहते हैं कि यह कोई नवीन अवधारण नहीं है. आज से ढाई हजार साल पहले भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में लोकधर्मी और नाट्यधर्मी इन दो शीर्षकों के अंतर्गत दोनों पद्धतियों का संकेत कर दिया था. वे एलिजाबेथकालीन थिएटर के योगदान और ग्लोब थिएटर, शेक्सपियर तथा रेनेसां थिएटर के कारण नए रंगमंचीय तत्वों के प्रयोग से लेकर गॉर्डन फ्रैग, जॉर्ज बर्नाड शॉ, लॉरेन्स ओलिवर और पीटर ब्रूक तक की रंगयात्रा को भी विस्तार से लिखते हैं, साथ ही मेयरहोल्ड, आर्तो और अगस्तोबोल के रंगमच को भी उद्घृत करते हैं. अंत में वे अभिनय, प्रेक्षागृह, सेट डिजाइन और निर्देशन की कहानी भी बताते हैं. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व रंगमंच की इस कथा यात्रा में भारतीय रंगमंच के योगदान को वे बखूबी स्थापित करते हैं.

पुस्तक की भाषा में लालित्य है, केवल सूचना की भाषा नहीं है. हर अध्याय एक निबंध है, ललित निबंध. वहीं पर अंग्रेजी शब्दों का टर्मिनोलॉजी और नाम के लिए बखूबी प्रयोग किया गया है जो कि भाषायी रूप से समृद्ध करती है. इसमें चित्र की कोई आवश्यकता नही थी और इस बात को लेखक ने स्पष्ट भी किया है. लेखन ही अपने आप में इतना सक्षम है कि संबंधित कथा का विजुअल पाठकों के सामने ला सके.

रंगमंच की कहानी रंगकर्म से जुड़े लोगों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ कहानी लेखकों के लिए भी जरूरी है क्योंकि हर कहानी में एक नाटक आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है. हां, यह एक दो-दिन में पढ़ डाली जाने वाली किताब नहीं है. तीन सौ सोलह पृष्ठ की इस किताब को आत्मसात करने के लिए समय देना होगा, क्योंकि यह कहानी के साथ एक शोध प्रबंध भी है. इस किताब का अन्य भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद अपेक्षित है, जिससे कि यह कहानी दूर-देश के लोग भी सुन-पढ़ सकें.

यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि देवेंद्र राज अंकुर जितना 'कहानी का रंगमंच' के लिए जाने जाते हैं, अब उतना ही वे 'रंगमंच की कहानी' के लिए भी जाने जाएंगे. ■

सवाल+जवाब

फिर झनके वीणा के तार

शास्त्रीय संगीतकार **पं. विश्वमोहन भट्ट** *मिमी* फिल्म में मोहन वीणा बजाने, रहमान और विशाल भारद्वाज के संगीत से जुड़े रहने और कोरोना संकट के एकांत पर

● *मिमी* के गीत *छोटी-सी चिरैया* में ए.आर. रहमान ने आपकी मोहन वीणा का खूब उपयोग किया. अरसे बाद आपका फिल्म संगीत से जुड़ना हुआ.

हां, ज्यादा तो नहीं पर जब भी फिल्म वाले बुलाते हैं तो करता हूं. कुछ संगीत निर्देशक हैं जो शास्त्रीय संगीत चाहते हैं. सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन लोग फिल्म बना रहे हैं, और उनका शास्त्रीय संगीत से कैसा लगाव है. हम शास्त्रीय संगीत वाले भी परहेज करते हैं क्योंकि वहां समझौते करने पड़ते हैं. हम चाहते हैं कि आप हम पर विश्वास करके पूरी स्वतंत्रता दें. *मिमी* का यह गीत राजस्थानी लोकसंगीत की एक पुरानी लोरी से प्रेरित है. फिल्मांकन भी राजस्थान में हुआ है.

● रहमान और विशाल भारद्वाज के साथ कई फिल्मों से आप जुड़े रहे हैं. रहमान के साथ दुअर भी किए.

रहमान और विशाल शास्त्रीय संगीत और उसके कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं. रहमान ने मुझसे एक मलयाली गीत में भी वादन कराया था. *इश्किया* में रेखा भारद्वाज का गाया गीत *बड़ी धीरे जली रैना* राग ललित पर आधारित था जिसमें मैंने मोहन वीणा बजाई थी.

● वैसे फिल्में आपको शुरू से ही पसंद रही हैं. सुना है कि आप युवावस्था में परिवारवालों को बिना बताए ही मुगल-ए-आजम देखने चले गए थे?

मेरे पिता बहुत सख्त थे. वे बहुत अनुशासन में हमारा पालन-पोषण कर रहे थे. उन्हें चिंता थी कि हम कहीं शास्त्रीय संगीत से भटक न जाएं. तो हम परिवारवालों को बिना बताए ही फिल्म देखने चले गए थे और हंगामा हो गया था.

● फिल्मों के संगीत से जुड़ना और उसमें मोहन वीणा वादन करना आपको कितनी संतुष्टि देता है?

यह एक अलग विधा है और बहुत मुश्किल भी है. शास्त्रीय संगीत में तो एक राग एक घंटे तक चलता है लेकिन यहां दो-तीन मिनट में आपको पूरा सार लाना पड़ता है.

● कोरोना काल ने मंचों के कार्यक्रम बंद कर दिए, कई कलाकार हमसे छीन लिए. इस दौरान आपने क्या किया?

आम दिनों में मैं महीने में 20-22 दिन बाहर ही रहता था लेकिन कोरोना काल में समय मिला तो मैंने गुरुओं को खूब सुना. आनलाइन कार्यक्रम और कार्यशालाएं कीं. मेरे मन में रोष नहीं था क्योंकि यह तो नियति है. मैंने इसका उपयोग किया. कई रचनाएं बनाईं. अभ्यास भी खूब हुआ.

—आलोक पराड़कर

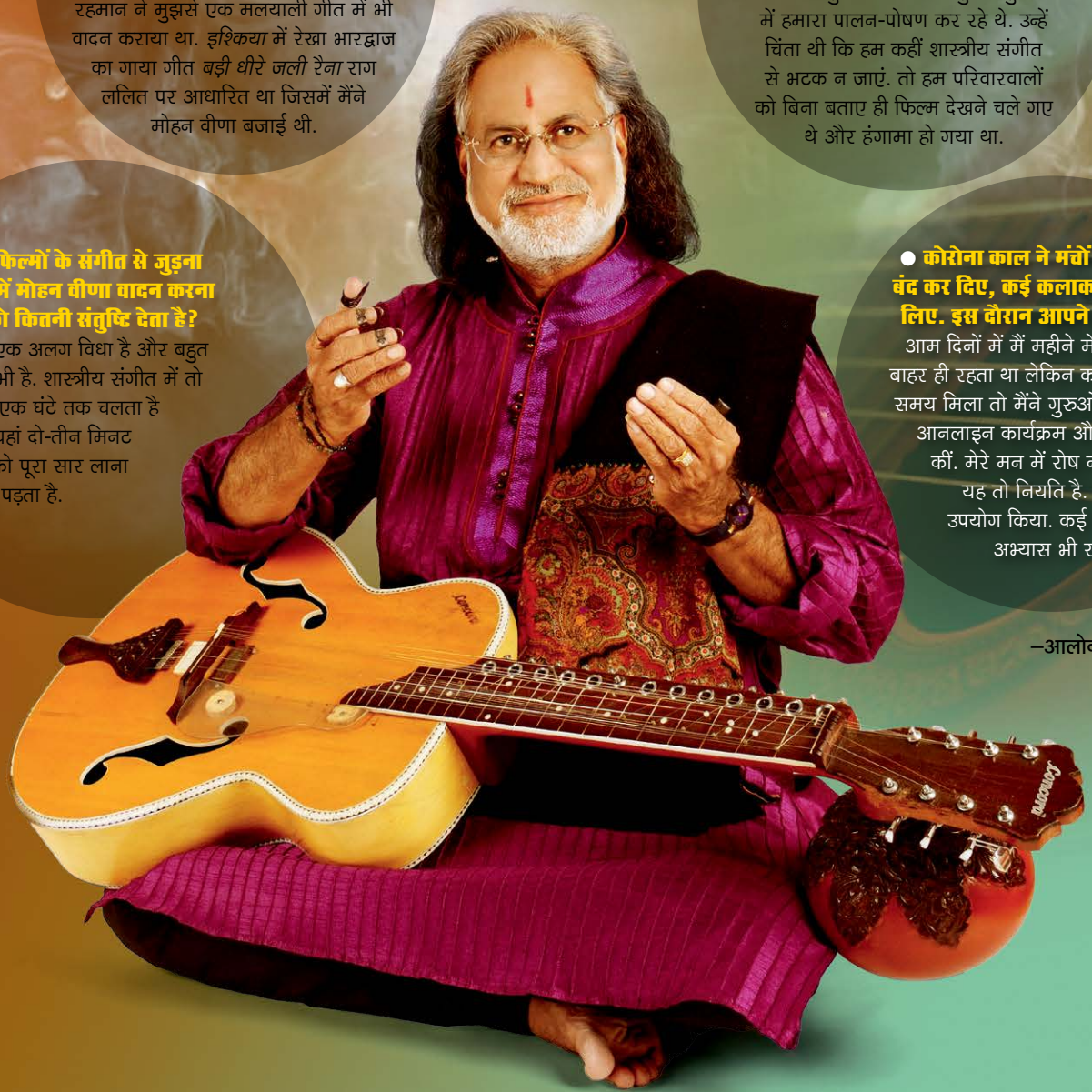

Sunfeast YiPPee! noodles

MOOD Masala

Enduring Value

MAIN MASALA FOR TASTE

+

MOOD MIX FOR YOUR MOOD

Match your mood with YiPPee! Mood Masala noodles, packed with 2 masala sachets!

Creative Visualization | Serving Suggestion

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE